सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2019–20



nidm

Resilient India - Disaster free India

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

nidm

Resilient India - Disaster free India

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

ए-विंग, चौथा तल, एनडीसीसी-II भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001

वेबसाइट : www.nidm.gov.in

वार्षिक रिपोर्ट एनआईडीएम 2019-20
© एनआईडीएम, नई दिल्ली

संपादक
मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल
वी एस एम
कार्यकारी निर्देशक, एनआईडीएम

प्रकाशन
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार),
नई दिल्ली-110001

nidm
Resilient India - Disaster free India

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

दृष्टिकोण

"भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक प्रमुख संस्थान बनना और क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी संस्थानों में से एक के रूप में पहचान स्थापित करना। सभी स्तरों पर निवारण और तैयारी की संस्कृति को विकसित करना और उसे बढ़ावा देकर आपदा मुक्त भारत बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना।"

विषय सूची

क्रम स.	विषय		पृष्ठ. स.
1.	**सिंहावलोकन**		1-6
	1.1	संस्थान के बारे में	3
	1.2	प्रबंधन संरचना	3
	1.3	परिकल्पना	3
	1.4	मिशन	4
	1.5	कार्य	4
	1.6	प्रमुख क्षेत्र	5
2.	**संगठनात्मक व्यवस्था**		7-14
	2.1	संगठनात्मक ढांचा	9
	2.2	सामान्य प्रशासन	13
	2.3	हिंदी का प्रगामी प्रयोग	14
3.	**प्रशिक्षण कार्यक्रम**		15-20
	3.1	उद्देश्य	17
	3.2	आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम	17
	3.3	प्रशिक्षण विधि	19
	3.4	प्रतिभागियों का विवरण	19
	3.5	ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	20
	3.6	स्व-अध्ययन कार्यक्रम	20
	3.7	इंटर्नशिप कार्यक्रम	20
4.	**परियोजनाएं**		21-38
	4.1	बहूजोखिम पर्यावरण में समुत्थाकनशीलता और सतत विकास के लिए जलवायु अनुकूली योजना (कैप-रस)	23
	4.2	स्वास्थ्य अनुकूलन और समुत्थातनशीलता : रणनीतिक ज्ञान और क्षमता को आगे बढ़ाना (हर-कैप)	24
	4.3	राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना (एनएडीएमपी)	26
	4.4	जलाशयों के संदूषण से निपटने के लिए संकट प्रबंधन योजना	27
	4.5	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूपनीकरण (सीसी-डीआरआर) इकाई, एनआईडीएम- दक्षिणी परिसर	28
	4.6	आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारत विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क (आईयूआईएन)	29
	4.7	जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर नीति दस्तावेज	30
	4.8	एनआईडीएम-जेएनयू-आपदा अनुसंधान कार्यक्रम (डीआरपी) आपदा अनुसंधान के लिए विशेष केंद्र (एससीडीआर) 2019-20 के लिए गतिविधियां	31
	4.9	आधारभूत संरचना (रोहिणी और दक्षिणी परिसर)	35
5.	**ज्ञान प्रबंधन और जागरूकता कार्यकलाप**		39-48
	5.1	भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)	41
	5.2	प्रलेखीकरण और प्रकाशन	42

	5.3	एनआईडीएम प्रशिक्षु डाटाबेस	43
	5.4	सूचना प्रसार	43
6.	**मुख्य आयोजन / कार्यशालाएं / सम्मेलन / सेमिनार और बैठकें**		49-78
	6.1	आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विश्वविद्यालय नेटवर्क पर परामर्श कार्यशाला	51
	6.2	आपदा प्रबंधन योजना पर प्रशिक्षण कार्यशाला	52
	6.3	बच्चों के लिए राष्ट्रीय आपदा तैयारी कार्यशाला	53
	6.4	कार्यकारी समूह की बैठक	53
	6.5	भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस) अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन कार्यक्रम	54
	6.6	राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना पर क्षेत्रीय परामर्शदात्री कार्यशाला	54
	6.7	जलवायु समुत्थानशीलता के लिए प्रकृति आधारित समाधान: भारतीय मैंग्रोव का भविष्य: विषय पर राष्ट्रीय परामर्शदात्री कार्यशाला	55
	6.8	एम.ए. और पीएचडी छात्रों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम / कार्यशाला : आपदा अनुसंधान के लिए विशेष केंद्र (एससीडीआर), एनआईडीएम-जेएनयू-डीआरपी	55
	6.9	आपदा जोखिम प्रबंधन पर कार्यशाला, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	56
	6.10	"एशिया-पैसिफिक डिजास्टर वल्नरेबिलिटी : द डिजास्टर रिस्कस्केप एंड पाथवेज फॉर रैजिलियैंस, इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट" विषय पर कार्यशाला	56
	6.11	चक्रवात फनी के प्रबंधन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला; सीखे गए सबक और आगे का रास्ता,	57
	6.12	मरुस्थलीकरण प्रतिरोध पर संयुक्त राष्ट्र समझौता, पार्टियों का सम्मेलन (सीओपी-14) विशेष आयोजन : भूमि-जल समुत्थानशीलता में सुधार के लिए सूखा जोखिम न्यूमनीकरण; ईको डी.आर.आर. के विकल्पो और उपकरणों को मुख्य धारा में लाना:	58
	6.13	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय और गेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 'आपदा प्रबंधन' विषय पर संयुक्त रुप से आयोजित कार्यशाला	59
	6.14	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की "राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना" के तहत 'एचआरव्हीसीए' कार्यशाला	60
	6.15	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रबोधन कार्यशाला	61
	6.16	आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) पर राष्ट्रीय कार्यशाला	62
	6.17	नेपाली प्रतिनिधिमंडल - समन्वय बैठक	63
	6.18	विकलांगता-समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए क्षमता निर्माण कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा, पर परामर्शदात्री बैठक: एनआईडीएम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा आयोजित	63
	6.19	स्वास्थ्य समुत्थाशनशीलता और क्षमता निर्माण पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला	64
	6.20	स्वास्थ्य समुत्थाशनशीलता और क्षमता निर्माण पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला	65

	6.21	पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की समन्वय बैठक	66
	6.22	आपदा जोखिम जागरूकता पर कार्यशाला	66
	6.23	आपदा जोखिम जागरूकता पर कार्यशाला	67
	6.24	स्वास्थ्य समुत्थानशीलता और क्षमता निर्माण पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला	68
	6.25	भारत में आपदा समुत्थानशील कृषि पर राष्ट्रीय हितधारक-परामर्श कार्यशाला	68
	6.26	'सूझबूझ और नवपरिवर्तन के माध्यम से जलवायु समुत्था नशीलता' विषय पर सेमिनार	69
	6.27	स्वास्थ्य समुत्थानशीलता और क्षमता निर्माण पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला	70
	6.28	"भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता" पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	71
	6.29	पशु समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण (एआईडीआरआर) के लिए क्षमता निर्माण पर परामर्श कार्यशाला	72
	6.30	सूखा समुत्थानशील कृषि पर इथियोपिया सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ पीयर एक्सचेंज राउंडटेबल	73
	6.31	विकलांगता-समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण : समावेश के मार्ग तथा समुत्थानशीलता हेतु कार्रवाई पर राष्ट्रीय सम्मेलन	74
	6.32	'आपदा जोखिम वित्तपोषण, बीमा तथा जोखिम अंतरण' पर राष्ट्रीय कार्यशाला	75
	6.33	तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता (सीडीआरआर एवं आर) पर राष्ट्रीय सम्मेलन	76
	6.34	आपदा प्रबंधन पर कॉनकॉर के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला	77
7.	**वित्त और लेखा**		79-98
	लेखा परीक्षित रिपोर्ट और बैलेंस शीट		81
8.	**अनुबंध**		99-111
	8.1 अनुबंध-I	: संस्थान के साधारण निकाय के सदस्यों की सूची	101
	8.2 अनुबंध-II	: संस्थान के शासी निकाय के सदस्यों की सूची	104
	8.3 अनुबंध-III	: एनआईडीएम द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची	105

लघुरूप और परिवर्णी शब्द

एडीपीसी	एशियाई आपदा तैयारी केन्द्र
एआईडीआरआर	पशु समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण
एआईआर	आकाशवाणी
एएमसीडीआरआर	आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन
एपीएचआरडीआई	आन्ध्र प्रदेश मानव संसाधन विकास संस्थान
एटीसी	वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन
एटीआई	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
सीएपी-आरईएस	समुत्थानशीलता तथा सतत् विकास के लिए जलवायु अनुकूलन योजना
सीबीडीआरआर	समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण केन्द्र
सीसीडीआरआर	शिशु केन्द्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण
सीसीआर	जलवायु परिवर्तन समुत्थानशीलता
सीडीपी	नगर विकास योजनायें
सीडीआरआर	तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण
सीईसीआर	जलवायु समुत्थानशीलता के लिए उत्कृष्टता केन्द्र
सीईएम	पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन आयोग
सीपीसीबी	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीआरई	जलवायु समुत्थानशीलता तथा पर्यावरण
सीआरआईए	शिशु जोखिम प्रभाव आकलन
सीआरएमडी	साइबर जोखिम प्रबन्धन प्रभाग
सीएसआईआर	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
डीडी	दूरदर्शन
डीईपीडब्लयूडी	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
डीआईडीआरआर	दिव्यांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण
डीएम	आपदा प्रबन्धन
डीआरएम	आपदा जोखिम प्रबन्धन
डीआरआर	आपदा जोखिम न्यूनीकरण
डीआरपी	आपदा अनुसंधान कार्यक्रम
डीआरआर और आर	आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता
डीआरआरडी	आपदा प्रतिक्रिया और रिकवरी प्रभाग
डीएसटी	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग

ईडीआरएम	पर्यावरणीय आपदा जोखिम प्रबन्धन
ईडब्लयूसी	पूर्वचेतावनी संचार व्यवस्था
एफडीपी	संकाय विकास कार्यक्रम
एफआरआर	प्रथम प्रतिक्रिया रेडियो
जीआईडीआरआर	सुशासन तथा समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण
जीएमआरडी	भू-मौसम सम्बन्धी जोखिम प्रबन्धन प्रभाग
एचएपी	स्वास्थ्य अनुकूलन योजना
एचईआई	उच्च शिक्षा संस्थान
एचईएलपी	बड़ी जनसंख्या में स्वास्थ्य आपात परिस्थितियां
एचआरवीए	जोखिम सम्बन्धी खतरे की भेद्यता का आकलन
एचआरवीसीए	जोखिम खतरा भेद्यता तथा क्षमता आकलन
आईसीएसएसआर	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद
आईडीएएस	भारतीय रक्षा लेखा सेवा
आईडीआरएन	भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क
आईईसी	सूचना शिक्षा तथा संचार
आईजीईएस	इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एनवायरमेंटल स्ट्रेटजीस
आईआईएचआर	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान
आईएनसीओआईएस	भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र
आईएसआईडी	औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान
आईटीएस	भारतीय दूरसंचार सेवा
आईयूआईएन	भारतीय विश्वविद्यालय तथा संस्थान नेटवर्क
जेएनयू	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
केएसएनडीएमसी	कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केन्द्र
एमसीटी	सामुहिक समागम तथा परिवहन
एमएचए	गृह मंत्रालय
एमओए	समझौता ज्ञापन
एमओएएफडब्लू	कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय
एमओईएफसीसी	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओएचएफडब्लयू	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय
एमओपी और एनजी	पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय
एमओएसजेई	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन

एनएबीएम	राष्ट्रीय प्रसारण एवं मल्टीमीडिया अकादमी
एनएडीएफएम	राष्ट्रीय रक्षा वित्तीय प्रबंधन अकादमी
एनएडीएमपी	राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना
एनडीएमए	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एनडीएमपी	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना
एनडीआरएफ	राष्ट्रीय आपदा राहत राशि
एनईआरआईएसटी	उत्तर – पूर्व क्षेत्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान
एनजीओ	गैर सरकारी संस्थान
एनआईडीएम	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
एनआईईएसबीयूडी	राष्ट्रीय उद्यमिता तथा लघु व्यापार विकास संस्थान
एनकेएमसीसी	जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय ज्ञान मिशन
एनपीडीआरआर	आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच
एनटीआईपीआरआईटी	राष्ट्रीय दूरसंचार नीति शोध, नवपर्वतन एवं प्रशिक्षण संस्थान
ओपीएसी	ऑनलाईन पब्लिक एक्सैस कैटालोग्स
पीडीएनए	आपदा पश्चात् आवश्यकता आकलन
पीडीआर	आपदा पश्चात् पुनर्निर्माण
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पीटीसी	मनोसामाजिक और आघात देखभाल
आरडी	ग्रामीण विकास
आरआईएफडी	समुत्थानशील अवसंरचना प्रभाग
आरएमआरएस	जोखिम शमन तथा प्रतिक्रिया रणनीति
एससीडीआर	आपदा अनुसंधान के लिए विशेष केन्द्र
एसडीएमए	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एसओपी	मानक परिचालन प्रक्रिया
टीओटी	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
टीएसएस	प्रशिक्षण सहायता सेवायें
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
यूएनईपी	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
युएनईएससीएपी	एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग
यूनीसेफ	संयुक्त राष्ट्र बाल आपात काल कोष
डब्लयूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
यशादा	यशवंतराव चव्हाण अकैडमी ऑफ डेवलॉपमेंट एडमिन्सट्रेशन

Resilient India - Disaster free India

मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल
वी एस एम
कार्यकारी निर्देशक

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)
National Institute of Disaster Management
Ministry of Home Affairs, Govt. of India
A-Wing, 4th Floor, NDCC-II, Jai Singh Road, New Delhi - 110001



कार्यकारी निदेशक के लेखन पटल से

यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है कि किसी देश में समावेशी विकास लाने के लिए जनसाधारण के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के परिणामों और प्रभावों का संचार महत्वपूर्ण है । एनआईडीएम अद्वितीय ढंग से इसमें योगदान दे रहा है । आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत, एनआईडीएम को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन और नीति समर्थन के लिए बुनियादी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पहले एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में और फिर राष्ट्रीय संस्थान के रूप में, एनआईडीएम ने राष्ट्रीय एजेंडा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को अग्र स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

वर्ष 2019 में जलवायु आपातकाल वैश्विक एजेंडा का शीर्ष विषय था । निश्चित रूप से पिछले पांच वर्षों तथा दशक के रिकार्ड की तुलना में सर्वाधिक गर्मी के साथ वर्ष की समाप्ति हुई । ग्रहों की सीमाओं का उल्लंघन किया गया है, और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने में असमर्थता बड़ी, विषम और अत्यधिक विनाशकारी आपदाओं के जोखिम को और बढ़ाती है । ये घटनाक्रम जीवन, आजीविका, पारिस्थितिकी तंत्र और विकास लाभ की रक्षा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशिष्ट महत्व को उजागर करते हैं । जोखिम न्यूनीकरण स्थायी विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और यह मानवीय बोझ को कम करने के लिए भी अपरिहार्य है । दुनिया आपदा-प्रतिक्रिया-मरम्मत-आवृति के चक्र में फंस गई है और इस प्रणाली से जुड़ी लागत बढ़ रही है ।

इस विषय पर विचार सांझा करने, चर्चा करने, विचार-मंथन करने के लिए 25 फरवरी 2020 को तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता पर एनआईडीएम ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया । इस सम्मेलन में प्रधान मंत्री के 10 बिंदु एजेंडे को लागू करके तटीय आपदा जोखिमों और प्रभावी सहयोगी कार्यों के बारे में बेहतर समझ के मामले में मानव क्षमता को बढ़ाने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाइ फ्रेमवर्क को लागू करके जोखिम को कम करने और प्रभावित हितधारकों के बीच समुत्थानशीलता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया । इस राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संगठनों / संस्थानों से लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

वैज्ञानिक आधुनिक शिक्षा विधियों को अपनाकर और संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण पुस्तिकायें तथा मार्गदर्शन और व्यवसायिक प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करके, एनआईडीएम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है ।

वार्षिक रिपोर्ट उन गतिविधियों और कार्यक्रमों की एक झलक प्रस्तुत करती है जो एनआईडीएम ने इसके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति नई अंतर्दृष्टि को बढ़ावा देने और समाज के विभिन्न वर्गों में इसे आगे बढ़ाने के लिए आरम्भ और पोषित किए हैं ।

MKBindal

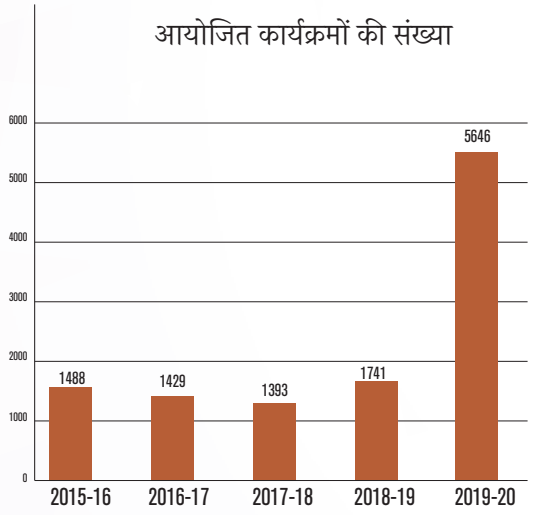
मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल
वीएसएम
कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम

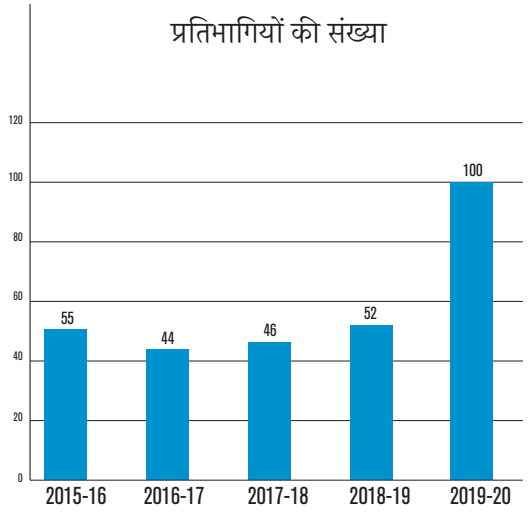
आपदा प्रबंधन महाविचार: पूरा भारत भागीदार

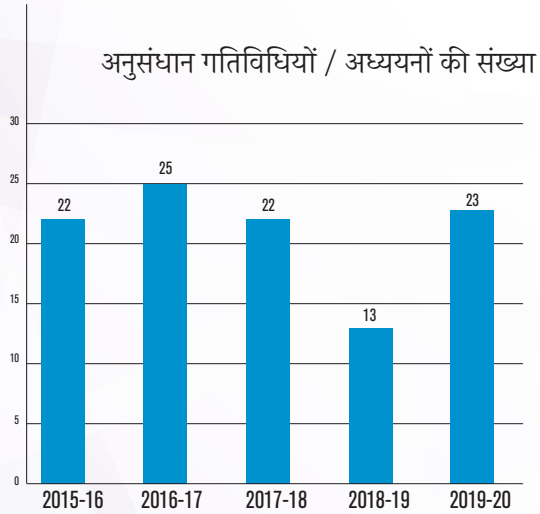
फोन / Ph: +91-11-23438285, • फैक्स / Fax: +91-11-23438286, • ई मेल / E-mail: ed.nidm@nic.in, • वेब साईट / Website : www.nidm.gov.in

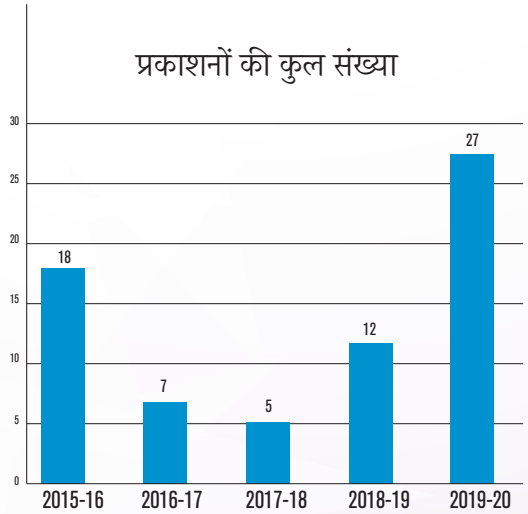
गतिविधियों की समीक्षा (2019-20)

2019-20 में 5646 प्रतिभागियों के लिए कुल 100 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें महिला प्रतिभागियों की भागीदारी 26.63 प्रतिशत थी। राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यापक वृद्धि हुई। 2019-2020 में, 28 राज्यों को कवर किया गया। ऐसा पहली बार हुआ, जब प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किए गए थे। वर्ष के दौरान 208 प्रतिभागियों के लिए कुल 6 ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रशिक्षण कार्यशालाएं / सेमिनार / सम्मेलन / अन्य गतिविधियां की संख्या 2015-16 में 20 से बढ़कर 2019-20 में 36 हो गईं तथा शोध गतिविधियों और अध्ययनों की संख्या भी 2015-16 में 22 से बढ़कर 2019-20 में 23 हो गई । पिछले वर्ष एनआईडीएम द्वारा प्रकाशित किए गए प्रकाशनों की कुल संख्या 27 थी। निम्नलिखित ग्राफिक चित्रण एनआईडीएम द्वारा इन वर्षों में विभिन्न गतिविधियों में अर्जित सापेक्ष वृद्धि को सारांशित करता है ।









अध्याय 1

सिंहावलोकन

अध्याय 1: सिंहावलोकन

1.1 संस्थान के बारे में

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन 30.10.2006[1] को गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) को आपदा प्रबंधन नीतियों, निवारक तंत्र और शमन उपायों[2] के संबंध में आपदा प्रबंधन प्रलेखीकरण और राष्ट्रीय स्तर का सूचना आधार तैयार करने के क्षेत्र में योजना बनाने और प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का दायित्व सौंपा गया है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र से 16 अक्टूबर, 2003 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के रूप में पुन: अधिकारिक नामकरण के बाद से एनआईडीएम सभी स्तरों पर आपदा निवारण और इसके लिए तैयार रहने की संस्कृति का विकास करके तथा इसे बढ़ावा देकर एक आपदा समुत्थानशील भारत तैयार करने के अपने लक्ष्य की ओर निंतर अग्रसर है।

1.2 प्रबंधन संरचना

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नियम, 2006 के अनुसार, संस्थान में 42 सदस्य हैं जिनमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न नोडल मंत्रालयों/विभागों के सचिव, राष्ट्रीय स्तर के संबंधित वैज्ञानिक, अनुसंधान और तकनीकी संगठनों के अध्यक्ष, प्रसिद्ध विद्वान, वैज्ञानिक और व्यावसायिक शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इस संस्थान के अध्यक्ष हैं। एनआईडीएम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित व्यापक नीतियों और दिशा-निर्देशों के अधीन कार्य कर रहा है।

संस्थान की शासी परिषद् में 15 सदस्य हैं जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और गृह सचिव उपाध्यक्ष[3] हैं। संस्थान के दैनिक प्रशासन का संचालन कार्यकारी निदेशक द्वारा किया जाता है।

संस्थान के निम्नलिखित शैक्षिक विभाग हैं:-

- सुशासन एवं समावेशी डीआरआर प्रभाग (जीआईडीआरआर)
- आपदा प्रतिक्रिया और रिकवरी प्रभाग (डीआरआरडी)
- भौगोलिक-मौसम संबंधी जोखिम प्रबंधन प्रभाग (जीएमआरडी)
- आपदा समुत्थानशील संरचना प्रभाग (आरआईएफडी)
- सीबीआरएन और साइबर जोखिम प्रबंधन प्रभाग (सीआरएमडी)
- पर्यावरणीय आपदा जोखिम प्रबंधन प्रभाग (ईडीआरएम)

इसके अलावा, संस्थान में 21 केंद्र और 7 कार्यात्मक समन्वय प्रकोष्ठ हैं।

1.3 परिकल्पना

भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक अग्रणी उत्कृष्टता प्राप्त संस्थान बनना और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणी संस्थान के रुप में अपनी पहचान बनाना। सभी स्तरों पर आपदा निवारण और इसकी तैयारी करने की संस्कृति का विकास और संवर्धन करके एक आपदामुक्त भारत के निर्माण के प्रति निरंतर प्रयास करना।[4]

[1]एनआईडीएम का गठन 30.10.2006 से एस.ओ. 1862(ई) द्वारा किया गया है।
[2]आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, धारा 42(8)
[3]एनआईडीएम नियम, 2006 की धारा 6
[4]प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक

1.4 मिशन

- नीति निर्माण में सहायता देकर सरकार के लिए एक विचारक मंडल के रूप में कार्य करना;
- निम्नलिखित द्वारा आपदाओं के दुष्परिणामों और प्रभावों को कम करने में सहायता देना;
  - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सेवाओं की आयोजना और संवर्धन;
  - अनुसंधान, प्रलेखीकरण और राष्ट्रीय स्तर का सूचना आधार तैयार करना;
  - आपदा के लिए प्रभावी ढंग से तैयारी करने और राहत के लिए पद्धति विकास और सुविज्ञता को प्रोत्साहित करना;
  - जागरूकता को बढ़ावा देना और सभी हितधारकों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना;
  - सभी संबंधितों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए संस्थानिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण;
  - नेटवर्किंग और सूचना, अनुभव और सुविज्ञता के आदान प्रदान को सुगम बनाना।[5]

1.5 कार्य

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन संस्थान को निम्न कार्य[6] सौंपे गए हैं:-

- आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, आपदा प्रबंधन में अनुसंधान और प्रलेख करना और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
- आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को समाहित करते हुए एक व्यापाक मानव संसाधन विकास योजना का निर्माण और कार्यान्वयन;
- राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार करने में सहायता प्रदान करना;
- विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के विकास के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों को आवश्यक सहायता प्रदान करना;
- राज्य स्तरीय नीतियों, रणनीतियों, आपदा प्रबंधन ढांचे के निर्माण और क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक अन्य सहायता के रूप में राज्य सरकार और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान करना;
- शैक्षिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित आपदा प्रबंधन के लिए शैक्षिक सामग्रियों का विकास;
- कॉलेज या स्कूल के शिक्षकों और छात्रों, तकनीकी कर्मियों और बहु-जोखिम न्यूनीकरण, तैयारियों और प्रतिक्रिया उपायों से जुड़े अन्य लोगों सहित हितधारकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना;
- उपरोक्त उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए देश के भीतर और बाहर अध्ययन पाठ्यक्रम, सम्मेलनों, व्याख्यानों, सेमिनारों को आयोजित करना और सुगम बनाना;

[5]प्रबंधन समिति की पहली बैठक की कार्यसूची
[6]आपदा प्रबंधन अधिनियम, धारा 42(9)

- पत्रिकाओं, शोध पत्रों और पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहायता प्रदान करना और पुस्तकालयों की स्थापना और रख-रखाव आदि;
- उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक तथा प्रासंगिक अन्य सभी विधि सम्मत कार्य करना; तथा
- केंद्र सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों का निष्पादन।

1.6 प्रमुख क्षेत्र

1.6.1 प्रशिक्षण

i. **आमने-सामने प्रशिक्षण:** एनआईडीएम सरकारी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए व्यापक विषयों और क्षेत्रों को कवर करते हुए विभिन्न विषयों पर परिसर में और परिसर के बाहर दोनों जगह प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

ii. **वेब आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण:** यह संस्थान आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विशेष विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रयोक्ता रजिस्टर करके ऑनलाइन अध्ययन पोर्टल का प्रयोग कर सकते हैं।

iii. **स्व-अध्ययन पाठ्यक्रम:** संस्थान ने वेब आधारित स्व-अध्ययन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं जिसके लिए, कोई भी, किसी भी समय लॉग-ऑन कर सकता है और इन पाठ्यक्रमों के अध्ययन से सीख सकता है।

1.6.2 अनुसंधान और प्रलेखीकरण

एनआईडीएम देश में होने वाली बड़ी आपदाओं का प्रलेखीकरण करता है ताकि इनके प्रबंधन से सबक लिया जा सके और इन मामलों के अध्ययन का प्रयोग प्रशिक्षण कक्षाओं के लिए संसाधन सामग्री और अनुकरण अभ्यास के लिए किया जा सके।

1.6.3 नीति अध्ययन और सहायता

ज्ञान और अनुसंधान संस्थान होने के नाते एनआईडीएम गृह मंत्रालय, एनडीएमए और अन्य हितधारकों को राष्ट्रीय स्तर के दिशा-निर्देश, नीतियां और योजनायें आदि तैयार करने में सहायता प्रदान करता है।

एनआईडीएम राज्य स्तर की नीतियां, रणनीतियां, आपदा प्रबंधन ढांचा तैयार करने में राज्य सरकारों और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों तथा हितधारकों के क्षमता निर्माण और उनके (राज्य सरकारों या राज्य प्रशिक्षण संस्थानों) द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता भी प्रदान करता है।

1.6.4 ज्ञान एकीकरण

एनआईडीएम नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, शोध, प्रलेखीकरण आदि के लिए कार्यक्रम आधारित गतिविधियों पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ संस्थानों के साथ सहयोग द्वारा ज्ञान एकीकरण करता है।

अध्याय 2

संगठनात्मक व्यवस्था

अध्याय 2: संगठनात्मक व्यवस्था

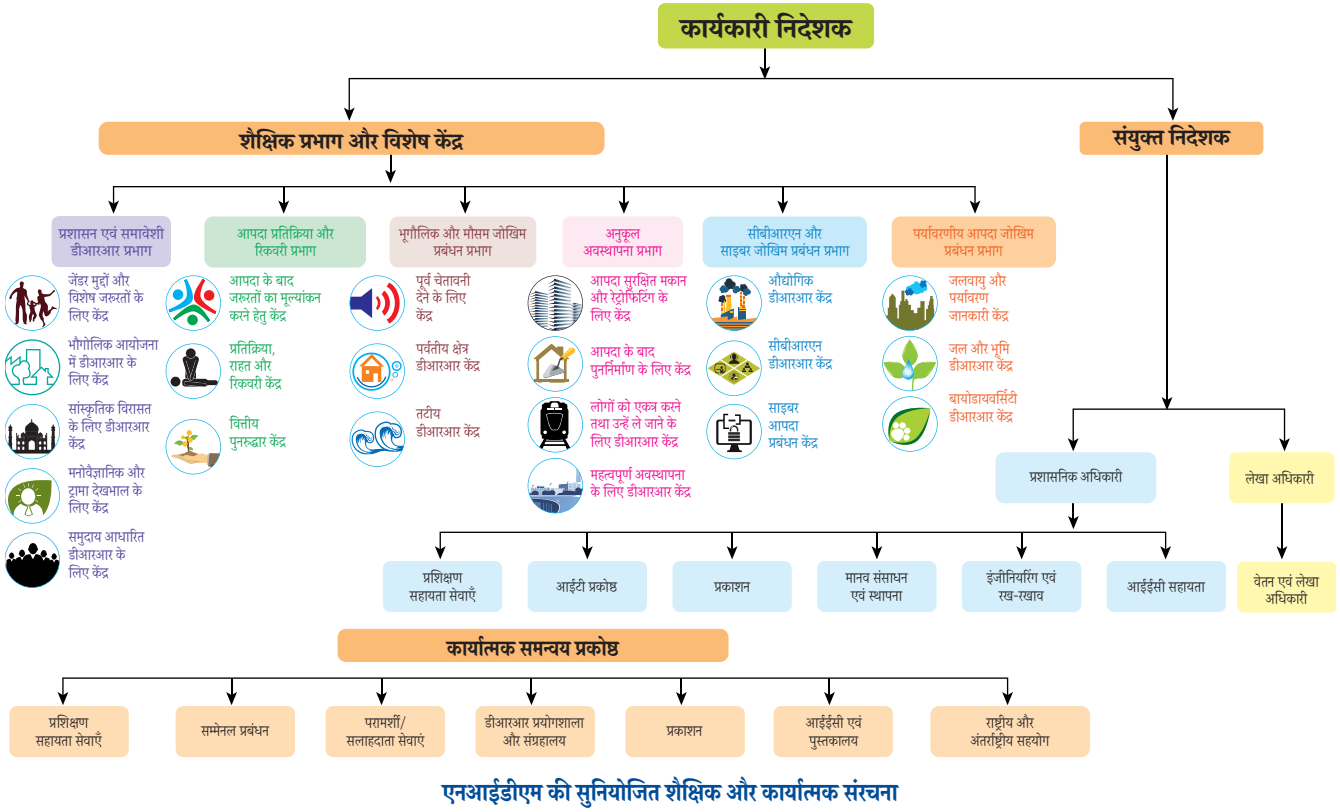
केंद्रीय गृह मंत्री इस संस्थान की आम सभा के अध्यक्ष हैं, और कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य सचिव हैं।

संस्थान में 42 सदस्य हैं, जिनमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न नोडल मंत्रालयों एवं विभागों के सचिव और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, अनुसंधान और तकनीकी संस्थानों के अध्यक्षों के अलावा प्रसिद्ध विद्वान, वैज्ञानिक और व्यवसायी शामिल हैं, **(अनुलग्नक-I: संस्थान के सदस्यों की सूची)**

संस्थान की एक शासी परिषद है जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और केंद्रीय गृह सचिव संस्थान के शासी परिषद् के उपाध्यक्ष हैं। **(अनुलग्नक-II: संस्थान की शासी परिषद् के सदस्यों की सूची)**

संस्थान के छः प्रभाग और 21 विशेष केंद्र हैं जिनकी सहायता के लिए 7 कार्यात्मक समन्वय प्रकोष्ठ हैं। (चित्र 2.1):-

2.1 संगठनात्मक ढांचा



एनआईडीएम की सुनियोजित शैक्षिक और कार्यात्मक संरचना

चित्र 2.1

तालिका 2.1: एनआईडीएम के कार्यकारी अधिकारी

क) कार्यकारी निदेशक

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री संजीव कुमार जिंदल	संयुक्त सचिव (डी एम) गृह मंत्रालय एवं कार्यकारी निदेशक एनआईडीएम (अतिरिक्त प्रभार) (12.03.2019 से 31 मई, 2019 तक)
2.	मेजर जनरल मनोज कुमार बिंदल, वी.एस.एम	कार्यकारी निदेशक (01.06.2019 से आज तक)

ख) संयुक्त निदेशक

क्र.सं.	नाम	पदनाम
3.	लेफ्टिनेंट कर्नल दिनेश चन्द्र वशिष्ठ	संयुक्त निदेशक (14.11.2019 से आज तक)

ग) परामर्शदाता

क्र.सं.	नाम	पदनाम
3.	श्री सुरेन्द्र ठाकुर	परामर्शदाता (11.09.2019 से आज तक)
4.	श्री आशीष कुमार पांडा	परामर्शदाता (06.09.2019 से आज तक)

घ) प्रशासनिक अधिकारी

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री विक्रम गुर्जर	डिप्टी कमांडेंट (प्रशिक्षण एवं प्रशासन) (07.02.2019 से आज तक) एनडीआरएफ से संबद्ध किए जाने पर

एनआईडीएम की प्रभागवार संकाय सूची तालिका 2.2 में दी गई है।

तालिका 2.2: एनआईडीएम का संकाय

1. सीबीआरएन और साइबर जोखिम प्रबंधन प्रभाग (सीआरएमडी)		
डॉ. आमिर अली खान		सहायक प्रोफेसर एवं प्रमुख
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र		केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य
i.	औद्योगिक डीआरआर केंद्र (आईएनडी)	-
ii.	सीबीआरएन डीआरआर केंद्र (सीबीआरएन)	-
iii.	साइबर आपदा प्रबंधन केंद्र (सीवाईडी)	-

2. आपदा प्रतिक्रिया और रिकवरी प्रभाग (डीआरआरडी)		
डॉ. संतोष कुमार		प्रोफेसर एवं प्रमुख
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र		केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य
i.	आपदा पश्चात् आवश्यकता मूल्यांकन केंद्र (पीडीएनए)	-
ii.	प्रतिक्रिया, राहत और रिकवरी केंद्र (आरआरआर)	श्री शेखर चतुर्वेदी, सहायक प्रोफेसर
iii.	वित्तीय पुनरुद्धार केंद्र (एफआर)	
3. पर्यावरणीय आपदा जोखिम प्रबंधन प्रभाग (ईडीआरएम)		
डॉ. अनिल कुमार गुप्त		प्रोफेसर एवं प्रमुख
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र		केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य
i.	जलवायु अनुकूलन और पर्यावरण केंद्र (सीआरई)	डॉ. सुषमा गुलेरिया, सहायक प्रोफेसर
ii.	जल और भूमि डीआरआर केंद्र (डब्ल्यूएलडी)	डॉ. सुषमा गुलेरिया, सहायक प्रोफेसर
iii.	वन और बायोडायवर्सिटी डीआरआर केंद्र (एफबीडी)	डॉ. ए. डी. कौशिक, (31.12.2019 से सेवानिवृत्त।) अनुसंधान एसोसिएट वर्तमान में श्री आशीष कुमार पांडा (01.01.2020 से आज तक)
4. भूमि-मौसम संबंधी जोखिम प्रबंधन प्रभाग (जीएमआरडी)		
डॉ. सूर्य प्रकाश		प्रोफेसर एवं प्रमुख
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र		केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य (जी एम आर डी)
i.	पूर्व चेतावनी संचार केंद्र (ईडब्ल्यूसी)	डॉ. सूर्य प्रकाश
ii.	पर्वतीय क्षेत्र डीआरआर केंद्र (एचएडीआरआर)	डॉ. सूर्य प्रकाश
iii.	तटीय डीआरआर केंद्र (सीडीआरआर)	डॉ. सूर्य प्रकाश
5. सुशासन और समावेशी डीआरआर प्रभाग (जीआईडीआरआर)		
डॉ. संतोष कुमार		प्रोफेसर एवं प्रमुख
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र		केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य (जी आई डी आर आर)
i.	जेंडर मुद्दों और विशेष आवश्यकताओं के लिए केंद्र (जीआईएन)	डॉ. अजिन्दर वालिया, सहायक प्रोफेसर

ii.	भौगोलिक आयोजना में डीआरआर के लिए केंद्र (जीपीएल)	डॉ. चंद्राणी बंद्योपाध्याय, सहायक प्रोफेसर
iii.	सांस्कृतिक विरासत केंद्र (सीएचआर)	डॉ. चंद्राणी बंद्योपाध्याय, सहायक प्रोफेसर
iv.	मनोवैज्ञानिक तथा ट्रॉमा देख रेख केंद्र (पीटीसी)	डॉ. अजिन्दर वालिया, सहायक प्रोफेसर
v.	समुदाय आधारित डीआरआर केंद्र (सीबीडीआरआर)	डॉ. चंद्राणी बंद्योपाध्याय, सहायक प्रोफेसर
6. समुत्थानशील अवसंरचना प्रभाग (आरआईएफडी)		
डॉ. चन्दन घोष		प्रोफेसर एवं प्रमुख (04.09.2019 से आई.आई.टी जम्मू में प्रतिनियुक्ति पर)
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र		केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य (आर आई एम डी)
i.	आपदा सुरक्षित मकान और रेट्रोफिटिंग केंद्र (डीएसएचआर)	-
ii.	आपदा पश्चात् पुनर्निर्माण केंद्र (पीडीआर)	-
iii.	जन एकत्रीकरण और परिवहन डीआरआर केंद्र (एमसीटी)	श्री शेखर चतुर्वेदी, सहायक प्रोफेसर
iv.	महत्वपूर्ण अवस्थापना डीआरआर केंद्र (सीआईडी)	-
7. कार्यात्मक समन्वय प्रकोष्ठ		
i.	प्रशिक्षण सहायता सेवाएँ (टीसीएस)	i. श्री विक्रम गुर्जर, डिप्टी कमांडेंट प्रभारी (टी एस एस) ii. सुश्री ऋतु सूद, प्रशासनिक अधिकारी
ii.	सम्मेलन प्रबंधन (सीएफएम)	
iii.	परामर्शी/सलाहकार सेवाएँ (सीएएस)	i. डॉ. अनिल कुमार गुप्त, प्रोफेसर ii. श्री शेखर चतुर्वेदी, सहायक प्रोफेसर iii. सुश्री ऋतु सूद, प्रशासनिक अधिकारी
iv.	डीआरआर प्रयोगशाला और संग्रहालय (डीएलएम)	i. डॉ. चन्दन घोष, प्रोफेसर (04.09.2019 से आईआईटी जम्मू में प्रतिनियुक्ति पर) ii. डॉ. आमिर अली खान, सहायक प्रोफेसर iii. सुश्री ऋतु सूद, प्रशासनिक अधिकारी
v.	प्रकाशन (पीयूबी)	i. श्री विक्रम गुर्जर, डिप्टी कमांडेंट, प्रभारी (प्रकाशन) ii. श्री संतोष कुमार तिवारी, पुस्तकालयाध्यक्ष

vi.	आईईसी और पुस्तकालय (आईईएल)	i. श्री विक्रम गुर्जर, डिप्टी कमांडेंट प्रभारी (आई ई एस) ii. श्री संतोष कुमार तिवारी, पुस्तकालयाध्यक्ष iii. सुश्री जया, पुस्तकालय अटैंडेंट
vii.	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (एनआईसी)	i. डॉ. संतोष कुमार, प्रोफेसर एवं प्रमुख ii. डॉ. अनिल कुमार गुप्त, प्रोफेसर एवं प्रमुख iii. डॉ. सुषमा गुलेरिया, सहायक प्रोफेसर

2.2 सामान्य प्रशासन

संस्थान के कार्यकारी निदेशक संस्थान के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं और शासी परिषद् के निर्देश और मार्गदर्शन के अधीन कार्य करते है। कार्यकारी निदेशक की सहायता के लिए संयुक्त निदेशक, परामर्शदाता (प्रशासन एवं मानव संसाधन), लेखा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी हैं। संस्थान के प्रशासन में मुख्यतया समन्वय, सांविधिक बैठकों का आयोजन, स्थापना और कार्मिक प्रबंधन, सुरक्षा, परिसर सहायता सेवाएं और कर्मचारियों का कल्याण शामिल है। यह कार्यक्रमों के अबाध आयोजन के लिए आवश्यक अवस्थापना और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करके संस्थान के शोध, प्रशिक्षण और परामर्शी कार्यों में मदद करता है। एनआईडीएम के कर्मचारियों की सूची तालिका 2.3 में दी गई है।

तालिका 2.3: एनआईडीएम के कर्मचारी

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	सुश्री ऋतु सूद	प्रशासनिक अधिकारी
2.	श्री एस.एस. बिष्ट	लेखा अधिकारी
3.	श्री हेमंत कुमार	कंप्यूटर प्रोग्रामर
4.	श्री संतोष कुमार तिवारी	पुस्तकालयाध्यक्ष
5.	श्री अविनाश कुमार पाण्डेय	वैयक्तिक सचिव
6.	श्री जे.एन. झा	कनिष्ठ अभियन्ता
7.	सुश्री अमृता गुप्ता	वैयक्तिक सहायक
8.	सुश्री संतोष मिश्रा	प्रशिक्षण सहायक
9.	सुश्री गीता शर्मा	प्रशिक्षण सहायक

10.	सुश्री मेघा कोहली (30.12.2019 से एन.एच.आर.सी में प्रतिनियुक्ति पर)	प्रशिक्षण सहायक
11.	श्री राजीव कुमार	प्रशिक्षण सहायक
12.	श्री अमर सिंह	मशीन ऑपरेटर
13.	सुश्री जया	पुस्तकालय अटेंडेंट
14.	श्री लक्ष्मण सिंह	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)
15.	श्री विजय कनौजिया	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)
16.	श्री पंकज कुमार	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)

2.3 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

एनआईडीएम में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस कार्यक्रमों/ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न आईईसी सामग्री जैसे पोस्टर, बुक मार्क, पैमफ्लेट, और वार्षिक रिपोर्ट आदि एनआईडीएम द्वारा हिंदी में तैयार की गई है। बैवसाइट को भी द्विभाषीय बनाया गया है।

अध्याय 3

प्रशिक्षण कार्यक्रम

अध्याय 3: प्रशिक्षण कार्यक्रम

आपदा प्रबंधन में संलग्न पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण पर जोर देना संस्थान के प्रमुख प्रयासों में से एक रहा है। इस प्रयास के रूप में, एनआईडीएम आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में विभिन्न क्षमता निर्माण मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं । कार्यक्रम उपलब्ध कराने की विधि के आधार पर इन्हें निम्नवत रूप में वर्गीकृत किया गया है :

i. आमने-सामने प्रशिक्षण
ii. ऑनलाइन प्रशिक्षण
iii. स्व-अध्ययन प्रशिक्षण

क्योंकि एनआईडीएम आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को अपनी सेवायें प्रदान करता है, एनआईडीएम सरकारी अधिकारियों, सिविल समाज संगठनों (आपदा प्रबंधन पेशेवरों), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, शिक्षाविदों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों (सरकारी विभागों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय स्वंय सेवी संगठनों) को प्रशिक्षण प्रदान करता है । ।

3.1 उद्देश्य

नीतियों, योजना और कार्यक्रमों में डीआरआर को मुख्य धारा के रूप में जोड़ने के लिए कौशल प्रदान करना एनआईडीएम का एक प्राथमिक उद्देश्य है । आपदा और विकास गतिविधियों में संलग्न आपदा प्रबंधन कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों को संकेंद्रित और समुचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए एनआईडीएम द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं :

- प्रभावी कार्यक्रम नियोजन और कार्यान्वयन के लिए जागरूकता पैदा करना, कौशल में सुधार करना और विकास प्राधिकारियों के ज्ञान को विस्तृत करना ;
- सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन क्षेत्र में उभरती जरूरतों के प्रति केंद्र और राज्यों के विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील बनाना ;
- परिचयात्मक दौरों, मामलों के अध्ययन और विकासात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से विकास कर्मियों में व्यवहारिक बदलाव लाना ।

3.2 आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

उपलब्ध कराने की विधि, लक्षित समूह और विषय के आधार पर एनआईडीएम के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वर्गीकृत किया गया है ।

3.2.1 आमने-सामने प्रशिक्षण

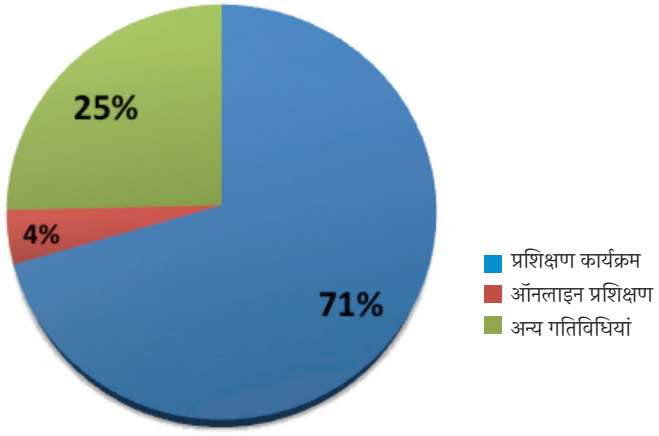
संस्थान अपने परिसर में या राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) / राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में आमने-सामने प्रशिक्षण विधि से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है । शैक्षिक प्रभागों के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आपदा प्रबंधन के लगभग सभी पक्षों को शामिल किया जाता हैं ।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान एनआईडीएम, नई दिल्ली तथा एनआईडीएम दक्षिणी परिसर द्वारा 100 आमने-सामने के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 5646 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया । एनआईडीएम द्वारा 30 कार्यशालाएं / सेमिनार/ सम्मेलन तथा अन्य गतिविधियां आयोजित की गईं जिनमें 1920 प्रतिभागियों ने भाग लिया । इसके अतिरिक्त 6 ऑनलाइन

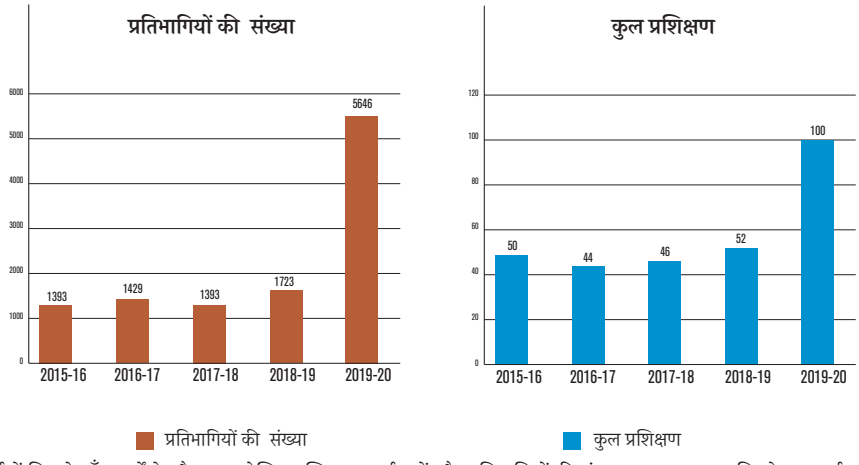
पाठ्यक्रम इस अवधि के दौरान सम्पन्न किए गए जिनमें 208 प्रतिभागियों ने भाग लिया । पिछले 5 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि एनआईडीएम द्वारा लगभग सभी राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों के अंतर्गत शामिल किया है । इस वर्ष, वर्तमान में कोविड-19 परिस्थितियों के कारण केवल 7 राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश ऐसे रहे, जहां कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा अन्य गतिविधि आयोजित नहीं की जा सकी ।

तालिका 3.1: वर्ष 2019-20 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

प्रशिक्षण कार्यक्रम		प्रशिक्षण कार्यक्रम		अन्य गतिविधियां	
कुल प्रशिक्षण	प्रतिभागियों की कुल संख्या	कुल ऑनलाइन प्रशिक्षण	प्रतिभागयों की कुल संख्या	कुल कार्यशालायें / सम्मेलन / अध्ययन गोष्ठियां	प्रतिभागियों की कुल संख्या
100	**5646**	**6**	**208**	**36**	**2144**



चित्र 3.1: 2019-20 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण



चित्र 3.2: बार चार्ट में पिछले पाँच वर्षों के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रतिभागियों की संख्या का तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाया गया है ।

3.3 प्रशिक्षण विधि

उपलब्ध कराये जा रहे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और साथ ही कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रशिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है । प्रशिक्षण विधियों में शामिल हैं :

- व्याख्यान सह-विचार-विमर्श
- मामला अध्ययन प्रस्तुतीकरण
- कार्य का अभ्यास
- समूह विचार-विमर्श/अभ्यास
- परिचयात्मक और अध्ययन दौरे
- पैनल विचार-विमर्श
- अनुकरण और भूमिका निभाना
- टेबल टॉप अभ्यास

3.4 प्रतिभागियों का विवरण

चूंकि एनआईडीएम द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन में लगे विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को शामिल किया गया है, अत: प्रशिक्षुओं की प्रोफाइल को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है;

- सरकारी कर्मचारी (केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के अधिकारी);
- सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू);
- शिक्षाविद् (शोधकर्ता, वैज्ञानिक, स्कूल शिक्षक और विश्वविद्यालय संकाय) ;
- ज्ञान भागीदार संस्थान;
- अंतर्राष्ट्रीय भागीदार (सरकारी विभाग, यूएन एजेंसियां, आईएनजीओ);
- अवसंरचना व्यवसायिक (इंजीनियर, वास्तुक, निर्माण एजेंसियां आदि);
- सिविल समाज संगठन (आपदा प्रबंधन व्यावसायिक)।

3.5 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान विश्व बैंक के सहयोग से आपदा जोखिम प्रबंधन पर ई-लर्निंग कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करता है । ये पाठ्यक्रम प्रतिभागियों को व्यवसायिक दिशा-निर्देशन के अन्तर्गत आपदा जोखिम प्रबंधन और राहत के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ अवसर उपलब्ध कराते हैं । प्रशिक्षण सामग्री ऑनलाइन देखी जा सकती है और पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद किसी भी समय प्रयोग के लिए डाइनलोड की जा सकती है । पंजीकृत प्रतिभागियों द्वारा सभी मॉड्यूल ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखे जा सकते है । इस कार्यक्रम में प्रस्तुतियों और श्रव्य, चर्चा मंच, प्रश्नोतर, स्पष्टीकरण, अभ्यास

और पाठ्यक्रम समाप्ति प्रोजेक्ट शामिल है, जिनका मूल्यांकन अनुभव प्राप्त पाठ्यक्रम सहायकों द्वारा किया जाता है । सफल होने वाले उम्मीदवारों को एनआईडीएम और विश्व बैंक संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं ।

3.6 स्व-अध्ययन कार्यक्रम

एनआईडीएम जन-सामान्य के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों और आपदा प्रबंधन में कार्य और जिम्मेदारी निभाने वाले अन्य हितधारकों के लिए स्व-अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उपलब्ध कराता है । स्व-अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी उसकी अपनी सुविधा के अनुसार नि:शुल्क देखे जा सकते हैं । इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के प्रति रूचि उत्पन्न करना और इस विषय में जानकारी, कौशल और जागरूकता का स्तर बढ़ाना है । **(www.nidmssp.in)**

3.7 इंटर्नशिप कार्यक्रम

हर वर्ष, एनआईडीएम को शैक्षिक / शोध / प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों / शोधकर्ताओं से, विशेषकर गर्मी के महीनों में, इंटर्नशिप के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं । इंटर्नशिप के उद्देश्य हैं :-

- संबंधित विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर करने वाले इच्छुक व पात्र उम्मीदवारों को समग्र आपदा प्रबंधन प्रणाली और इसके विभिन्न पहलुओं की जानकारी देना।
- विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के छात्रों को आपदा प्रबंधन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और शोध में व्यवहारिक अनुभव लेने में मदद करना।
- छात्रों को उनके कौशल के परीक्षण के लिए नवाचार और नए विचारों तथा तकनीकों को शामिल करने का पर्याप्त अवसर देना।
- औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, व्यवसायिक संस्थानों को एनआईडीएम और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की जानकारी देना।
- एनआईडीएम में इंटर्नशिप के लिए एक नीति तैयार तथा अनुमोदित करके इस प्रक्रिया को औपचारिक बनाया गया है । इंटर्नशिप के लिए आवेदन खुले विज्ञापन के द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं, जिसके बाद बहु-स्तरीय चयन प्रक्रिया का पालन किया जाता है । पूरे देश से विभिन्न विषयों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों से इंटर्न शोध कार्य के लिए चुने जाते हैं ।
- वर्ष 2019-20 में चुने गए 9 इंटर्न में से 7 इंटर्न ने ज्वाइन किया और मेंटोर के रूप में विभिन्न संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन में शोध कार्य पूरा किया।

अध्याय 4

परियोजनाएं

अध्याय 4: परियोजनाएं

4.1 बहूजोखिम पर्यावरण में समुत्थानशीलता और सतत विकास के लिए जलवायु अनुकूली योजना (कैप-रस)

कैप-रस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय ज्ञान मिशन (एनकेएमसीसी) के तहत समर्थित है। परियोजना विभिन्न क्षेत्रों और स्तरों पर परामर्शदात्री कार्यशालाओं और प्रमुख हितधारकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित ज्ञान मंच के माध्यम से समर्थित क्षमता विकास के उद्देश्य से परिचालित है, तथा देश में एजेंसियों की व्यापक रेंज के लिए संसाधन व्यक्तियों के रूप में हितधारकों का प्रशिक्षण और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करती है । परियोजना के तहत उत्पादित संसाधन सामग्री में परिणाम / पाठ, केस अध्ययन, नीति / तकनीकी प्रपत्र, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पुस्तिकायें, संकलन / संसाधन खंड आदि दस्तावेज शामिल हैं।

इस परियोजना ने विभिन्न ज्ञान उत्पादों के रूप में प्रस्तुत रणनीतिक ज्ञान सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसमें शामिल हैं: 1) क्षेत्रीय नीति उपकरणों और व्यवसाय निरंतरता के माध्यम से विकासात्मक योजना और प्रथाओं में प्रकृति-आधारित समाधानों को मुख्यधारा में लाने पर दो पुस्तक अध्याय और प्रकृति-आधारित समाधानों को मुख्यधारा में लाने के लिए, नए रास्ते की खोज ताकि समुदाय या स्थानीय स्तर पर परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के द्वारा समुत्थानशीलता स्थापित करके एस जी डी और 2015 के बाद



के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके । 2) जलवायु परिवर्तन और समुत्थानशीलता विकास पर स्थानीय सरकारी अधिकारियों की धारणा का आकलन करने और जांच करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक पत्रिका, भारत के उत्तराखंड राज्य की केस स्टडी, 3) भारत में जलवायु, आपदा समुत्थानशीलता और समुत्थानशील कृषि के लिए हरित विकास के लाभों पर दो नीति संक्षेप 4) 5 विषयगत क्षेत्रों में प्रशिक्षण की आवश्यकता और अंतराल का आकलन, 5) आपदा प्रबंधन के उभरते नए आयाम के रूप में नोवल कोरोना वायरस महामारी और स्वास्थ्य समुत्थानशीलता पर पत्रिका के लिए लेख और 6) विभिन्न अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय कार्यशालाओं, सम्मेलनों और संगोष्ठियों की कार्यवाही।

कैप-रस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की झलकियां (26-27 सितंबर 2019)



चित्र 1



चित्र 2



चित्र 3

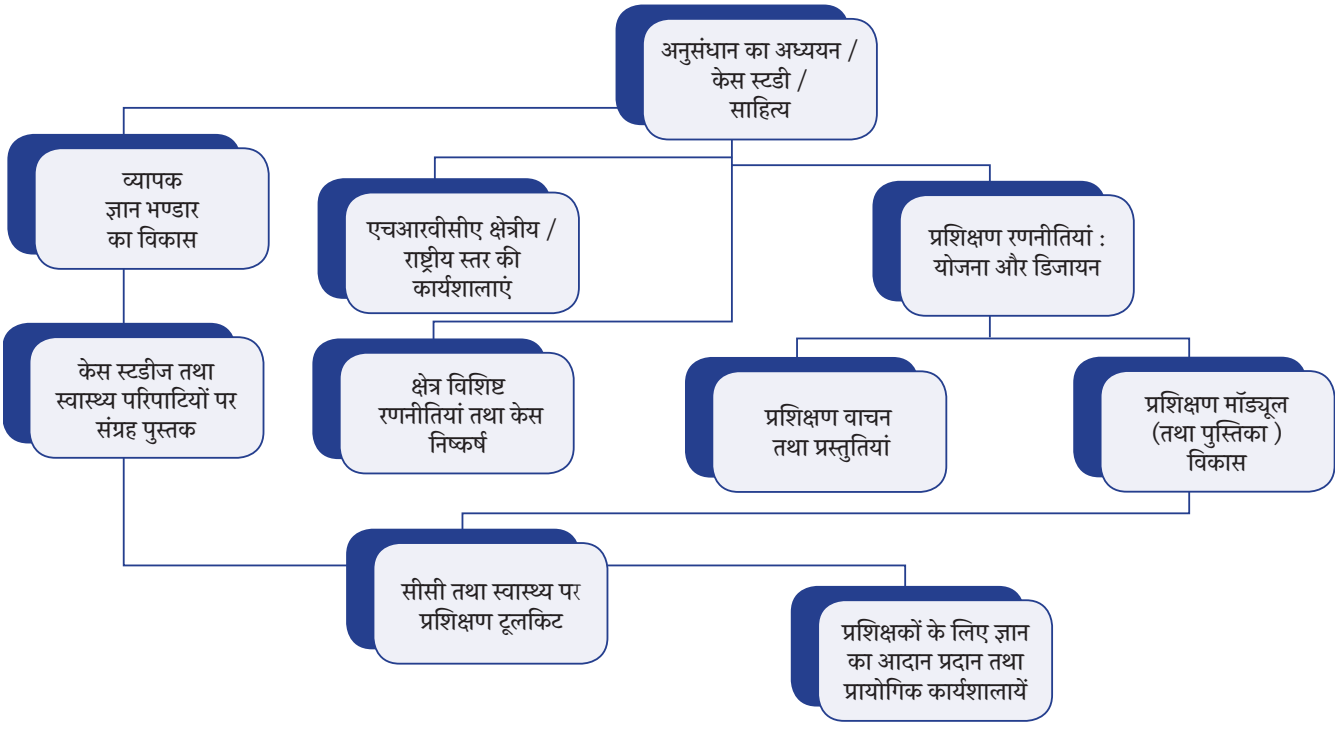


चित्र 4

4.2 स्वास्थ्य अनुकूलन और समुत्थानशीलता : रणनीतिक ज्ञान और क्षमता को आगे बढ़ाना (हर-कैप)

विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने "स्वास्थ्य अनुकूलन और समुत्थानशीलता : रणनीतिक ज्ञान और क्षमता को आगे बढ़ाना (हर-कैप)" परियोजना को लागू किया है। इस परियोजना के तहत, 2019-20 के दौरान सारे देश में,

स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, कृषि, जल स्वच्छता, ग्रामीण और शहरी विकास, उद्योग, चिकित्सा संस्थानों, निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी संगठनों के विशेषज्ञों के साथ जलवायु प्रभावों को दूर करने और स्वास्थ्य अनुकूलन और आपदा समुत्थानशीलता के लिए क्षेत्र विशेष मुद्दों को मान्यता देने के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों में मौजूदा अंतराल और चुनौतियों को समझने के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त करने के लिए चार क्षेत्रीय परामर्श कार्यशालाएं आयोजित की गईं। वर्तमान स्वास्थ्य परिदृश्य में महत्वपूर्ण खामियों की पहचान करने के बाद, जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुकूलन योजना को समुत्थानशील स्वास्थ्य सेवाओं के विकास को संभव बनाने, संस्थानों को उनकी तैयारी और क्षमता को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं के प्रभावों को कम करने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। एक प्रशिक्षण टूलकिट विकसित की गई है जो जलवायु परिवर्तन संबंधित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) दृष्टिकोणों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं और प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए एक विशिष्ट मंच प्रदान करती है। विभिन्न क्षेत्रों के संसाधन व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने के लिए एक निर्देशिका तैयार की गई है जो जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य मुद्दों और आपदा भेद्यता मूल्यांकन और डीआरआर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के प्रभाव का सामना करने वाले भारत के विभिन्न हिस्सों से सीखे गए पाठों को उजागर करते हुए केस स्टडी और नीति पत्रों का एक संग्रह विकसित किया जा रहा है।



'जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य को समझने के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण : ज्ञान और क्षमता अंतराल का समाधान करना'

क्षेत्रीय परामर्श कार्यशालाओं से झलकियां



चित्र 1



चित्र 2



चित्र 3



चित्र 4

4.3 राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना (एनएडीएमपी)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2009 के अनुसार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए एक राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर रहा है। इसका उद्देश्य रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया की संस्कृति के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी संचालित करके, और समुदाय आधारित रणनीति विकसित करके "कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए एक सुरक्षित और आपदा समुत्थानशील योजना" का निर्माण करना है। वर्ष 2019-20 के दौरान, दो क्षेत्रीय परामर्श कार्यशालाएं और दो कार्य समूह बैठकें आयोजित की गईं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के परिसर में एचआरव्हीसीए पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी जहाँ मंत्रालय के सभी नोडल अधिकारी मौजूद थे। एनएडीएमपी के



प्रक्रिया प्रवाह आरेख

मसौदे पर सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के समक्ष एक प्रस्तुति भी दी गई । सदस्य सचिव और एनडीएमए सदस्यों, की उपस्थिति में योजना पर एक प्रस्तुति दी गई। "भारत में समुत्थानशील कृषि के लिए रोडमैप" पर एक नीति पत्र भी प्रकाशित किया गया था । इस बीच, प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए खाका तैयार किया गया और अब मॉड्यूल 1 के लिए मसौदा पूरा हो गया है। शेष मॉड्यूल प्रक्रिया में हैं।

एनएडीएमपी के कार्य समूह की बैठक और एचआरव्हीसीए परामर्श कार्यशाला से झलक



चित्र 1



चित्र 2



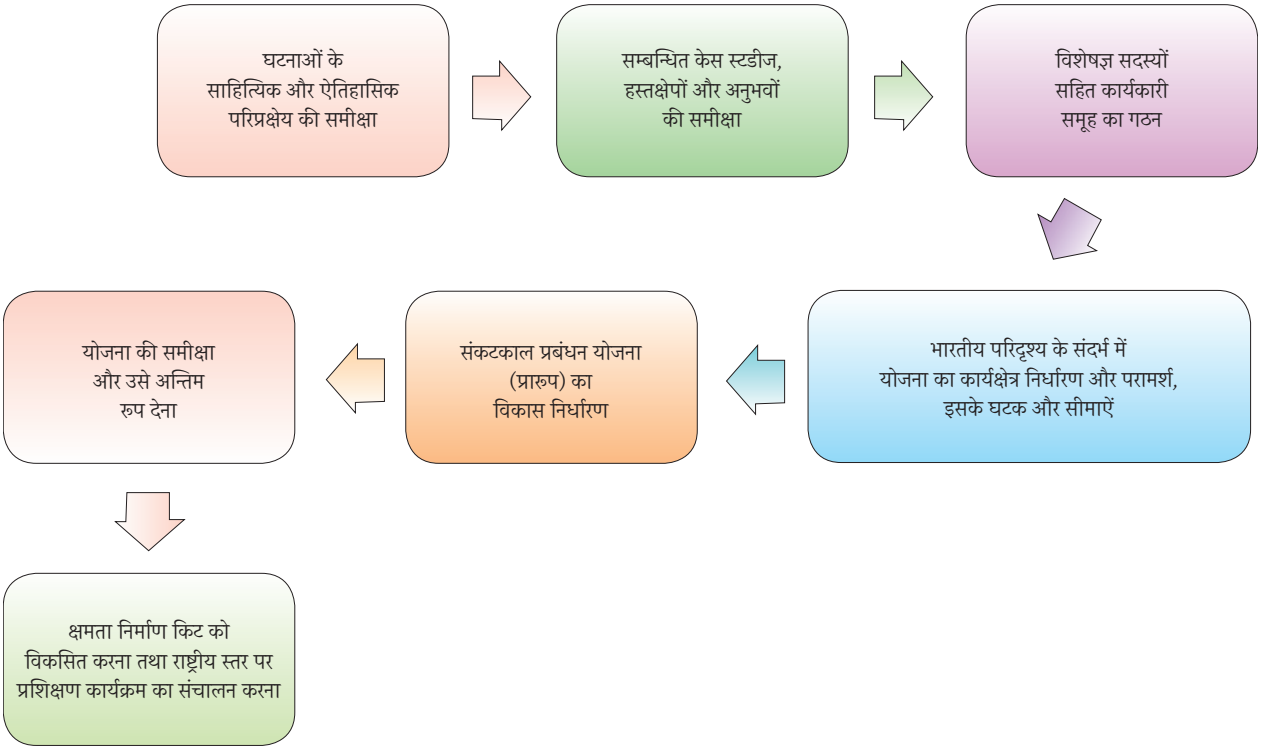
चित्र 3



चित्र 4

4.4 जलाशयों के संदूषण से निपटने के लिए संकट प्रबंधन योजना

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने “सीएमपी-डब्लयूबी” परियोजना को लागू किया है। राष्ट्रीय स्तर पर जलाशयों के अचानक जल प्रदूषण के मुद्दे के समाधान के लिए एक संकट प्रबंधन योजना तैयार की जा रही है। जनवरी-मार्च 2020 की अवधि के दौरान, जल संदूषण संबंधी घटनाओं के साहित्यक और ऐतिहासिक पहलुओं की समीक्षा की गई है। 27 मई 2020 को जलाशयों में आकस्मिक जल संकट आपात स्थितियों के लिए विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को समझने और पहचानने के लिए “जलाशयों के संदूषण के लिए संकट प्रबंधन योजना” पर एक वेब आधारित राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसके अलावा, आने वाले महीनों में प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जाएंगे।



प्रक्रिया प्रवाह आरेख

4.5 बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसी-डीआरआर) इकाई, एनआईडीएम- दक्षिणी परिसर

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय के विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में स्थित, दक्षिणी परिसर, से कार्य कर रहे बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर) केंद्र को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ) के द्वारा दिसंबर 2018 के अंतिम सप्ताह से संयुक्त रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस परियोजना को तीन वर्षों के लिए तीन चरणों में संचालित किए जाने की योजना है।

केंद्र का उद्देश्य बच्चों से संबंधित डेटा प्रबंधन, जोखिम अनुसार कार्य योजना, बाल जोखिम प्रभाव आकलन (सीआरआईए) और आपदा प्रबंधन संस्थान की क्षमता निर्माण के लिए नीतिगत फ्रेम वर्क के लिए राज्यों की सहायता करना है। केंद्र सूखा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बच्चे से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान दे रहा है। यह केंद्र भारत में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) और क्षेत्रीय संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

सीसीडीआरआर केंद्र के प्रमुख घटक, यूनिसेफ के चार डीआरआर लक्ष्यों के अनुसरण में बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रोत्साहन और परामर्श है।

1. बच्चों और महिलाओं के लिए डीआरआर एक राष्ट्रीय और स्थानीय प्राथमिकता है।
2. लड़कियों, लड़कों और महिलाओं के समक्ष आने वाले विभिन्न जोखिमों की पहचान की जाती है और उनका समाधान किया जाता है।

3. लड़कियों, लड़कों और महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित और समुत्थानशील परिस्थितियां।
4. क्षमता विकास के माध्यम से मानवीय तैयारियों, प्रतिक्रिया और रिकवरी प्रक्रिया को मजबूत करना।

4.6 आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारत विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क (आईयूआईएन)

'ह्योगो फ्रेमवर्क फार एक्शन'[1] पर आधारित, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में सुरक्षा और समुत्थानशीलता की संस्कृति का निर्माण करने के लिए 'ज्ञान, नवाचार और शिक्षा को शामिल किया गया था, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाइ फ्रेमवर्क 2015-2030[2] "आपदा जोखिम को समझना" अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में चिन्हित करता है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, अनुसंधान, नागरिक और व्यावसायिक शिक्षा और सभी स्तरों पर प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना, इन्हें इस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण साधनों के रूप में पहचाना गया है। इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के साथ भागीदारी करते हुए, विश्वविद्यालयों और अन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी समुदायों को नवीन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान को बढ़ावा देने, क्षमता विकास को सुविधाजनक बनाने और स्थानीय जोखिमों के निराकरण और सबसे कमजोर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्णय लेने में योगदान देने की परिकल्पना की गई है।

इस नेटवर्क की पृष्ठभूमि माननीय प्रधान मंत्री के 10 बिंदु एजेंडा से उभरी है, जो कि भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में वर्ष 2016 में आयोजित एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान एशियाई देशों के नेताओं के समक्ष उनके द्वारा उल्लिखित किया गया था। माननीय प्रधान मंत्री के 10 बिंदु एजेंडा का बिंदु 6 "भारत में आपदा मुद्दों पर काम करने के लिए विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क विकसित करने" की आवश्यकता पर जोर देता है।

भारत की प्रतिबद्धता और विश्वविद्यालयों और संस्थानों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, एनआईडीएम द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विश्वविद्यालयों और संस्थानों का नेटवर्क(आईयूआईएन-डीआरआर) की स्थापना की जा रही है। इस नेटवर्क में, एनआईडीएम के अलावा, कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और संस्थान आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित संसाधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर काम करने वाले हितधारकों के बड़े समूह आपस में ज्ञान साझा करने के लिए एक साथ आयेंगे। इस नेटवर्क में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ का प्रतिनिधित्व भी होगा।

उद्देश्यः

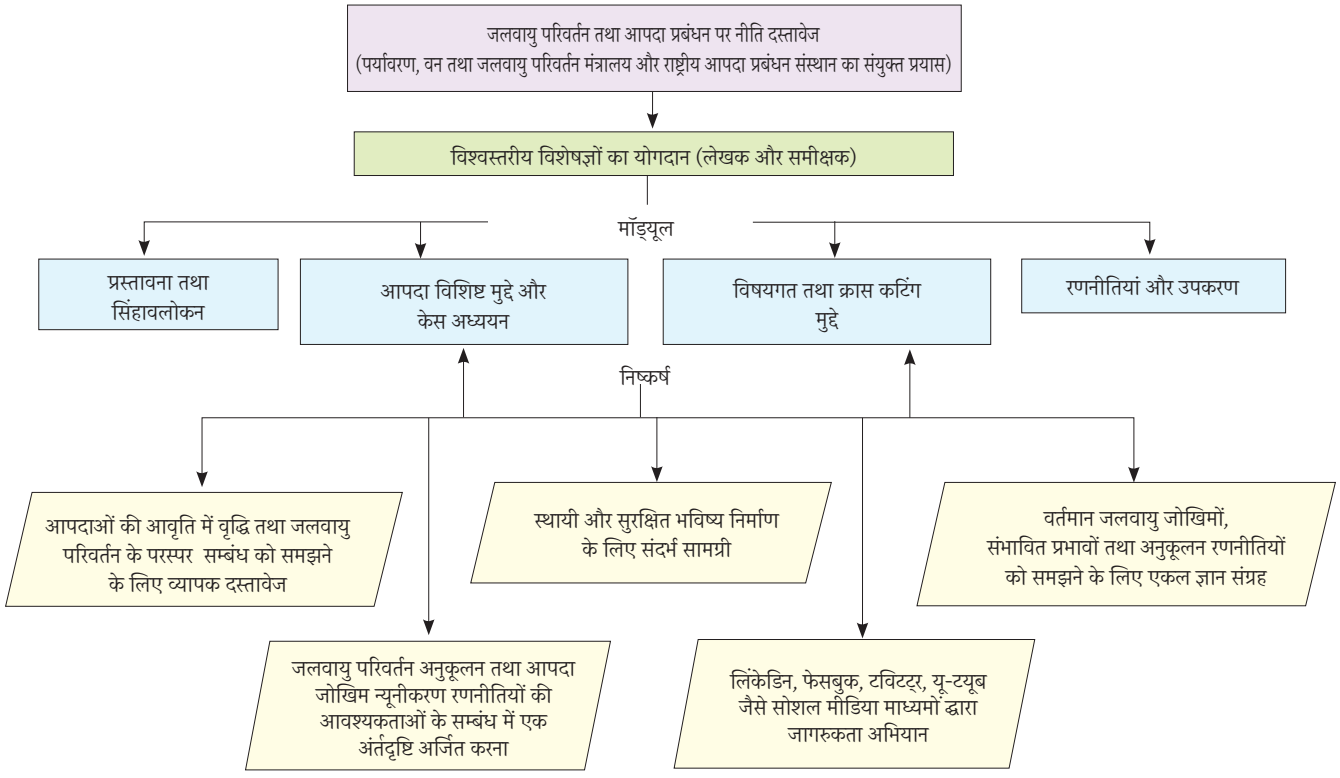
आईयूआईएन -डीआरआर को इन उद्देश्यों के साथ स्थापित किया जा रहा है कि इसके सदस्य

- शिक्षा और अनुसंधान के संचालन, निष्कर्षों को साझा करने और आपदा जोखिमों के प्रभाव को कम करने के तरीके खोजने के लिए निकट सहयोग में काम करेंगे।
- सहयोग स्थापित करने के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, निगमित निकायों और नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर काम करेंगे जो अंततः डीआरआर के लिए समुत्थानशील समुदायों और मजबूत नीतियों को बढ़ावा देंगे।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में कार्यान्वयन-उन्मुख शिक्षा और अनुसंधान के प्रति वचनबद्धता व्यक्त करेंगे।

[1] https://www.undrr.org/we/coordinate/hfa
[2] https://www.undrr.org/we/coordinate/sendai-framework

4.7 जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर नीति दस्तावेज

जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर यह परियोजना नीति दस्तावेज, (पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय-एनआईडीएम) द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जो प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति को गति देने में जलवायु परिवर्तन की भूमिका पर केंद्रित है और इन घटनाओं और जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों को दर्शाता है। "जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर नीति दस्तावेज़" नामक पुस्तक में 29 अध्याय हैं, जिन्हें 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है (1) परिचय और साक्षात्कार (2) आपदा विशिष्ट मुद्दे और मामलों का अध्ययन (3) विषयगत और क्रॉस-कटिंगमुद्दे और (4) रणनीतियाँ और उपकरण (परियोजना फ्रेमवर्क को समझने के लिए नीचे दिए गए आंकड़े देखें) । दुनिया भर से लगभग 50 लेखकों और 20 समीक्षकों ने इसमें योगदान दिया है।



लक्ष्य और उद्देश्य

जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर नीति दस्तावेज का उद्देश्य मौजूदा जलवायु खतरों की पहचान करना, उनसे निपटने के तरीके और इस संदर्भ में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करना है। इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:

- भारत में जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरनाक जोखिम को समझने के प्रति पाठकों को सक्षम बनाना।

- आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि के साथ जलवायु परिवर्तन कैसे संबद्ध है, इसकी जानकारी प्राप्त करने में शोधकर्ताओं की मदद करना।
- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियों को अपनाकर स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिशानिर्देशों को लागू करने में नीति-निर्माताओं की मदद करना।
- जलवायु खतरों से जुड़े जोखिमों को नियंत्रित करने में प्राप्त उपलब्धियों के प्रदर्शन में भारत सरकार की मदद करना।
- दुनिया भर के लेखकों और समीक्षकों की सेवायें लेकर जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के पहलू पर विचारों, विशेषज्ञता और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

प्रमुख परिणाम

- एक ऐसा एकल ज्ञान संग्रह, जिसका उपयोग नीति-निर्माता (नीति कार्यान्वयन के लिए), शोधकर्ता (जलवायु परिवर्तन और आपदा के संबंध को समझने के लिए), भारत सरकार (प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में भारत द्वारा किए गए प्रयासों के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने और इसे प्रदर्शित करने के लिए कर सकती है।)
- इस पुस्तक के चार प्रमुख खंडों का विकास, जिनमें (1) परिचय और सिंहावलोकन (2) आपदा विशिष्ट मुद्दे और केस स्टडी (3) विषयगत और क्रॉस-कटिंग मुद्दे (4) रणनीतियाँ और उपकरण सम्मिलित हैं।
- भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियों के कार्यान्वयन की आवश्यकता को समझने के लिए वर्तमान जलवायु मुद्दों पर कई डोमेन विशेषज्ञों द्वारा व्यापक शोध कार्यों का संग्रह और संकलन।
- जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिमों के बीच पारस्परिक संबंध की विस्तृत व्याख्या; पर्यावरण पर उनके प्रभाव, इन घटनाओं की भेद्यता और सुरक्षित और स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए इन जोखिमों से निपटने के तरीके।

4.8 एनआईडीएम-जेएनयू-आपदा अनुसंधान कार्यक्रम (डीआरपी) आपदा अनुसंधान के लिए विशेष केंद्र (एससीडीआर) 2019-20 के लिए गतिविधियां

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों, सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अकादमिक बैठकों के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के साथ-साथ अकादमिक सामग्री, डेटा और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक जानकारी के आदान-प्रदान के लिए 2015 में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के एक भाग के रूप में, 27 अक्टूबर, 2017 को जेएनयू कैंपस में एमओयू के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशेष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई।

वर्ष 2019-20 के महत्वपूर्ण आयोजन इस प्रकार हैं :

1. **एम.ए.और पी.एच.डी छात्रों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम / कार्यशाला: आपदा अनुसंधान के लिए विशेष केंद्र (एससीडीआर), एनआईडीएम-जेएनयू-डीआरपी, 07 अगस्त, 2019, सभागार, एससीडीआर,जेएनयू, नई दिल्ली**

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान(एनआईडीएम) और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) ने 2015 में शैक्षणिक सामग्री, डेटा इत्यादि के आदान-प्रदान के साथ संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, अंतत: जेएनयू में एक नया अकादमिक अनुसंधान केंद्र 'स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च' (एससीडीआर) के रूप में स्थापित किया गया है और यह बहु-विषयक प्रकृति का है। एनआईडीएम और जेएनयू के बीच एमओयू में परिकल्पित इस विशेष केंद्र की स्थापना जेएनयू में की गई थी और 26 अक्टूबर, 2017 को माननीय राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इस केंद्र की स्थापना आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान की सुविधा के लिए की गई थी। उन्होंने सुझाव दिया कि अनुसंधान की प्रकृति पूर्णतया सामाजिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान के सख्त मूल विषयों तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि उन वैज्ञानिक निष्कर्षों को अवशोषित करने के लिए अपनी सीमाओं और हदों को पार करना होगा जो निर्णय लेने और सामाजिक विज्ञान संवेदनशीलता का समर्थन करते हैं ताकि समुदायों और निर्णय लेने वाली संस्थाओं की ओर इन निष्कर्षों को निर्देशित किया जा सके।



2. आपदा अनुसंधान के लिए विशेष केंद्र, जेएनयू आईएसआईडी (औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान), द्वारा आपदा समुत्थानशील स्मार्ट सिटीज विषय पर आयोजित वैश्विक संगोष्ठी,वसंत कुंज, 4-6 दिसंबर 2019, नई दिल्ली

आपदा अनुसंधान के लिए विशेष केंद्र ने औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान (आईएसआईडी), वसंत कुंज इंस्टी ट्यूशनल एरिया, वसंत कुंज, नई दिल्ली में 4-6 दिसंबर, 2019 के दौरान'आपदा समुत्थानशील स्मार्ट सिटीज़' पर तीन दिवसीय वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी का आयोजन भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया गया था, जो भारत में स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय है। तीन दिवसीय संगोष्ठी में स्मार्ट सिटी मिशन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, यूनेस्को के विशेषज्ञों, उद्योग और दुनिया भर के शिक्षाक्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल करके, स्मार्ट सिटीज़ की प्रधान मंत्री की परिकल्पना को अधिक आपदा समुत्थानशील बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। 100 स्मार्ट शहरों में कोर इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशल समाधान प्रदान करने का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण में व्याप्त अनेक कमियों को दूर करना और शहरी प्रशासन में सुधार करना है।

उद्घाटन समारोह के विशिष्ट अतिथि, पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री और वर्तमान में, बिहार विधान परिषद के सदस्य, प्रोफेसर संजय पासवान ने स्मार्ट शहरों के निर्माण के महत्व पर जोर दिया, जो कि समावेशी, सस्ते, सुलभ, परिवर्तनकारी और सुधारवादी हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी पटना को मिशन मोड में बनाने के लिए बिहार विधान परिषद में आपदा प्रबंधन समिति का गठन करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है, जो कि आपदा समुत्थानशील और सामान्यजन केंद्रित है। चूंकि भारत में ग्रामीण आबादी की तुलना में शहरीकरण तीन गुना बढ़ रहा है, इसलिए आपदा रोधी स्मार्ट शहरों का निर्माण करना महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क में शामिल है। श्री राहुल कपूर, मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, ने आपदा समुत्थानशील जलवायु कुशल-स्मार्ट सिटीज़ के निर्माण के तीन प्रमुख मापदंडों पर चर्चा की : समन्वित शहरी नियोजन,समुत्थानशील अवसंरचना और नागरिक सेवा वितरण के लिए स्मार्ट समाधान (नवीनतम तकनीकों पर आधारित, जैसे वस्तु स्थिति की जानकारी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली, वायु और जल प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसे शहरी मुद्दों के प्रबंधन के लिए नवीन तकनीकें) श्री जीवीवी सरमा, सदस्य सचिव, एनडीएमए, ने अपने वास्तविक अनुभव को साझा करते हुए, इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में वर्तमान आपदा प्रशासन अभी भी ज्यादातर आपदा आने पर राहत के वितरण पर आधारित है। भारत को आपदा पूर्व निवारक और शमन उपायों के लिए आपदा पश्चात् सुदृढ़ विनिर्माण कार्य पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

उद्घाटन समारोह में सूरत नगर निगम के महापौर, श्री जगदीशभाई पटेल, का सूरत के विकास पर उनके सराहनीय कार्य तथा आपदा समुत्थानशील स्मार्ट सिटी के अनुकरणीय निर्माण के लिए, जेएनयू के रजिस्ट्रार, डॉ० प्रमोद कुमार, और श्री मारकस गोडार्ड, अध्यक्ष,नेटेक्सपलो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नेटवर्क-पेरिस द्वारा स्मार्ट सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। सूरत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग में की गई पहल, नदी से गाद निकालने के लिए राज्य और जिला प्रशासन के बीच अंतर एजेंसी नेटवर्क को मजबूत करना, विकेंद्रीकृत प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण द्वारा शहर

में हताहतों की संख्या को कम करने और प्रशासन को मजबूत करने में मदद मिली। प्रौफेसर अमिता सिंह, संस्थापक अध्यक्ष,आपदा अनुसंधान के लिए विशेष केंद्र, ने कहा कि ऐसे परिदृश्य में, जब भारत ने यू एन क्लाइमेट एक्शन शिखर सम्मेलन 2019, न्यूयॉर्क में 'ग्लोबल कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर' को प्रारम्भ करने की पहल का नेतृत्व किया है, ऐसे में ज्ञान के आदान-प्रदान, बेहतर जोखिम पहचान और समुत्थानशीलता निर्माण के लिए ऐसी सांझेदारी स्थापित करने की पहल करना महत्वपूर्ण हो जाता है। हालाँकि, इस पहलू को अभी भी भारतीय स्मार्ट शहरों की विकास नीति में एकीकृत किया जाना है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंडाइ फ्रेमवर्क के लेंस से इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर की खोज इस संगोष्ठी का उद्देश्य रहा।

संगोष्ठी का आयोजन आपदा अनुसंधान के लिए विशेष केंद्र, जेएनयू द्वारा नेटक्सपलो के स्मार्ट सिटीज़ एक्सीलरेटर ग्रुप ऑफ पेरिस, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद(आईसीएसएसआर), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान के सहयोग से किया गया था।



4.9 आधारभूत संरचना (रोहिणी और दक्षिणी परिसर)

4.9.1 नई दिल्ली के रोहिणी में एनआईडीएम के नए परिसर की आधारभूत संरचना के विकास में प्रगति

डीडीए ने भूखंड संख्या 15, ब्लॉक बी, सेक्टर 29 रोहिणी में एनआईडीएम के परिसर की स्थापना के लिए 2.87 हेक्टेयर भूमि आवंटित की । गृह मंत्रालय द्वारा एनआईडीएम के परिसर की स्थापना के लिए 47.70 करोड़ रुपए आबंटित किए गए और एनबीसीसी के माध्यम से कार्य को करने की मंजूरी दी गई।

मार्च 2020 तक कार्य की भौतिक प्रगति इस प्रकार है:

क) प्रशासनिक ब्लॉक- संरचना कार्य पूर्ण।

ख) हॉस्टल ब्लॉक- संरचना कार्य पूर्ण।

ग) निवास, प्रकार II, प्रकार III, प्रकार IV और प्रकार V, प्रकार VI ,संरचना कार्य पूर्ण।

घ) फिनिशिंग का काम, सीवरेज का काम, सड़क का काम और अग्निशमन का काम आदि प्रगति में है। मार्च 2020 तक लगभग 92% भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली गई है।

मॉनिटरिंग कमेटी में प्रो.एके गुप्त, लेफ्टिनेंट कर्नल डीसी वशिष्ठ, श्री सुरेंद्र ठाकुर, परामर्शदाता (प्रशासन और मानव संसाधन), डॉ० अजिंदर वालिया और अभियन्ता जे एन झा एनआईडीएम और अभियन्ता दिनेश कुमार, पूर्व-इंजीनियर इन चीफ और सदस्य, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजिनीयरज़ एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में, एनआईडीएम परिसर के निर्माण की भौतिक प्रगति और निमार्ण गुणवत्ता की निगरानी कर रहे हैं । निगरानी समिति के साथ कार्यकारी निदेशक और संयुक्त निदेशक द्वारा निरीक्षण के दौरान ली गई अद्यतन तस्वीरें निम्नानुसार हैं :





4.9.2 आंध्र प्रदेश में एनआईडीएम दक्षिणी परिसर कीआधारभूत संरचना के विकास की प्रगति

आंध्र प्रदेश सरकार ने एनआईडीएम दक्षिणी परिसर की स्थापना के लिए कोंडापोवाल्लुरु ग्राम, गन्नवरम मंडल कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में 10 एकड़ भूमि आवंटित की। गृह मंत्रालय ने एनआईडीएम परिसर को स्थापित करने के लिए 36.76 करोड़ की राशि स्वीकृत की और एनबीसीसी के माध्यम से कार्य करवाने का अनुमोदन दिया।

मार्च 2020 तक कार्य की भौतिक प्रगति इस प्रकार है:

क) प्रशासनिक ब्लॉक- संरचना निर्माण कार्य पूर्ण।

ख) हॉस्टल ब्लॉक- संरचना निर्माण कार्य पूर्ण।

ग) निवास, प्रकार II, प्रकार III, प्रकार IV और प्रकार V, प्रकार VI , संरचना निर्माण कार्य पूर्ण।

घ) फिनिशिंग कार्य, सीवरेज कार्य, सड़क निर्माण कार्य और अग्निशमन कार्य आदि प्रगति में है।

आरसीसी फुटिंग का काम पूरा हो चुका है और ईंट चिनाई का काम चल रहा है। मार्च 2020 तक निर्माण कार्य में लगभग 75% भौतिक प्रगति हासिल कर ली गई है।

संयुक्त निरीक्षण दल में एनआईडीएम से श्री सुरेंद्र ठाकुर, परामर्शदाता (प्रशासन और मानव संसाधन) अथवा श्री विक्रम गुर्जर, डीसी (प्रशिक्षण) और अभियन्ता जे एन झा, एनडीआरएफ सैकिण्ड-इन-कमांड, एनबीसीसी के अतिरिक्त जीएम और इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियरिंग से एक स्वतंत्र सदस्य के रुप में प्रो० पी.के. रामाराव, एनआईडीएम दक्षिण परिसर के निर्माण कार्य की मात्रा, भौतिक प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी कर रहे हैं । संयुक्त निदेशक के साथ संयुक्त निरीक्षण दल की यात्रा के दौरान ली गई अद्यतन तस्वीरें निम्नानुसार हैं:


Champion



अध्याय 5

ज्ञान प्रबंधन और जागरुकता कार्यकलाप

अध्याय 5: ज्ञान प्रबंधन और जागरुकता कार्यकलाप

5.1 भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)



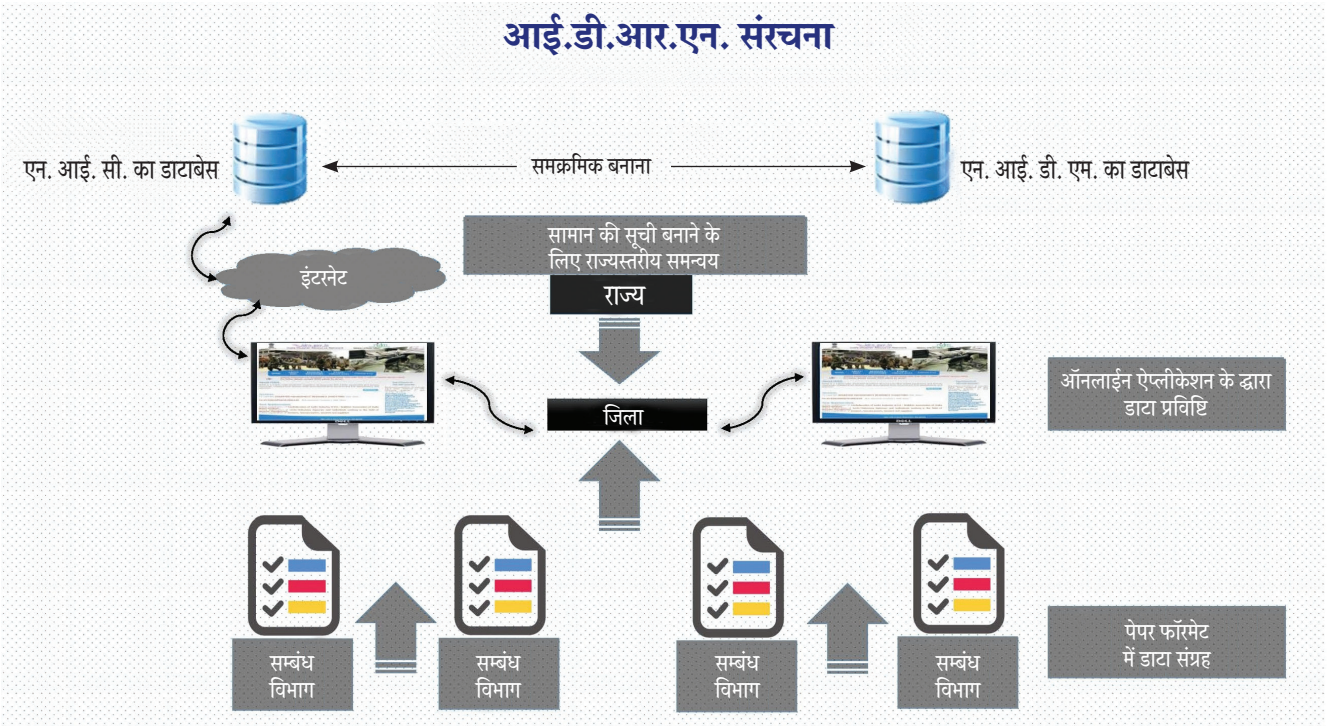
आईडीआरएन की शुरुआत गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार-यूएनडीपी आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2003 में की गई थी ।

आईडीआरएन के राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) को वर्ष 2008 से आईडीआरएन की निगरानी और रख-रखाव का दायित्व सौंपा है ।

आईडीआरएन एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह मानव संसाधन और महत्वपूर्ण सप्लाई के संबंध में आवश्यक सूचना उपलब्ध कराता है, जो जिला स्तर पर संबद्ध विभागों और एजेंसियों के पास उपलब्ध है ।

आई.डी.आर.एन की कार्य प्रणाली

राज्य प्राधिकारियों की भूमिका- आईडीआरएन में आंकड़ो को अघतन करने के लिए राज्य के राहत / आपदा प्रबंधन / एसडीएमए विभाग, डीएम / डीसी से समन्वय करते हैं ।



जिला प्राधिकारियों की भूमिका- जिला स्तर पर आंकड़ो के संग्रह और उन्हें अघतन रूप देने के कार्य को सुगम बनाने के लिए जिला कलेक्टर / मैजिस्ट्रेट प्राधिकृत अधिकारी होता है। आंकड़ों के संग्रह का प्रारूप सभी सम्बद्ध विभागों और एजैंसियों को जिला प्रशासन द्वारा भेजना होता है और एक या दो सप्ताह में उसे एकत्र करना होता है । जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों की तकनीकी सेवाओं का उपयोग करते हुए जिला स्तर पर आंकड़ो की प्रविष्टियां की जानी चाहिए ।

आडीआरएन पोर्टल का उपयोग- आपात स्थिति में कोई भी उपलब्ध संसाधनों के सम्बंध में अघतन जानकारी प्राप्त करने के लिए आईडीआरएन पोर्टल का उपयोग कर सकता है जो कि आपात स्थिति में जान, माल तथा अवसंरचना को होने वाली हानि को कम करने में अत्यधिक सहायक होगा ।

5.2 प्रलेखीकरण और प्रकाशन

सूचना को संसाधन माना जाता है जो संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है । एक परिसंपत्ति के रूप में सूचना का मूल्य तभी बढ़ता है जब कि इसका प्रभावी प्रबंधन किया जाए । एनआईडीएम का एक अधिदेश आपदा प्रबंधन और विकास संबंधी सूचना का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए निरंतर प्रयास करना है ताकि संस्थान के प्रशिक्षण, शोध और परामर्श कार्यकलापों में सहायता की जा सके ।

पुस्तकालय

एनआईडीएम पुस्तकालय द्वारा दी जा रही सेवाएं इस प्रकार हैं:-

- पुस्तकों और पत्रिकाओं तथा अन्य पठन सामग्री की प्राप्ति
- संदर्भ और संदर्भित कार्य

- परिचालन कार्य
- पुस्तकालय स्वचालन

एनआईडीएम पुस्तकालय ओपीएसी: **http://nidm.bestbookbuddies.com** देखें।

ओपीएसी: ऑनलाईन पब्लिक एक्सेस कैटालॉगस

5.3 एनआईडीएम प्रशिक्षु डाटाबेस

प्रत्येक वर्ष एनआईडीएम अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है । सरकार / हितधारकों की मदद के लिए इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षुओं का पूरा ऑनलाईन डाटाबेस रखा गया है ताकि आपदा तैयारी के लिए इन प्रशिक्षुओं की जानकारी रखी जा सके । यह सूचना एनआईडीएम की बेवसाइट URL:**http://nidm.gov.in/trainee.asp** पर 2009 से उपलब्ध है।

5.4 सूचना प्रसार

5.4.1 सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री

संस्थान को आपदा प्रबंधन और संबंधित पहलुओं पर सूचना प्रसार का कार्य सौंपा गया है । इस कार्य को पूरा करने के लिए संस्थान द्वारा नियमित रूप से एक त्रै-मासिक समाचार पत्रिका और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मॉड्यूल आदि प्रकाशित किए जाते हैं । विभिन्न आपदाओं और उनके प्रबंधन पर सूचना और जागरूकता के लिए एनआईडीएम विभिन्न जागरूकता कार्यकलापों और कार्यक्रमों के साथ नियमित रूप से आईईसी सामग्री प्रकाशित करता है। ये दस्तावेज एनआईडीएम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और इन्हें **http://nidm.gov.in/iec.asp** पर देखा जा सकता है । एनआईडीएम द्वारा तैयार की गई आईईसी सामग्री का प्रयोग आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न हितधारकों द्वारा एनआईडीएम को उचित भुगतान के साथ किया जा सकता है और व्यापक प्रसार के लिए इसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है । एनआईडीएम द्वारा तैयार की गई जागरूकता सामग्री का विवरण इस प्रकार है:

i. **आपदा पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन पर राष्ट्रीय कार्यशाला (पीडीएनए)**



चित्र 1: आपदा पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन (पीडीएनए) पर राष्ट्रीय कार्यशाला

आपदा के बाद की आवश्यकताओं का आकलन आपदा पूर्व स्थितियों की त्वरित और कुशल बहाली और आपदा-समुत्थानशील विशेषताओं के साथ पुनर्निर्माण सुनिश्चित करने की जरूरतों को परिभाषित करता है। पीडीएनए आपदा के बाद की जरूरतों के आकलन को सुगम बनाता है, जो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के सभी प्रभावित क्षेत्रों में और साथ ही साथ विश्लेषण के विभिन्न स्तरों पर प्रभावों और मात्रात्मक आकलन के आधार पर होता है। पीडीएनए दीर्घकालिक बहाली और पुनर्निर्माण आवश्यकताओं के आकलन के लिए आपदा प्रभावों का एक एकीकृत, वैज्ञानिक और व्यापक विश्लेषण है। पीडीएनए जोखिमों की संभावना के समक्ष विभिन्न क्षेत्रों में विकास निवेश का निर्धारण करने के लिए एक उपकरण है । विकसित किए गए पीडीएनए उपकरण को सर्वोत्तम वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय पद्धितियों के आधार पर भारत के लिए अनुकूलित किया गया है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया है, जो आपदा प्रभावों और इनके गहन विश्लेषण के आधार पर बहाली और पुनर्निर्माण आवश्यकताओं के व्यापक और वैज्ञानिक मूल्यांकन को सुगम बनायेगा ।

ii. हैंडबुक पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट इंडिया



चित्र 2: हैंडबुक पोस्ट डिजास्टर नीड्स एसेसमेंट

आपदा पश्चात् आवश्यकताओं के आकलन (पीडीएनए) को भारत के लिए सर्वोत्तम वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के आधार पर अनुकूलित किया गया है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया है, जो आपदा के प्रभावों और परिणामों के गहन विश्लेषण के आधार पर बहाली और पुनर्निर्माण की जरूरतों के व्यापक और वैज्ञानिक मूल्यांकन को सुगम बनायेगा । यह पद्धति भविष्य की घटनाओं के प्रति समुत्थानीशीलता सृजन के साथ-साथ आपदा के बाद बहाली और पुनर्निर्माण को आपदा प्रबंधन के एक अलग और अतिरिक्त क्षेत्र के रूप में स्वीकार करती है । इसके अलावा, मौजूदा समय में राहत सहायता केवल प्रभावित आबादी के एक हिस्से को प्रदान की जाती है, अर्थात ज्यादातर प्रभावित आबादी के गरीब वर्ग को और अर्थव्यवस्था के सभी प्रभावित क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, जो कि एक त्वरित बहाली के लिए अनुकूल नहीं है । इसके अतिरिक्त, प्रभावित परिवारों के लिए प्रतिक्रिया सहायता की मात्रा स्पष्ट रूप से नष्ट परिसंपत्तियों के पुनर्निमाण के लिए अपर्याप्त है। पुनर्निर्माण के लिए पूंजी के अन्य स्रोतों के अभाव में, लोग अपने घरों और अन्य परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण में गुणवत्ता के निचले मानकों को अपनाते हैं और अपर्याप्त निर्माण सामग्री का उपयोग करते हैं जिसके परिणामस्वरूप आपदा पश्चात् जोखिम कम होने की अपेक्षा और बढ़ जाता है।

iii. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर, पोस्ट डिजास्टर नीड्स एसेसमेंट इंडिया

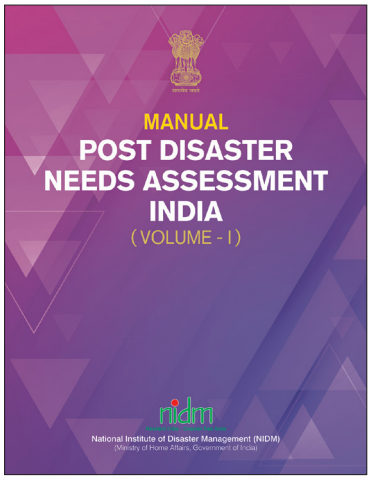


चित्र 3: स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर, पोस्ट डिजास्टर नीड्स एसेसमेंट इंडिया

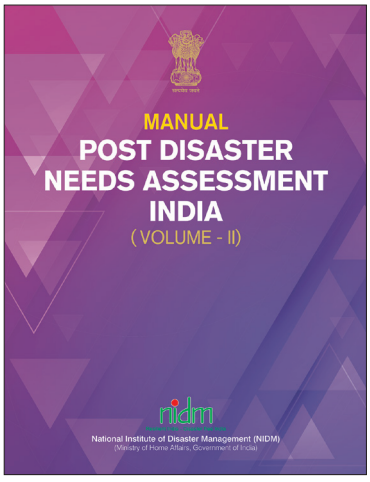
इस मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा विकसित पीडीएनए इंडिया टूल्स के अनुसार आपदा के बाद आवश्यकताओं के आकलन के लिए एक व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण रखने के लिए राज्यों के लिए एक मानक तंत्र स्थापित करना है । इसलिए, यह एसओपी, राज्य और उसकी एजेंसियों को आपदा के पश्चात् आवश्यकताओं के मूल्यांकन (पीडीएनए) और बेहतर ढंग से पुर्ननिर्माण कार्यों के लिए एक बहाली और पुनर्निर्माण योजना विकसित करने में मार्गदर्शन करेगा । राष्ट्रीय एजेंसियों, विशेष रूप से आपदा प्रबंधन से सम्बद्ध नोडल मंत्रालयों के साथ-साथ पीडीएनए में राज्य की सहायता करने और आपदा पश्चात् बहाली और पुनर्निर्माण गतिविधियों में रुचि रखने वाले विकास भागीदारों का भी इस एसओपी द्वारा मार्ग दर्शन किया जाएगा । इस एसओपी का उद्देश्य विभिन्न राज्यों को दिशानिर्देशों का एक ऐसा स्पष्ट सेट प्रदान करना है, जो भारत में एक प्राकृतिक आपदा घटित होने के बाद आपदा पश्चात् आवश्यकताओं के आकलन के लिए मार्ग-दर्शन दे सके । यह एसओपी आपदा पश्चात् आपातकालीन राहत और प्रतिक्रिया के लिए तेजी से मूल्यांकन सम्बंधी किसी भी वर्तमान प्रोटोकॉल को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं है ।

iv. मैनुअल : पोस्ट डिजास्टर नीड्स एसेसमेंट इंडिया (वॉल्यूम- I) और (वॉल्यूम- II)

आपदा के प्रभावों का आकलन नीचे से ऊपर तक एक समग्र दृष्टिकोण में करने की आवश्यकता है जिसमें भौतिक, टिकाऊ संपत्तियों के विनाश के मूल्य का अनुमान तथा आर्थिक और सामाजिक गतिविधि के सभी प्रभावित क्षेत्रों में उत्पादन प्रवाह के आपदा-प्रेरित विघटन का मूल्यांकन और तत्पश्चात् उनका संकलन शामिल हैं, ताकि कुल आपदा प्रभावों और परिणामों का पता लगाया जा सके । आपदा प्रभाव और आपदा-पश्चात् बहाली संबंधी आवश्यकताओं के समग्र दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुवर्ती वैध एकत्रीकरण को सुनिश्चित किया जा सके । विभिन्न शब्दों का उपयोग करते हुए, आर्थिक और सामाजिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों को समान सुसंगत प्रक्रिया का पालन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुवर्ती प्रभाव विश्लेषण और आवश्यकता सम्बंधी आकलन पूर्णतया मान्य रहे ।

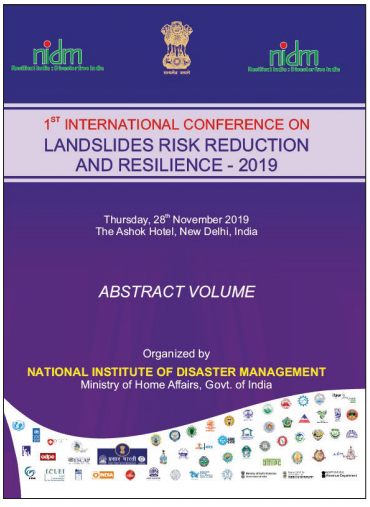


चित्र 4: मैनुअल : पोस्ट डिजास्टर नीड्स एसेसमेंट इंडिया (वॉल्यूम-I)



चित्र 5: मैनुअल : पोस्ट डिजास्टर नीड्स एसेसमेंट इंडिया (वॉल्यूम-II)

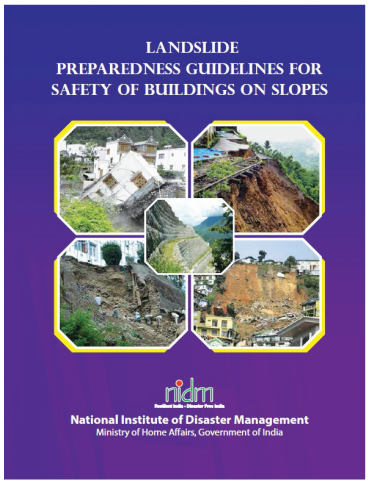
v. एबस्ट्रैक्ट वाल्यूम



चित्र 6: एबस्ट्रैक्ट वॉल्यूम

भूस्खलन ऐसे संभावित खतरों में से एक है जो समुदाय, मानव बस्तियों, पशुधन, आजीविका और पर्यावरण पर विनाशकारी आपदाओं और विध्वंस का कारण बनता है, जिससे व्यापक नुकसान होता है और संचयी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि होती है । भूस्खलन से होने वाले आर्थिक नुकसान न केवल इमारतों, सड़कों, रेलवे, पुलों, बांधों, संचार प्रणालियों और बंदरगाहों जैसी संरचनाओं और बुनियादी ढांचे की तबाही से ही जुड़े हैं, बल्कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को भी हानि पहुंचाते हैं जो क्षेत्रीय निवासियों के लिए अमूल्य और अपूरणीय धरोहर होते हैं । विनाशकारी घटना में व्यापक परिमाण और प्रकार होते हैं जो अन्य आपदाओं जैसे भूकंप, अभूतपूर्व वर्षा, वनाग्नि, चक्रवात, बाढ़, बादल फटने और पहाड़ियों की अनियमित कटाई, कमजोर ढलानों पर ईमारतों और सड़कों का बेरतरतीब निर्माण और खनन जैसी मानवजनित गतिविधियों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं ।

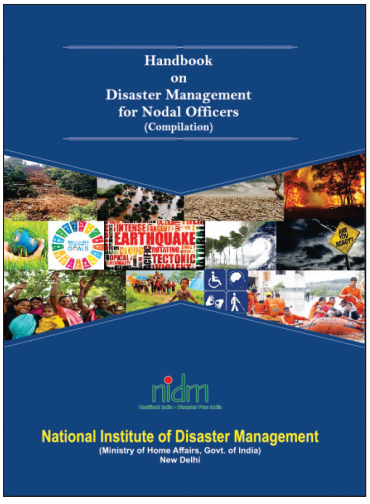
vii. लैण्डस्लाइड प्रिपेयरडनैस गाईडलाइन्स फार सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स ऑन स्लोपस



चित्र 7: लैण्डस्लाइड प्रिपेयरडनैस गाईडलाइन्स फार सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स ऑन स्लोपस

भूस्खलन (लैंडस्लाइड) शब्द का उल्लेख तब किया जाता है, जब चट्टान, मलबे या पृथ्वी के द्रव्यमान का द्वारा निमिर्त ढलान गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में और विभिन्न कारकों द्वारा उत्प्रेरित होकर नीचे और बाहर की ओर खिसकने लगती है । उत्तर और उत्तर-पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और विंध्य भारत में भूस्खलन सबसे अधिक व्याप्त होने वाला खतरा है । यह मानव जीवन को बड़े पैमाने पर लील लेता है और पर्यावरण, संसाधनों के बुनियादी ढांचे और सेवाओं को नुकसान के अलावा हर साल भारी आर्थिक हानि का कारण भी बनता है । भूस्खलन की घटनाओं और प्रभावों को कम करना समय की जरूरत है । भूस्खलन ज्यादातर अस्थिर ढलान वाले क्षेत्रों में होते हैं अर्थात्, एक ऐसी सतह जिसका एक छोर दूसरे छोर से उच्च स्तर पर होता है ।

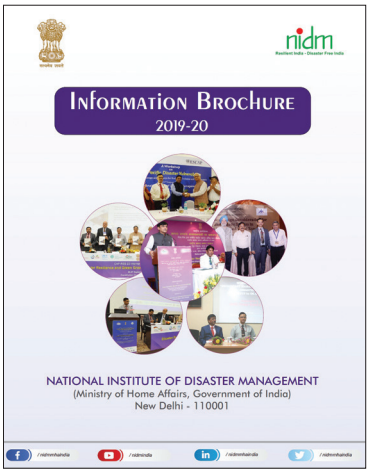
viii. हैंडबुक ऑन डिजास्टर मैनेजमैंट फॉर नोडल ऑफिसरस (कम्पायलेशन)



चित्र 8: हैंडबुक ऑन डिजास्टर मैनेजमैंट फॉर नोडल ऑफिसरस (कम्पायलेशन)

आपदा अचानक आई किसी विनाशकारी घटना का परिणाम होती है जो समाज या समुदाय के सामान्य कार्य को इस सीमा तक गंभीर रूप से बाधित करती है कि वह बाहरी मदद के बिना वापस अपने पैरों पर वापस खड़ा नहीं हो सकता । आपदा केवल एक घटना का घटित होना ही नहीं है जैसे भूकंप, बाढ़, लड़ाई-झगड़ा, स्वास्थ्य महामारी या कोई औद्योगिक दुर्घटना; यदि मानव आबादी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है तो उसे आपदा का आना कहा जाता है । यह एक ऐसा घटनाक्रम है कि आपदाएं लोगों के जीवन, संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती हैं और लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को नष्ट कर सकती हैं । आपदा एक खतरे के समक्ष लोगों के एक समूह को असुरक्षित रूप में लाकर खड़ा कर देती है, जिससे समाज के कामकाज में गंभीर रुकावट आती है और इससे जान, माल, आर्थिक या पर्यावरणीय हानि होती हैं जो प्रभावित समुदाय या समाज के वहन करने की क्षमता से अधिक हो जाती है । यह खतरों और भेद्यता के संयोजन से होता है जो जोखिम के संभावित नकारात्मक परिणामों को कम करने की समाज की क्षमता से अधिक होते हैं ।

ix. एनआईडीएम (इन्फारमेशन ब्रॉचर) सूचना विवरणिका 2019-20



चित्र 9: एनआईडीएम (इन्फारमेशन ब्रॉचर) सूचना विवरणिका 2019-20

एनआईडीएम सूचना विवरणिका संस्थान के बारे में संक्षिप्त जानकारी, संस्थान की प्रबंधन संरचना, परिकल्पना और मिशन, इसके कार्यों, प्रशिक्षण के प्रकार और एनआईडीएम की विभिन्न अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी देती है ।

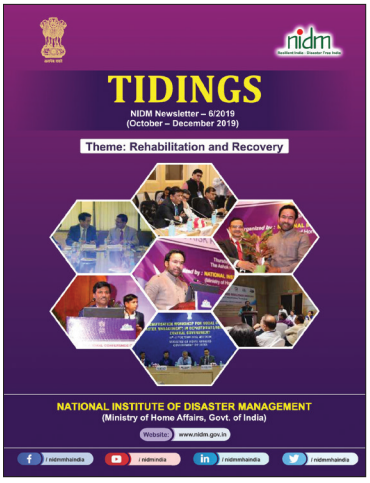
x. वार्षिक रिपोर्ट 2018-19



चित्र 10:
वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

एनआईडीएम की वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट अंग्रेजी और हिंदी दोनों में भाषाओं में प्रकाशित की गई है । इस रिपोर्ट में संस्थान की परिकल्पना, मिशन, अधिदेश, संरचना, कार्य और मुख्य उपलब्धियों की जानकारी दी गई है । रिपोर्ट में आठ अध्याय, नामत: सिंहावलोकन, संगठनात्मक व्यवस्था, प्रशिक्षण कार्यक्रम, परियोजनाएं, ज्ञान प्रबंधन और जागरूकता कार्यकलाप, मुख्य कार्यक्रम / कार्यशालाएं / सम्मेलन / सेमिनार, बैठकें और अन्य कार्यकलाप, वित्त और लेखा के अतिरिक्त प्रशिक्षण / प्रशिक्षुओं की संख्या, प्रशिक्षण के प्रकार आदि के संबंध में किए गए कार्यकलापों और प्राप्त प्रगति की जानकारी दी गई है । ये उपलब्धियां नक्शों, चार्ट और चित्र के रूप में भौगोलिक, प्रतीकात्मक और कालिक प्रवृतियां के रूप में दर्शायी गई हैं । इसमें पांच अनुबंध हैं जिनमें एनआईडीएम परिसर में और परिसर से बाहर आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत सूची, शासी परिषद के सदस्यों की सूची आदि दी गई है ।

xi. समाचार पत्रिका



चित्र 11: एनआईडीएम
समाचार पत्रिका

एनआईडीएम की समाचार पत्रिका "टाइडिंग्स" त्रैमासिक रूप से प्रकाशित की जाती है । इसमें एनआईडीएम द्वारा नियमित रूप से आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनार और कार्यशालाओं की सिफारिशें प्रकाशित की जाती हैं । आने वाले महीनों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पहले से प्रचार देने के अलावा इस समाचार पत्रिका में संकाय विकास, सफलता की कहानियां, दौरों और प्रतिनिधिमंडलों आदि के संबंध में समाचार प्रकाशित किए जाते हैं ।

अध्याय 6

मुख्य आयोजन कार्यशालाएं/ सम्मेलन/ सेमिनार और बैठकें

अध्याय 6: मुख्य आयोजन/कार्यशालाएं/सम्मेलन/सेमिनार और बैठकें

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि के दौरान एनआईडीएम प्रशिक्षण कैलेंडर में सूचीबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा, अन्य सम्पन्न गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं।

6.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विश्वविद्यालय नेटवर्क पर परामर्श कार्यशाला, 5-6 अप्रैल 2019, नई दिल्ली



चित्र 1: आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विश्वविद्यालय नेटवर्क पर परामर्श कार्यशाला

दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एएमसीडीआरआर) 2016 में, माननीय प्रधान मंत्री ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए उनके द्वारा रखे गए 10 एजेंडा बिंदुओं में से एक के रूप में विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया । इस संदर्भ में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'यूएनआईएसडीआर' और केयो विश्वविद्यालय, जापान के साथ संयुक्त रूप से, 5-6 अप्रैल 2019 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए यूनिवर्सिटी नेटवर्क पर परामर्शदात्री कार्यशाला का आयोजन किया । इसमें कई विश्वविद्यालयों ने, एक महत्वपूर्ण हितधारक समूह के रूप

में इसमें भाग लिया, योगदान दिया तथा आपदा प्रबंधन अध्ययन, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, शिक्षक और नीति समर्थन सम्बंधी कार्रवाई बिंदुओं को निर्धारित किया । कार्यशाला के दौरान हुए विचार-विमर्श में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विश्वविद्यालय नेटवर्क की आवश्यकता के सम्बंध में विभिन्न विशेषज्ञों को एक साथ बैठकर संवाद करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया ।

रोजगार क्षमता की आम चुनौती के अलावा, विश्वविद्यालयों द्वारा अध्ययन सामग्री की कमी और क्षेत्रीय भाषा में इसके अनुवाद की चुनौती, सरकार और शिक्षाविदों के बीच, शिक्षाविदों की आवश्यकता को लेकर संवाद का अभाव, प्रशिक्षित संकाय का अभाव और प्रशासनिक बाधाएं, जिनका विश्वविद्यालयों में शिक्षाविदों को एक नया पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सामना करना पड़ता है, का भी उल्लेख किया । कार्यशाला के सदस्यों का यह मानना था कि ऐसे नेटवर्क की स्थापना संस्थानों और संकाय सदस्यों के बीच सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के अंतर को कम करने में मदद कर सकती है, और साथ ही यह विश्वविद्यालयों के बीच सूचना, जानकारी और आंकड़ो के आदान-प्रदान में सहायक होने के साथ-साथ ऐसे नेटवर्क से विशेषज्ञों का एक समूह विकसित हो सकता है तथा इससे विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त शोध कार्यक्रमों में भी वृद्धि हो सकती है ।

6.2 आपदा प्रबंधन योजना पर प्रशिक्षण कार्यशाला, 23 मई 2019

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने नई दिल्ली में 23 मई 2019 को खान मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से "आपदा प्रबंधन" पर एक राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के कुल 10 अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसका उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता (डीआरआर एंड आर) के बारे में बेहतर समझ विकसित करना, देश में आपदा प्रबंधन पर प्रासंगिक अधिनियम, नीति, योजना, दिशानिर्देश और प्रमाणिक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के बारे में जानकारी प्राप्त



चित्र 2 : आपदा प्रबंधन योजना पर प्रशिक्षण कार्यशाला

करना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और सतत विकास सम्बंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और घोषणाओं के बारे में जानकारी हासिल करना, आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण सम्बंधी कार्यात्मक और भौगोलिक व्यवस्थाओं के लिए गतिविधियों की शुरुआत करना तथा आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सहयोग और

सुदृढ़ीकरण तंत्रों पर चर्चा करना था । कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा मंत्रालयों / विभागों / संगठनों द्वारा आपदा प्रबंधन योजना की रूपरेखा पर चर्चा की गई।

6.3 बच्चों के लिए राष्ट्रीय आपदा तैयारी कार्यशाला, 24 मई 2019, आंध्र प्रदेश



चित्र 3: बच्चों के लिए राष्ट्रीय आपदा तैयारी कार्यशाला

बाल केन्द्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण केन्द्र (सीसीडीआरआर) और यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड (यूनिसेफ) के सहयोग से एनआईडीएम ने 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को परिवर्तन का ध्वज वाहक मानकर, उनके लिए एनआईडीएम साउथ कैंपस, बापटला में 24 मई 2019 को आधे दिन की "आपदा तैयारी कार्यशाला" का आयोजन किया । कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की आपदाओं और आपात स्थितियों के प्रति बच्चों को जागरूक करना और तैयार करना था और उनसे उनकी क्षेत्रीय जरूरतों के बारे में जानना भी था। कार्यशाला से पहले, केंद्र ने आपदा तैयारियों पर एक 'चिल्ड्रन एक्टिविटी बुक' तैयार की थी । कार्यशाला के दौरान गतिविधि पुस्तक में प्रयुक्त कार्यप्रणाली की प्रभावशीलता का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया ।

6.4 कार्यकारी समूह की बैठक, 17 जून 2019

भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थओं के साथ समझौता ज्ञापन को अन्तिम रूप देने के लिए एक कार्यकारी समूह की स्थापना की गई जिसमें एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम के प्रोफेसर संतोष कुमार, टिस्स (TISS) से डा० जानकी ओधारिया, नेहु (NEHU) से प्रो० देवेश वालिया और आईआईटी रुढ़की से प्रो० महुआ मुखर्जी शामिल थी । संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन) इस समूह में विशेष अतिथि के रूप में आमन्त्रित थे । 17 जून, 2019 को कार्यकारी समूह की बैठक में आईयूआईएनडीआरआर – एनआईडीएम के बीच समझौता ज्ञापन को अन्तिम रूप दिया गया ।

6.5 भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस) अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन कार्यक्रम, 24 जून 2019, पुणे

नेशनल एकेडमी ऑफ डिफेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रीजनल ट्रेनिंग सेंटर, भारत सरकार, पुणे के अनुरोध पर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर एक दिवसीय विषयबोध कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यशाला का आयोजन 24 जून 2019 को पुणे में किया गया । कार्यशाला में 28 अधिकारियों ने भाग लिया । मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल ने नेशनल एकेडमी ऑफ डिफेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (एनएडीएफएम), पुणे के निदेशक के साथ उद्घाटन और समापन भाषण दिया । कार्यक्रम की रिपोर्ट 'एनएडीएफएम' द्वारा 'एनआईडीएम' के साथ साझा की गई ।

6.6 राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना पर क्षेत्रीय परामर्शदात्री कार्यशाला, 12 जुलाई 2019 एनआईडीएम, नई दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) आपदाओं और मौसम की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए कृषक समुदाय की समुत्थानशीलता को मजबूत करने के उद्देश्य से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए एक राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना (एनएडीएमपी) विकसित कर रहा है । योजना में एचआरवीसीए गतिविधियां, रोकथाम के घटक, शमन, प्रतिक्रिया और रिकवरी शामिल हैं, जिसके लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है, जिसे आगे विकसित किया जाना है । इस संदर्भ में, 12 जुलाई 2019



चित्र 4 : राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना पर क्षेत्रीय परामर्शदात्री कार्यशाला

को कॉन्फ्रेंस हॉल, द्वितीय तल एनडीसीसी बिल्डिंग, एनआईडीएम, नई दिल्ली में एक अर्ध दिवसीय क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन डीएम योजना के कार्यक्षेत्र, इसकी रूपरेखा, कार्यप्रणाली तथा खतरों के जोखिम सम्बंधी भेद्यता विश्लेषण सम्बन्धी टैम्पलेट पर चर्चा के लिए किया गया था ।

परामर्श कार्यशाला का उद्देश्य कृषि, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी एजेंसियों, वैज्ञानिक / शैक्षणिक / अनुसंधान संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के विशेषज्ञों के बीच ज्ञान साझा करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना था। कार्यशाला राष्ट्रीय स्तर पर कृषि क्षेत्रीय परिदृश्य और आपदा जोखिम के बारे में बेहतर समझ विकसित करने, 'एनएडीएमपी' के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को परिभाषित करने, राष्ट्रीय स्तर पर खतरों-जोखिम, भेद्यता और क्षमता का आकलन करने के लिए एक व्यावहारिक खाका / रूपरेखा विकसित करने और क्षमता सम्बन्धी आवश्यकताओं की बेहतर समझ विकसित करने के लिए आयोजित की गई ।

6.7 जलवायु समुत्थानशीलता के लिए प्रकृति आधारित समाधान: भारतीय मैंग्रोव का भविष्य: पर राष्ट्रीय परामर्शदात्री कार्यशाला, 5 अगस्त 2019 'वाईएमसीए', नई दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, के जलवायु समुत्थानशीलता में उत्कृष्टता के लिए केन्द्र (सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलियैंस) ने जापान के इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट स्ट्रेटजीज़ (आईजीईएस), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून; काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआईआर), नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर और 'आईयूसीएन' कमिशन ऑन इकोसिस्टम मैनेजमेंट (सीईएम) के सहयोग से 5 अगस्त 2019 को 'वायएमसीए'



चित्र 5 : जलवायु समुत्थानशीलता के लिए प्रकृति आधारित समाधान: भारतीय मैंग्रोव का भविष्य: विषय पर राष्ट्रीय परामर्शदात्री कार्यशाला

ऑडिटोरियम, दिल्ली में "जलवायु समुत्थानशीलता के लिए प्रकृति आधारित समाधान:" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया । कार्यशाला का उद्देश्य भारतीय मैंग्रोव पर विशेष ध्यान देने के साथ जलवायु समुत्थानशीलता और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रकृति आधारित समाधान के अवसरों और चुनौतियों को समझना था । इस कार्यक्रम ने शोधकर्ताओं, पेशेवरों और प्रबंधकों को एक जगह पर लाकर बहुहितधारकों में परस्पर संवाद के लिए एक मंच प्रदान किया । यूनेस्को 'सीटूसी', 'डब्लयूआईआई', 'आईजीईएस' (टोक्यो विश्वविद्यालय, जापान), 'आईसीयूएन', 'सीएसआईआर-एनईईआरआई', एकीकृत तटीय प्रबंधन सोसायटी (सिकोम-एमओईएफ और सीसी), 'एनडीएमए', 'डब्लयूटीआई', 'डब्लयूएफएफ-इंडिया', 'टीईआरआई-एसएएस', आईआईटी मुम्बई के प्रतिनिधियों सहित लगभग 30 प्रतिभागियों ने कार्यशाला के दौरान चर्चा में भाग लेकर सक्रिय रूप से योगदान दिया ।

6.8 एम.ए. और पीएचडी छात्रों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम / कार्यशाला : आपदा अनुसंधान के लिए विशेष केंन्द्र (एससीडीआर), एनआईडीएम-जेएनयू-डीआरपी, 07 अगस्त 2019, एससीडीआर, ऑडिटोरियम, जेएनयू, नई दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान(एनआईडीएम) और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) ने 2015 में शैक्षिक सामग्री, आंकड़ों इत्यादि के आदान-प्रदान के साथ संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों के आयोजन के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए । इसके अतिरिक्त, जेएनयू में एक नया अकादमिक अनुसंधान केंद्र, 'स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च' (एससीडीआर) के रूप में स्थापित किया गया है और यह केन्द्र बहुविषयक केन्द्र के रूप में कार्य करेगा । एनआईडीएम और जेएनयू के बीच एमओयू में परिकल्पित इस विशेष केंद्र की स्थापना



चित्र 6 : एम.ए. और पीएचडी के छात्रों के लिए प्रबोधन कार्यशाला

जेएनयू में की गई थी और 26 अक्टूबर 2017 को माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस केंद्र की स्थापना आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान को सुगम बनाने के लिए की गई थी और यह सुझाव भी दिया गया था कि अनुसंधान की प्रकृति सामाजिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान के मूल विषयों तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि इसका उद्देश्य वैज्ञानिक निष्कर्षों को अवशोषित करने के लिए अपनी सीमाओं को पार करते हुए निर्णय लेने और सामाजिक विज्ञान संवेदनाओं को तथा इन निष्कर्षों को उन समुदायों और संस्थानों तक पहुँचाना होगा जो इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभाते हैं ।

6.9 आपदा जोखिम प्रबंधन पर कार्यशाला, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय़, 8 अगस्त 2019, नई दिल्ली

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सम्मेलन हॉल में 8 अगस्त 2019 को एक प्रबोधन कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला का उद्देश्य एनसीआर क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन के पहलुओं के बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करना और उन खतरों पर विशेष ध्यान देना था जो मंत्रालय और इसके प्रतिष्ठानों के लिए आपदाएं पैदा कर सकते हैं । इस कार्यशाला में 60 प्रतिभागी शामिल हुए, जिसमें विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी



चित्र 7 : आपदा जोखिम प्रबंधन पर कार्यशाला

सम्मिलित थे जो विभिन्न प्रभागों का प्रतिनिधित्व करते हुए कार्यक्रम में शामिल हुए । अधिकांश प्रतिभागियों को मंत्रालय के भीतर आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यकताओं के बारे में अच्छी जानकारी थी ।

6.10 "एशिया-पैसिफिक डिजास्टर वल्नरेबिलिटी : द डिजास्टर रिस्कस्केप एंड पाथवेज फॉर रैजिलियैंस, इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट" विषय पर कार्यशाला, 23 अगस्त 2019, होटल ताज एंबेसडर, नई दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान(एनआईडीएम) ने यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक (यूनेस्केप) के साथ मिलकर 'एशिया-पैसिफिक डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, द डिजास्टर रिस्कस्पेस एंड पाथवेज फॉर, इंक्लूजन एंड



चित्र 8 : "एशिया-पैसिफिक डिजास्टर वल्नरेबिलिटी: द डिजास्टर रिस्कस्केप एंड पाथवेज फॉर रैजिलियैंस, इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट" विषय पर कार्यशाला

एंपावरमेंट' विषय पर एक कार्यशाला 23 अगस्त 2019 को नई दिल्ली के होटल ताज एंबेसडर में आयोजित की । कार्यशाला में लगभग 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों को गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, तथा जलवायु परिवर्तन, तेजी से बढ़ते शहरीकरण और पर्यावरणीय गिरावट के कारण इन आपदाओं की आवृत्ति, और विषमता में निरंतर वृद्धि हो रही है । इस क्षेत्र के कई देश एक ऐसे शिखर बिंदु तक पहुंच सकते हैं, जहां आपदा जोखिम की गंभीरता, उनकी प्रतिक्रिया क्षमता से अधिक होगी ।

एशिया-पैसिफिक डिजास्टर रिपोर्ट 2019 ने आपदा 'रिस्कस्केप' में नुकसान के स्तर का आकलन किया और उन राशियों का अनुमान लगाया, जिन्हें संबंधित देशों को बढ़ते आपदा जोखिमों से बचने के लिए निवेश करने की आवश्यकता होगी, जबकि समुत्थानशीलता के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है । रिपोर्ट में उन राशियों को दिखाया गया है जो उस क्षति के समक्ष छोटी पड़ जाती है, जितनी हानि यह देश वर्तमान में आपदाओं के कारण झेल रहे हैं । इसी तरह, रिपोर्ट में यह पता लगाया गया कि नीतिगत हस्तक्षेपों में सबसे गरीब और सबसे कमजोर समूहों को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए व्यापक डेटा और डिजिटल पहचान जैसी उभरती हुई तकनीकों का उपयोग कैसे किया जा सकता है । रिपोर्ट में क्षेत्रीय नीति क्रिया कलापों को भी प्रस्तावित किया गया है । इन सभी पहलुओं पर इस कार्यशाला में चर्चा की गई ।

6.11 चक्रवात फनी के प्रबंधन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला; सीखे गए सबक और आगे का रास्ता, 26-28 अगस्त 2019, ओडिशा

'एनआईडीएम' ने 26-28 अगस्त, 2019 को 'ओएसडीएमए' के सहयोग से तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया । 300 प्रतिभागियों ने 'लैसनस लर्नट' वर्कशॉप में तीनों दिन भाग लिया । जिला प्रशासन के सभी सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ इसमें खोज तथा बचाव दलों जैसे 'एनडीआरएफ', 'एसडीआरएफ', सिविल डिफैंस, 'ओडीआरएएफ' और अंतिम रूप से 'एनजीओ'/ 'आईएनजीओ' ने इस कार्यशाला में भाग लिया । सभी हितधारकों ने चक्रवात 'फनी' के प्रति उनकी प्रतिक्रिया, जिन चुनौतियों का उन्होनें सामना किया, उससे क्या सबक सीखा और भविष्य में आपदाओं का सामना करने के लिए तैयार की गई कार्य योजना के सम्बंध में अपने अनुभवों को साझा किया । 'फनी' चक्रवात के प्रलेखन और अनुभव पूरे राज्य में जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन रणनीतियों को ढालने और मजबूत करने में मदद कर सकते हैं और यह अन्य राज्यों को भी उनकी सुधार प्रक्रिया में मदद कर सकते है ।



चित्र 9 : चक्रवात फनी के प्रबंधन पर राज्य स्तरीय

'फनी' चक्रवात के बाद, जेन सेट्स, मशीनों और गैंगमैन की माँग आपदा से निपटने में संलग्न विभागों और हितधारकों में बहुत बढ़ गई । प्रत्येक क्षेत्र की कार्ययोजना स्वाभाविक रूप से तदनुसार तैयार की जाएगी, हालांकि यह भविष्य में आपदाओं का सामना करने के लिए प्रासंगिक है, लेकिन भविष्य की आपदाओं का मुकाबला करने में बेहतर समुत्थानशीलता सुनिश्चित करने के लिए अतीत में या 'फनी' चक्रवात के दौरान समक्ष आये अनदेखे जोखिमों का निराकरण भी महत्वपूर्ण है । इस कार्यशाला में विकलांगों, वृद्धों, महिलाओं, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के आपदा प्रतिक्रिया में समायोजन पर भी व्यापक रूप से चर्चा की गई । 'फनी' चक्रवात के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नवत कुछ चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता पड़ी:-

1. पेयजल की कमी
2. जाति आधारित भेदभाव
3. सामाजिक बहिष्कार

इन चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए ।

6.12 मरुस्थलीकरण प्रतिरोध पर संयुक्त राष्ट्र समझौता, पार्टियों का सम्मेलन (सीओपी-14) विशेष आयोजन : भूमि-जल समुत्थानशीलता में सुधार के लिए सूखा जोखिम न्यूनीकरण; ईको डी.आर.आर. के विकल्पो और उपकरणों को मुख्य धारा में लाना: 2 सितंबर 2019, ग्रेटर नोएडा, एनसीआर

जलवायु समुत्थानशीलता पर उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 'आईयूसीएन-सीईएम', दक्षिण एशिया के सहयोग से "भूमि-जल समुत्थानशीलता में सुधार के लिए सूखा जोखिम न्यूनीकरण: ईको डी.आर.आर. के विकल्पों और उपकरणों को मुख्यधारा में लाना" विषय पर एक पक्षीय कार्यक्रम आयोजित किया । इस सत्र का उद्देश्य निरंतर गंभीर रूप धारण कर रही सूखे की परिस्थितियों, सूखे के कारण भूमि की क्षमता में गिरावट के प्रमुख केन्द्रों पर चर्चा करना था और इसमें मौजूदा सूखा जोखिम न्यूनीकरण सम्बंधी रणनीतियों की समीक्षा की गई तथा विकासात्मक योजना में ईको डी.आर.आर. आधारित समाधान के लिए समुत्थानशील उपकरणों की पहचान की गई । सम्मेलन में सतत् विकास लक्ष्यों, पेरिस जलवायु समझौते, एसएफडीआरआर को प्राप्त करने के लिए एक रोड-मैप तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, तथा जलवायु समुत्थानशीलता और किसानों का जीवनयापन सुगम बनाने को प्रोत्साहन देने तथा "वैश्विक सूखा शमन पहल" को सक्षम बनाने की दिशा में सबक हासिल करने पर चर्चा की गई ।



चित्र 10 : विशेष आयोजन: भूमि-जल समुत्थानशीलता में सुधार के लिए सूखा जोखिम न्यूनीकरण; ईको डी.आर.आर. के विकल्पो और उपकरणों को मुख्य धारा में लाना:

सत्र में 'सीआरआईडीए', 'आईएआरआई', 'आईएमडी', 'एनडीएमए', 'एनआईडीएम', 'सीएसआईआर-एनईईआरआई', 'डीएसी & एफडब्लयू', 'एमएनसीएफसी' तथा 'आईयूसीएन' और 'आईयूसीएन-सीईएम' सहित संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां; 'जीआईजेड', 'डब्लयूएचओ-इंडिया', 'जीजीजीआई' सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों; 'एनजीओ / आईएनजीओ' कार्यान्वयनकर्ता, और दिल्ली विश्वविद्यालय, 'डब्ल्यूआईआई', 'जी.बी. पंत विश्वविद्यालय, बिट्स-गोवा, 'टेरी-एसएएस', इग्नू, आरजीआईईपीटी, पेशेवर और व्यावसायिक संगठनों सहित विभिन्न अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों इत्यादि से 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

6.13 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय और गेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 'आपदा प्रबंधन' विषय पर संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला, 11-12 सितंबर, 2019 जीटीआई, नोएडा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ने 11-12 सितंबर, 2019 को गेल के सहयोग से नोएडा में "आपदा प्रबंधन" पर दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया । इस कार्यक्रम का समन्वयन "भू-मौसम सम्बधी जोखिम प्रबन्धन प्रभाग" के प्रमुख डॉ. सूर्य प्रकाश ने किया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के विभिन्न प्रासंगिक विभागों, विशेष रूप से गेल और शहरी स्थानीय निकायों से 46 प्रतिभागी इसमें शामिल हुए, जिनमें जेएनयू और अन्य गैर सरकारी संगठनों से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों के



चित्र 11 : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय तथा गेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन पर संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला

शिक्षाविद शामिल थे । कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य प्रबंधक (प्रशिक्षण), गेल श्री धर्मेंद्र खत्री और डॉ. सूर्य प्रकाश, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा किया गया ।

कार्यक्रम का उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता(डीआरआर एंड आर) के बारे में बेहतर समझ विकसित करना, देश में आपदा प्रबंधन पर प्रासंगिक अधिनियम, नीति, योजना, दिशानिर्देश और एसओपी के बारे में जानकारी प्राप्त करना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और सतत विकास पर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और घोषणाओं के बारे में जानना, आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुदृढ़ तंत्र पर चर्चा करना, उनकी कार्यात्मक और भौगोलिक व्यवस्थाओं के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की गतिविधियों को शुरू करना था । कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन अधिनियम की मूल अवधारणा और मंत्रालयों की जिम्मेदारियों और भूमिका के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति और योजना तथा 'एसएफडीआरआर', 'एसडीजीएस', जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण एजेंडा और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेंडे के एकीकरण द्वारा, आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी करने सम्बन्धी दिशानिर्देशों पर चर्चा की गई ।

6.14 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की "राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना" के तहत 'एचआरव्हीसीए' कार्यशाला, 17 सितंबर 2019, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली



चित्र 12 : कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की "राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना" के तहत 'एचआरव्हीसीए' कार्यशाला

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (जलवायु परिवर्तन पर उत्कृष्टता केंद्र)ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, के साथ "राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना" के तहत आधे दिन की कार्यशाला का आयोजन 17 सितंबर 2019 को कृषि भवन, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली में किया । यह कार्यशाला 'डीओएसी' एवं 'एफडब्लयू' और 'डीएआरई' संस्थानों के सभी प्रभागों के साथ जोखिम भेद्यता और क्षमता विश्लेषण ('एचआरवीसीए') पर चर्चा करने और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आयोजित की गई ।

कार्यशाला का उद्घाटन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक, मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल, और श्री अमिताभ गौतम, संयुक्त सचिव, सूखा प्रबंधन, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किया, उन्होंने 'एनएडीएमपी' और 'एचआरवीसीए' प्रक्रिया का महत्व प्रतिभागियों को समझाया । ईसीडीआरएम प्रभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. अनिल के गुप्त ने एचआरवीसीए कार्यशाला के उद्देश्य और योजना में इसकी भूमिका के बारे में प्रतिभागियों को बताया । सुश्री ऋचा श्रीवास्तव, अनुसंधान सलाहकार,'एनएडीएमपी' प्रोजेक्ट, 'एनआईडीएम', ने 'एचआरवीसीए' की प्रक्रिया और स्थिति के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुति 'डीओएसी एवं एफडब्लयू' और 'डीएआरई' संस्थानों के सभी प्रभागों के नोडल अधिकारियों के समक्ष दी ।

'एचआरवीसीए' और 'आरएमआरएस'(जोखिम शमन तथा प्रतिक्रिया नीति) सम्बन्धी टेम्पलेट को 'एनएडीएमपी' टीम के सहयोग से सभी नोडल अधिकारियों द्वारा मौके पर सफलतापूर्वक भरा गया ।

कार्यक्रम में कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग और डी.ए.आर.ई संस्थानों के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया और 'एनएडीएमपी' टीम के साथ 'ईसीडीआरएम' डिवीजन के विभागाध्यक्ष डॉ. अनिल के गुप्त ने 'जलवायु परिवर्तन पर उत्कृष्टता केंद्र' राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के तहत कार्यशाला का संयोजन किया।

6.15 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रबोधन कार्यशाला, 19 सितंबर 2019 नई दिल्ली



चित्र 13 : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रबोधन कार्यशाला

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन में 19 सितंबर 2019 को एक अर्ध दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया । स्वास्थ्य मंत्रालय के 40 प्रतिभागियों ने कार्यशाला में भाग लिया । कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. तनु जैन, एडीजी ट्रेनिंग और डॉ. यू.बी. दास, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा किया गया, जिन्होंने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के संदर्भ में सामान्य रूप से आपदाओं को समझने पर जोर दिया । सत्र की शुरुआत डॉ. अनिल गुप्त, एसोसिएट प्रोफेसर, ईडीआरएम डिवीजन, एनआईडीएम द्वारा उद्घाटन भाषण के साथ हुई, जिन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में आपदा प्रबंधन सम्बंधी परम्पराओं को एकीकृत करने के महत्व पर प्रकाश डाला और उसी के बारे में कुछ उदाहरणों को उद्धृत किया । एनआईडीएम की सहायक प्रोफेसर डॉ. सुषमा गुलेरिया ने आपदा प्रबंधन विषय की बुनियादी अवधारणाओं और शब्दावली पर एक संक्षिप्त जानकारी दी ।

एनआईडीएम में सहायक प्रोफेसर डॉ. अजिंदर वालिया ने पारिवारिक स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना का अवलोकन किया और परिवार के लिए आपदा प्रबंधन किट तैयार करने पर भी चर्चा की ।

इसके बाद 'एनआईडीएम' के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आमिर अली खान ने आग, भूकंप और बाढ़ सुरक्षा सामान्य खतरों के संदर्भ में विभिन्न करने और न करने योग्य बातों पर चर्चा की । उन्होंने 'मॉक ड्रिल' करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया । यह तथ्य उभर कर सामने आया कि आपदा प्रबंधन वास्तव में सभी योजनाओं और तैयारियों का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक सुरक्षा और कार्यालय आपदा तैयारी योजना पर अधिक विस्तृत कार्यशाला के साथ इसे आगे बढ़ाने के प्रति रुचि दिखाई है ।

6.16 आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) पर राष्ट्रीय कार्यशाला, 23 सितंबर 2019, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली।



चित्र 14 : आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) पर राष्ट्रीय कार्यशाला

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने 23 सितंबर, 2019 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, दिल्ली में आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया । अध्ययन के तहत विकसित आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) उपकरण, सर्वोत्तम वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के आधार पर और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भारत के लिए अनुकूलित किया गया है, जो आपदा प्रभावों और परिणामों के गहन विश्लेषणके आधार पर बहाली और पुनर्निर्माण की जरूरतों के व्यापक और वैज्ञानिक मूल्यांकन को सुगम करेगा । विभिन्न मंत्रालयों, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, विश्व बैंक और निजी क्षेत्र के आवासों से लगभग 92 प्रतिभागियों ने कार्यशाला में भाग लिया । प्रो० संतोष कुमार ने मंच पर आसीन प्रतिष्ठित महानुभावों श्री नित्यानंद राय, माननीय गृह राज्य मंत्री, मेजर जनरल मनोज कुमार बिंदल, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम और श्री जी.वी. सरमा, सदस्य सचिव एनडीएमए के स्वागत में संबोधन दिया । कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय द्वारा किया गया, जिसके पश्चात पीडीएनए मैनुअल, हैंडबुक और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई ।

6.17 नेपाली प्रतिनिधिमंडल - समन्वय बैठक, 24 सितंबर 2019, नई दिल्ली



चित्र 15: नेपाली प्रतिनिधिमंडल - समन्वय बैठक

7 सदस्यों वाले एक नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने 24 सितंबर 2019 को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एनआईडीएम का दौरा किया । टीम में ब्रिगेडियर जनरल सहदेव कदखाम, नंबर 7 ब्रिगेड कमांडर, श्री संत बहादुर सुनार, संयुक्त सचिव, प्रबंधन प्रभाग, रक्षा मंत्रालय, सुश्री इंदु घिमिरे, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, कर्नल सुबाष थापा, उप निदेशक, आपदा प्रबंधन निदेशालय, लेफ्टिनेंट कर्नल किरणराज श्रेष्ठा, एसओ, योजना और नीति निदेशालय, लेफ्टिनेंट कर्नल राजेंद्र पराजुली, नंबर 2, आपदा प्रबंधन बटालियन कमांडर और गृह मंत्रालय के अवर सचिव श्री बंशी कुमार आचार्य शामिल थे । एनआईडीएम के विभिन्न प्रभागों के प्रमुख, के विभागों के प्रमुख, इस बैठक की समन्वयक डॉ० सुषमा गुलेरिया, सहायक प्राध्यापक के साथ इस समन्वय बैठक में उपस्थित थे । एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक, मेजर जनरल मनोज कुमार बिंदल के कक्ष में दोपहर 2.00 बजे से बैठक आयोजित की गई । ईडीआरएम प्रभाग के प्रमुख डॉ० अनिल के गुप्त ने एनआईडीएम और इसके शासनादेशों और गतिविधियों के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी । नेपाली प्रतिनिधिमंडल को एनआईडीएम के वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर और एनआईडीएम द्वारा संचालित विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के बारे में भी बताया गया । प्रतिनिधिमंडल को एनआईडीएम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में और कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करने में भी रुचि थी । उन्होंने एनआईडीएम के साथ भविष्य के अनुसंधान और प्रलेखन सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की । एनआईडीएम द्वारा प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों को यादगार के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट किए गए ।

6.18 विकलांगता-समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए क्षमता निर्माण कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा, पर परामर्शदात्री बैठक: एनआईडीएम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा आयोजित, 18 अक्टूबर 2019, नई दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार ने क्षमता निर्माण, अनुसंधान और सहायता के माध्यम से विकलांगता समावेशी डीआरआर (डीआईडीआरआर) के लिए काम करने के प्रति सहयोग करने का निर्णय किया है ।



चित्र 16 : विकलांगता-समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए क्षमता निर्माण पर परामर्शदात्री बैठक: कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा

इस प्रक्रिया के पहले चरण के रूप में, आगे बढ़ने की दिशा में एक परामर्शदात्री बैठक 18 अक्टूबर 2019 को आयोजित की गई । यह बैठक समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक रूपरेखा पर पहुंचने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट कार्यों की पहचान करने के लिए विचार मंथन के उद्देश्य से हुई । परामर्श बैठक में 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बैठक में आपदाओं के दौरान दिव्यांगजनो के समक्ष आने वाली बाधाओं पर विचार किया गया और जोखिम प्रबंधन में शामिल किए जाने वाले मुद्दों, आपदा समावेशी 'डीआरआर' और 'डीआईडीआरआर' के लिए क्षमता निर्माण सम्बंधी कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा की गई ।

6.19 स्वास्थ्य समुत्थानशीलता और क्षमता निर्माण पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला, 1 नवंबर 2019, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत, स्वास्थ्य पर एक नया मिशन, मानव कल्याण में स्वास्थ्य पहलुओं के केंद्रीय महत्व को देखते हुए जोड़ा गया है । स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना विकसित की जा रही है, जिसमें एनआईडीएम, डब्लूएचओ और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से, अपने



चित्र 17 : स्वास्थ्य समुत्थानशीलता और क्षमता निर्माण पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला

ईसीडीआरएम डिवीजन में जलवायु समुत्थानशीलता के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीईसीआर) के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य, संचारी और गैर-संचारी रोग, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, व्यावसायिक, औद्योगिक स्वास्थ्य आदि सहित अन्य आपदा संबंधी बीमारियां से निपटने के लिए स्वास्थ्य अनुकूलन योजना के लिए कार्य योजना और रोडमैप तैयार कर रहा है ।

1 नवंबर 2019 को लखनऊ, यूपी में मैरियट, के होटल फेयरफील्ड में एक उत्तर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, महामारी विज्ञान, सामुदायिक चिकित्सा, आपदा जोखिम प्रबंधन, सामान्य प्रशासन से जुड़े, राज्य के विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय संस्थानों, एनआईओएच, सीईपीटी विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों, गैर-सरकारी संगठनों, यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, एनडीएमए, आईएमडी, वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल, आदि से लगभग 30 विशेषज्ञ प्रतिनिधियों ने भाग लिया । कार्यक्रम का आयोजन डब्ल्यूएचओ और एनसीडीसी, जीईएजी (गोरखपुर पर्यावरणीय कार्रवाई समूह) के साथ संयुक्त रूप से किया गया । स्वास्थ्य अनुकूलन योजना (एचएपी) के पश्चात् मामलों के अध्ययन संबंधी एक विस्तृत विवरण, प्रशिक्षण टूलकिट तैयार की जायेगी और क्षमता निर्माण के प्रमुख मुद्दों पर नीति पत्रों की श्रृंखला का एक संग्रह तैयार किया जायेगा ।

6.20 स्वास्थ्य समुत्थानशीलता और क्षमता निर्माण पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला, 4 नवंबर 2019, पश्चिम बंगाल, कोलकाता



चित्र 18 : स्वास्थ्य समुत्थानशीलता और क्षमता निर्माण पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत, स्वास्थ्य पर एक नया मिशन, मानव कल्याण में स्वास्थ्य पहलुओं के केंद्रीय महत्व को देखते हुए जोड़ा गया है । स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना विकसित की जा रही है, जिसमें डब्लूएचओ और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से, एनआईडीएम अपने ईसीडीआरएम डिवीजन में जलवायु परिवर्तन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य, संचारी और गैर-संचारी रोग, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, व्यावसायिक, औद्योगिक स्वास्थ्य आदि सहित अन्य आपदा संबंधी बीमारियां से निपटने के लिए, स्वास्थ्य अनुकूलन योजना के लिए कार्य योजना और रोडमैप तैयार कर रहा है । 4 नवंबर, 2019 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल के होटल ताज विवांता, ईएम बाईपास में एक पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, महामारी विज्ञान, सामुदायिक चिकित्सा, आपदा क्षेत्र के विशेषज्ञों में से लगभग 30 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें जोखिम प्रबंधन, सामान्य प्रशासन, राज्य के विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय संस्थानों, एनआईओएच, सीईपीटी विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों, गैर सरकारी संगठनों, यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, एनडीएमए, आईएमडी, वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल, आदि से प्रतिनिधि शामिल थे । कार्यक्रम डब्ल्यूएचओ और एनसीडीसी, एडमास विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया । स्वास्थ्य अनुकूलन योजना (एचएपी) के पश्चात् मामलों के अध्ययन सम्बंधी एक विस्तृत विवरण, प्रशिक्षण टूलकिट तैयार की जायेगी तथा स्वास्थ्य समुत्थानशीलता और क्षमता निर्माण के प्रमुख मुद्दों पर नीति पत्रों की श्रृंखला का एक संग्रह तैयार किया जायेगा ।

6.21 पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की समन्वय बैठक, 7 नवंबर 2019, नई दिल्ली



चित्र 19 : पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ समन्वय बैठक

पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल (जिनमें 2 भारत में चीन के दूतावास के अधिकारी थे) ने 7 नवंबर 2019 को संस्थान के साथ भविष्य के सहयोग पर बातचीत और चर्चा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का दौरा किया । मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल, कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और श्री झेंग गुओगुआंग, उप-मंत्री, आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने बैठक के सम्बंध में प्रारंभिक टिप्पणी दी । डॉ. अनिल कुमार गुप्त, प्रमुख ईसीडीआरएम और एसोसिएट प्रोफेसर ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के बारे में एक प्रस्तुति दी । श्री झेंग गुओगुआंग, उप-मंत्री, आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय और इसकी गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया । उन्होंने संक्षेप में चीन में आपातकालीन प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण केंद्र के उद्देश्य और मंतव्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्रभाग के संचालन के साथ आपदा प्रबंधन प्रणाली के कामकाज पर भी चर्चा की । यह बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ समाप्त हुई ।

6.22 आपदा जोखिम जागरूकता पर कार्यशाला, 9 नवंबर, 2019, विजयवाड़ा



चित्र 20 : आपदा जोखिम जागरूकता पर कार्यशाला

आपदाओं से दुनिया भर के लोगों के जीवन, संवैधानिक अधिकारों और जरूरतों को खतरा है । पिछले दो दशकों में, भारत को विनाशकारी आपदाओं जैसे लातूर भूकंप (1993), ओडिशा सुपर साइक्लोन (1999), भुज भूकंप (2001), भारतीय सुनामी (2004), जम्मू और कश्मीर भूकंप (2005), बिहार बाढ़ (2008), उत्तराखंड बाढ़ (2013), चक्रवात फैलिन (2013), चेन्नई बाढ़ (2015), केरल बाढ़ (2018) और चक्रवात फनी (2019) का सामना करना पड़ा । सूखा धीमी गति से आने वाली आपदा है, जो आबादी को समान रूप से प्रभावित करती हैं । कर्नाटक (16 जिले) और आंध्र प्रदेश (4 जिले) ने 2001-2015 के बीच कम से कम 10 सूखे के प्रकोप को झेला । इन आपात स्थितियों के दौरान, विशेष रूप से बच्चे बीमारियों, कुपोषण, हिंसा और तस्करी के शिकार होते हैं ।

जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लोगों की बढ़ती भेद्यता को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दक्षिणी परिसर ने काकरापर्ती भावनारायण कॉलेज के सहयोग से 9 नवंबर, 2019 को कॉन्फ्रेंस हॉल, केबीएन कॉलेज, विजयवाड़ा में एनसीसी और एनएसएस के छात्रों के लिए 'आपदा जोखिम जागरूकता कार्यशाला' का आयोजन किया, जिसमें 107 छात्रों ने भाग लिया ।

6.23 आपदा जोखिम जागरूकता पर कार्यशाला, 14 नवंबर, 2019, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, आन्ध्र प्रदेश



चित्र 21 : आपदा जोखिम जागरूकता पर कार्यशाला

आपदाओं से दुनिया भर के लोगों के जीवन, संवैधानिक अधिकारों और जरूरतों को खतरा है। पिछले दो दशकों में भारत ने विनाशकारी आपदाओं जैसे लातूर भूकंप (1993), ओडिशा सुपर साइक्लोन (1999), भुज भूकंप (2001), भारतीय सुनामी (2004), जम्मू और कश्मीर भूकंप (2005), बिहार बाढ़ (2008), उत्तराखंड बाढ़ (2013), चक्रवात फैलिन (2013), चेन्नई बाढ़ (2015), केरल बाढ़ (2018) और चक्रवात फनी (2019) का सामना किया है। सूखा धीमी गति से आने वाली आपदा है, जो आबादी को समान रूप से प्रभावित करती हैं। कर्नाटक (16 जिले) और आंध्र प्रदेश (4 जिले) ने 2001-2015 के बीच कम से कम 10 बार सूखे के प्रकोप को झेला। इन आपात स्थितियों के दौरान बच्चे विशेष रूप से बीमारियों, कुपोषण, हिंसा और तस्करी के शिकार होते हैं ।

जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लोगों की बढ़ती भेद्यता को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दक्षिणी परिसर ने 14 नवंबर 2019 को आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एनएसएस के छात्रों के लिए आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय के सहयोग से 'आपदा जोखिम जागरूकता कार्यशाला' का आयोजन किया, जिसमें 180 छात्रों ने भाग लिया ।

6.24 स्वास्थ्य समुत्थानशीलता और क्षमता निर्माण पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला, 14 नवंबर 2019, हैदराबाद



चित्र 22 : स्वास्थ्य समुत्थानशीलता और क्षमता निर्माण पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत, स्वास्थ्य पर एक नया मिशन, मानव कल्याण में स्वास्थ्य सम्बंधी पहलुओं के केंद्रीय महत्व को देखते हुए जोड़ा गया है । स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना विकसित की जा रही है जिसमें एनआईडीएम, डब्लूएचओ और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से, अपने ईसीडीआरएम डिवीजन में जलवायु परिवर्तन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य, संचारी और गैर-संचारी रोग, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, व्यावसायिक, औद्योगिक स्वास्थ्य आदि सहित अन्य आपदा संबंधी बीमारियां से निपटने के लिए कार्य योजना और रोडमैप तैयार कर रहा है । 14 नवंबर, 2019 को हैदराबाद केसीपी के होटल मरक्यूर में एक दक्षिणी क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभागों के जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, महामारी विज्ञान, सामुदायिक चिकित्सा, आपदा जोखिम प्रबंधन, सामान्य प्रशासन, क्षेत्र से लगभग 30 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें केन्द्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय संस्थानों, एनआईओएच, सीईपीटी विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों, गैर सरकारी संगठनों, यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, एनडीएमए, आईएमडी, वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल आदि से प्रतिनिधि शामिल हुए । कार्यक्रम डब्ल्यूएचओ और एनसीडीसी के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था । स्वास्थ्य अनुकूलन योजना (एचएपी) के पश्चात् मामलों के अध्ययन संबंधी एक विस्तृत विवरण, प्रशिक्षण टूलकिट और क्षमता निर्माण के प्रमुख मुद्दों पर नीति पत्रों की श्रृंखला का एक संग्रह तैयार किया जायेगा ।

6.25 भारत में आपदा समुत्थानशील कृषि पर राष्ट्रीय हितधारक-परामर्श कार्यशाला 15 नवंबर, 2019 हैदराबाद ।

जलवायु समुत्थानशीलता के लिए उत्कृष्टता केन्द्र, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (सीईसीआर-एनआईडीएम) द्वारा संयुक्त रूप से 'आईसीएआर-सीआरआईडीए', हैदराबाद के साथ राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना के अन्तर्गत भारत में 'आपदा समुत्थानशील कृषि' विषय पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का 15 नवम्बर,2019 को आयोजन किया । इस कार्यशाला में वैज्ञानिक, पेशेवर, केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों, एसडीएमए, एनडीएमए, आईएमडी, आईसीएआर-आईएआरआई, इसरो / एमएनसीएफसी,



चित्र 23 : भारत में आपदा समुत्थानशील कृषि पर राष्ट्रीय हितधारक-परामर्श कार्यशाला

सीआरआरआई, एनएएआरएम, यूएनडीपी, जीआईजेड, गैर सरकारी संगठनों, आदि के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य ड्राफ्ट एनएडीएमपी पर चर्चा करने के अतिरिक्त भारत में समुत्थानशील कृषि के लिए रोडमैप तैयार करना, संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से सहायता संघ मोड में 'सीईसीआर-एनआईडीएम' के तहत आपदा समुत्थानशील कृषि के लिए एक रणनीतिक कार्यक्रम का निर्माण करना है, जिसमें 'यूएनसीसीडी' लक्ष्य, 'एसडीजी', किसानों की आय दोगुनी करना, 2024 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन को आसान बनाना शामिल होगा ।

एनएडीएमपी आपदा समुत्थानशील कृषि को मूर्त रूप देने के लिए एक विशेष संस्थागत नेटवर्क तैयार करने की भी पहल करेगा और अन्य प्रमुख कार्यक्रमों के साथ इसे एकीकृत भी करेगा । कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, श्री मनोज कुमार बिन्दल इस आयोजन के विशिष्ट अतिथि थे, जबकि 'आईसीएआर-मैनेज' की महानिदेशक, सुश्री जयालक्ष्मी मुख्य अतिथि थीं ।

6.26 'सूझबूझ और नवपरिवर्तन के माध्यम से जलवायु समुत्थानशीलता' विषय पर सेमिनार, 25 नवंबर, 2019, नई दिल्ली



चित्र 24 : 'सूझबूझ और नवपरिवर्तन के माध्यम से जलवायु समुत्थानशीलता' विषय पर सेमिनार

स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज, यॉर्क विश्वविद्यालय, टोरंटो, कनाडा के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली के जलवायु समुत्थानशीलता के लिए उत्कृष्टता केंद्र ('सीईसीआर') द्वारा 25 नवंबर 2019 को 'वायएमसीए' ऑडिटोरियम में "सूझबूझ और नवपरिवर्तन के माध्यम से जलवायु समुत्थानशीलता" विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है । कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, श्री मनोज कुमार बिन्दल ने स्वागत भाषण दिया जबकि प्रो. संतोष कुमार और मेजर जनरल (से.नि.) वी. के. नाइक ने अपनी टिप्पणी दी । यॉर्क यूनिवर्सिटी के डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट प्रोग्राम की प्राध्यापक प्रो. निरुपमा अग्रवाल ने विशेष चर्चा की, जिसमें जलवायु परिवर्तन और शमन के मुद्दों के वैज्ञानिक ज्ञान और जन धारणा सम्बंधी पहलुओं को शामिल किया गया ।

उन्होंने कनाडा, अमेरिका और भारत सहित विकासशील देशों के लिए आपदा समुत्थानशीलता के लिए जलवायु समुत्थानशीलता और पर्यावरण अनुकूल विकास के मुद्दों के कई उदाहरणों और प्रकरणों पर चर्चा की । संगोष्ठी का समन्वयन डॉ. अनिल के गुप्ता कार्यक्रम निदेशक, सीईसीआर-एनआईडीएम और सुश्री थिनल्स चोंडोल, यंग प्रोफेशनल-सीईईसीआर द्वारा किया गया । सेमिनार में 5 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न मंत्रालयों, संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, शिक्षाविदों, डीआरआर और जलवायु परिवर्तन पेशेवरों, अनुसंधान और पीजी छात्रों सहित लगभग 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया । एनआईडीएम और यॉर्क विश्वविद्यालय ने अकादमिक और अनुसंधान सहयोग और दीर्घकालिक संबंधों के विकल्पों पर भी चर्चा की ।

6.27 स्वास्थ्य समुत्थानशीलता और क्षमता निर्माण पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला, 27 नवंबर, 2019, अहमदाबाद

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत, स्वास्थ्य पर एक नया मिशन, मानव कल्याण में स्वास्थ्य पहलुओं के केंद्रीय महत्व को देखते हुए जोड़ा गया है । स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना विकसित की जा रही है जिसमें एनआईडीएम, डब्लूएचओ और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से, अपने



चित्र 25 : स्वास्थ्य समुत्थानशीलता और क्षमता निर्माण पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला

ईसीडीआरएम डिवीजन में जलवायु परिवर्तन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य, संचारी और गैर-संचारी रोग, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, व्यावसायिक, औद्योगिक स्वास्थ्य आदि सहित अन्य आपदा संबंधी बीमारियां से निपटने के लिए कार्य योजना और रोडमैप तैयार कर रहा है । 27 नवंबर, 2019 को अहमदाबाद के होटल प्राइड प्लाजा में एक पश्चिमी क्षेत्रीय परामर्श

कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, महामारी विज्ञान, सामुदायिक चिकित्सा, आपदा जोखिम प्रबंधन, सामान्य प्रशासन क्षेत्र से लगभग 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें राज्यों के विभागों और संघ शासित क्षेत्र, राष्ट्रीय संस्थान, एनआईओएच, सीईपीटी विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, गैर सरकारी संगठन, यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, एनडीएमए, आईएमडी, वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल आदि से प्रतिनिधि शामिल हुए । कार्यक्रम डब्ल्यूएचओ, एनसीडीसी और गुजरात विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया । स्वास्थ्य अनुकूलन योजना (एचएपी) के पश्चात् मामलों के अध्ययन सम्बंधी एक विस्तृत विवरण, प्रशिक्षण टूलकिट तथा स्वास्थ्य समुत्थानशीलता और क्षमता निर्माण के प्रमुख मुद्दों पर नीति पत्रों की श्रृंखला का एक संग्रह तैयार किया जाएगा ।

6.28 "भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता" पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 28 नवंबर, 2019, अशोक होटल, नई दिल्ली

28 नवंबर 2019 को होटल अशोक, नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय द्वारा भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया । इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा किया गया । उद्घाटन सत्र के दौरान दो दस्तावेज "ढलान पर इमारतों की सुरक्षा के लिए भूस्खलन तैयारी सम्बंधी मार्गदर्शिका" और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की "सार माला" भी माननीय मंत्री द्वारा जारी की गई । उद्घाटन सत्र सदस्य सचिव, एनडीएमए, श्री जी.वी.वी. सरमा; संयुक्त सचिव (डीएम) गृह मंत्रालय, श्री संजीव के जिंदल; 'एनडीएमए' के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त)



चित्र 26 : "भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता" पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-2019

एन. सी. मारवाह, पीवीएसएम, एवीएसएम और श्री कमल किशोर के साथ-साथ कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल, वीएसएम और अन्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों / संस्थानों /विश्वविद्यालयों के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति से सुशोभित रहा ।

माननीय गृह राज्य मंत्री ने समुदाय, अवसंरचना और संरचना पर भूस्खलन आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों पर प्रकाश डाला । इसके अलावा, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को सूचना, अनुभव और नवाचारों का प्रसार करने के लिए व्यापक सहयोग तंत्र निर्माण के लिए प्रेरित किया, ताकि भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता तथा तत्संबंधी तैयारी के लिए उपयुक्त

प्रौद्योगिकी विकसित की जा सके । इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भूस्खलन शमन और प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों / संस्थानों / विश्वविद्यालयों से लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

6.29 पशु समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण (एआईडीआरआर) के लिए क्षमता निर्माण पर परामर्श कार्यशाला, 9 जनवरी 2020, नई दिल्ली



चित्र 27 : पशु समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए क्षमता निर्माण पर परामर्श कार्यशाला

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ('एनआईडीएम') ने 9 जनवरी 2020 को द एंबेसडर होटल, नई दिल्ली में पशु समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण ('एआईडीआरआर') के लिए क्षमता निर्माण पर एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया । उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता प्रो. वी.के. शर्मा, श्री उपमन्यु बसु, संयुक्त सचिव, डीओएएचडी, सुश्री भारती, महानिरीक्षक वन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल, कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा की गई । कार्यशाला में विभिन्न संगठनों जैसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पशुपालन विभाग, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय वन्यजीव संस्थान, डब्ल्यूटीआई, जीआईजेड, विभिन्न राज्यों के पशु चिकित्सा विशेषज्ञों आदि ने भाग लिया । इस कार्यशाला का उद्देश्य आपदाओं के दौरान जानवरों के प्रति मौजूदा लापरवाही पर विचार-मंथन करना, आपदाओं के दौरान जानवरों की देख-रेख और देखभाल से संबंधित मुद्दे, और इस संबंध में मौजूदा नीतियों का अध्ययन करना, त्रुटिग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करना और आपदाओं के दौरान जानवरों के लिए एक प्रभावी आपदा जोखिम न्यूनीकरण तंत्र के लिए रूपरेखा तैयार करना था । कार्यशाला में मानव स्वास्थ्य (ज़ूनोसिस) के संदर्भ में पशु देखभाल जैसे विषयों, संरक्षण और प्रबंधन के लिए जीव-जन्तु संसाधनों पर जंगल की आग के प्रभाव को समझना, पशु समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उद्देश्य से स्थानीय नेटवर्क की क्षमता का दोहन, चिड़ियाघर के लिए विशिष्ट आपदा प्रबंधन योजना पर चर्चा की गई । समापन सत्र की अध्यक्षता सीजेडए के सदस्य सचिव डॉ. एसपी यादव और 'जेडएसआई' के निदेशक डॉ. कैलाश चंद्र ने की । कार्यशाला का समन्वयन प्रो अनिल के. गुप्त और श्री आशीष के. पांडा ने किया ।

6.30 सूखा समुत्थानशील कृषि पर इथियोपिया सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ पीयर एक्सचेंज राउंडटेबल, 30 जनवरी 2020, नई दिल्ली



चित्र 28 : सूखा समुत्थानशील कृषि पर इथियोपिया सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ पीयर एक्सचेंज राउंडटेबल

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने एशिया आपदा तैयारी केंद्र (एडीपीसी) के सहयोग से 30 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में सूखा समुत्थानशील कृषि पर पीयर एक्सचेंज राउंडटेबल का आयोजन किया, जो कि इथियोपियाई सरकार के अधिकारियों द्वारा जलवायु और आपदा समुत्थानशील कृषि सम्बंधी अच्छी कार्यप्रणालियों को जानने के लिए एक ज्ञान-विनिमय यात्रा के भाग के रूप में था । कार्यशाला का समन्वयन एनआईडीएम के प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्त ने किया और उद्घाटन डॉ. अनिल कुमार सिंह, सचिव, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, डॉ. शिबेंदु शंकर रे, निदेशक, महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर और लेफ्टिनेंट कर्नल दिनेश चंदर वशिष्ठ, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम द्वारा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, आईसीआरए-सीआरआईडीए, एमएनसीएफसी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया । इथियोपिया के प्रतिनिधिमंडल ने इथियोपिया में कृषि, पशुधन और पूर्व चेतावनी निगरानी के परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए तीन प्रस्तुतियाँ दीं । उन्होंने कर्नाटक पीयर लर्निंग विजिट की अंतर्दृष्टि पर एक प्रस्तुति भी साझा की । राउंडटेबल की अध्यक्षता डॉ. अनिल कुमार सिंह और राष्ट्रीय एजेंसियो के प्रतिभागियों, जैसे आईएमडी से डॉ. के. के. सिंह, डॉ. एस.डी. अत्री, एनडीएमए से डॉ. पवन कुमार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से डॉ. प्रदीप कुमार साहा, आईसीएआर-सीआरआईडीए से डॉ. जेवीएनएस प्रसाद, एमएनसीएफसी से डॉ. सालिनी सक्सेना, आदि द्वारा की गई । प्रतिभागियों ने पूर्व चेतावनी प्रणाली, सूखे की घोषणा, फसल बीमा कार्यक्रम, आदि पर चर्चा की । वक्ताओं ने सूखा समुत्थानशील कृषि के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला । समापन समारोह में भारत में इथियोपिया की राजदूत डॉ. तिजिता मुरुगेटा, डॉ. नीना मल्होत्रा, अतिरिक्त सचिव (पूर्व और दक्षिणी अफ्रीका), विदेश मंत्रालय ने भाग लिया और अपनी टिप्पणी दी । डॉ. तिजिता मुरुगेटा ने इस कार्यक्रम में आमंत्रण के लिए आभार व्यक्त किया । उन्होंने जोर देकर कहा कि

इस तरह के कार्यक्रम अन्य देशों के लिए भी आयोजित किए जाने चाहिए क्योंकि सूखा आज एक बड़ी चुनौती है जिसका सामना अधिकांश देश कर रहे हैं । उन्होंने आयोजकों को इथियोपिया के प्रतिनिधिमंडलों के लिए एक ऐसा मंच बनाने के लिए बधाई दी, जहाँ वे उनके समक्ष आ रही समस्याओं का प्रदर्शन कर सकते हैं, और सूखे से निपटने के लिए भारत से सीख सकते हैं । डॉ. नीना मल्होत्रा ने भारतीय कृषि के परिदृश्य और समुत्थानशील कृषि के प्रति योजनाओं, नीतियों और की गई पहलों के बारे में प्रकाश डाला । उन्होंने प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना और कृषि तथा किसान मंत्रालय के वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर जोर दिया। कार्यक्रम इथियोपिया के प्रतिनिधिमंडल और भारतीय अधिकारियों के बीच स्मृति चिन्ह के आदान-प्रदान और डॉ. सनायानबी होदाम के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुआ ।

6.31 विकलांगता-समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण : समावेश के मार्ग तथा समुत्थानशीलता हेतु कार्रवाई पर राष्ट्रीय सम्मेलन, 5 फरवरी, 2020, नई दिल्ली



चित्र 29 : विकलांगता-समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन: समावेश के मार्ग तथा समुत्थानशीलता हेतु कार्रवाई

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से विकलांगता-समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीडीआरआर); समावेश के मार्ग और समुत्थानशीलता के लिए कार्रवाई विषय पर 5 फरवरी 2020 को नई दिल्ली के राजदूत होटल में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के माननीय सदस्य श्री कमल किशोर, और श्री एस.एन. प्रधान, महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने सम्मेलन का उद्घाटन किया । आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रिया में दिव्यांगजन समावेश पर तीन तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया: एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता, स्थानीय स्तर

की कार्रवाई में मुख्यधारा के समावेश और दिव्यांगजनों की आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रिया में भागीदारी । श्रीमती शकुंतला गैमलिन, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और श्री जी.वी.वी. सरमा, माननीय सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सम्मेलन के समापन सत्र को सम्बोधित किया ।

6.32 'आपदा जोखिम वित्तपोषण, बीमा तथा जोखिम अंतरण' पर राष्ट्रीय कार्यशाला, 13 फरवरी 2020, इंश्योरेंस इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया, मुम्बई



चित्र 30 : 'आपदा जोखिम वित्तपोषण, बीमा तथा जोखिम अंतरण' पर राष्ट्रीय कार्यशाला

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मुम्बई के सहयोग से 13 फरवरी 2020 को इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मुम्बई के सभागार में 'आपदा जोखिम वित्तपोषण, बीमा तथा जोखिम अंतरण' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया । बीमा पर कार्यशाला का आयोजन आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्बंधी राष्ट्रीय मंच (तृतीय) (एनपीडीआरआर) के पूर्व आयोजन के रूप में, आपदा जोखिम वित्तपोषण को समझने, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा सेक्टर-विशिष्ट समाधानों की सिफारिश करने, राज्यों में आपदा जोखिम बीमा के कार्यान्वयन और भविष्य की कार्य योजना के निर्माण के लिए नीति समर्थन के उद्देश्य से आयोजित किया गया था । यह आयोजन आपदा समुत्थानशीलता के लिए आगे बढ़ने के रास्ते पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, वित्तीय समुत्थानशीलता और बेहतर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उद्देश्य से सरकार और बीमा कंपनियों को एक मंच पर लेकर आया । कार्यशाला में देश भर के 186 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और विभिन्न नोडल मंत्रालयों, राज्य सरकार के विभागों और बीमा कंपनियों ने इसमें भागीदारी की ।

6.33 तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता (सीडीआरआर एवं आर) पर राष्ट्रीय सम्मेलन - 25 फरवरी 2020 , अशोक होटल, नई दिल्ली



चित्र 31 : तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता (सीडीआरआर एवं आर) पर राष्ट्रीय सम्मेलन - 2020

25 फरवरी 2020 को होटल अशोक, नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय द्वारा तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया । माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय ने, राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की । उद्घाटन सत्र को सदस्य सचिव, एनडीएमए, श्री जी.वी.वी. सरमा; डीजी, आईएमडी, डॉ. एम महापात्र; प्रख्यात विशेषज्ञ डॉ. आर के भंडारी, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम, मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल, वीएसएम;प्रो. सूर्य प्रकाश (प्रमुख जीएमआर डिवीजन, एनआईडीएम) और विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों / संस्थानों / विश्वविद्यालयों के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति से सुशोभित किया । एक दिवसीय सम्मेलन में तटीय आपदा जोखिमों के बारे में बेहतर समझ और प्रभावी सहयोगी कार्यों के लिए प्रधान मंत्री के 10-सूत्री एजेंडे और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाइ फ्रेमवर्क को लागू करने और प्रभावित हितधारकों के बीच समुत्थानशीलता संवर्धन के लिए मानव क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया । इस राष्ट्रीय सम्मेलन से तटीय आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संगठनों / संस्थानों / विश्वविद्यालयों से लगभग 200 प्रतिभागियों को एक मंच पर एकत्रित होने का अवसर मिला ।

6.34 आपदा प्रबंधन पर कॉनकॉर के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला, 28 फरवरी 2020, नई दिल्ली



चित्र 32 : आपदा प्रबंधन पर कॉनकॉर के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड(कॉनकॉर), देश में समुद्री कंटेनरों को संभालने के लिए बहुविध परिवहन और संभार तंत्र अवसंरचना विकसित करने के मुख्य उद्देश्य के लिए जिम्मेदार है । इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन के वैचारिक और कानूनी ढांचे को समझना, आपदा पूर्व परिदृश्यों पर जोखिम न्यूनीकरण, ऑनसाइट और ऑफ-साइट आपातकालीन योजनाओं की जांच करना, कॉनकॉर टर्मिनलों की गतिविधियों और बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन पर आवश्यक आदानों के प्रति प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना था । विचार मंथन सत्र में भाग लेने के पश्चात प्रतिभागियों से आगे के इनपुट एकत्र करने में मदद मिली ताकि भविष्य में आपदा प्रबंधन पर क्षमता निर्माण / वृद्धि की योजना बनाई जा सके । इस कार्यशाला में कॉनकॉर के सहायक प्रबंधक / प्रबंधक और उससे ऊपर के स्तर, सहायक अधिकारी और ऊपर के स्तर, वरिष्ठ कार्यकारी इत्यादि स्तर के लगभग 27 अधिकारियों ने भाग लिया ।

अध्याय 7

वित्त और लेखा

लेखा परीक्षित रिपोर्ट और बैलेंस शीट

Vipin Aggarwal Kudsia & Associates
CHARTERED ACCOUNTANTS
150-A, DDA Flats, Shahpur Jat,
New Delhi - 110049
Tel. / Fax : 011-26492207/08
e-mail : welcome@vakaassociates.com

सेवा में,
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
नई दिल्ली

1. **हमने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान** को 31 मार्च, 2020 तक के संलग्न तुलना-पत्र सहित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते (नकद आधार पर बनाए गए) और प्राप्त और भुगतान खाता भी शामिल है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सारांश इसके साथ जोड़ा गया है।

2. **वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी**

   प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उसमें प्रस्तुत विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है। प्रस्तुत वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाले हैं तथा इनमें कोई मिथ्या कथन नहीं है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि का कारण हो।

3. **लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व**

   हमारी जिम्मेदारी प्रस्तुत वित्तीय विवरणों के आधार पर लेखापरीक्षा पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और अनुपालन और लेखापरीक्षा का निष्पादन करने के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरण में कोई मिथ्य कथन नहीं है।

   एक ऑडिट में वित्तीय विवरणों के बारे में लेखों और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिम के आकलन शामिल है, वह चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो उन जोखिम आकलनों को बनाने में, लेखापरीक्षक ऑडिटी की तैयारी और वित्तीय वक्तव्यों के उचित प्रस्तुतीकरण के लिए आंतरिक नियंत्रण को मानता है ताकि परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिटिंग प्रक्रिया की जा सके, लेकिन इसमें इकाई की प्रभावशीलता पर कोई राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं है। आतंरिक नियंत्रण, एक लेखापरीक्षा में लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की उचितता, साथ ही वित्तीय कर्तव्यों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रुप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

हमारा मानना है कि हमने लेखापरीक्षक राय प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त विवरण प्राप्त किया है। इस संस्थान के प्रबंधन ने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अपनाई जाने वाली लेखांकन नीतियों का अनुपालन नहीं किया है। प्रबंधन ने वित्तीय विवरण की प्राप्ति आधार अपनाया है (स्थापना व्यय, किराया, दर तथा कर, सहायक अनुदान के अतिरिक्त, जिनका लेखा जोखा नकदी के आधार पर रखा जाता है) जिसके कारण प्राप्ति संकल्पना नीति और टीडीएस प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।

स्रोत पर कर के रुप में काटी गई 2,53,673.65 रुपए की राशि लंबे समय से बही में दर्ज है और वसूली योग्य नहीं है।

4. अभिमत

हमारे विचार में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण यथा अपेक्षित रीति में सूचना देते हैं और भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन 'सिद्धांतों के अनुरुप होने की उपयुक्त योग्यता को छोड़कर सही और निष्पक्ष हैं'

(i) बैलेंस शीट के मामले में संस्थान की स्थिति 31 मार्च, 2020 के अनुसार है:

(ii) आय और व्यय विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय आय से अधिक है: और

(iii) प्राप्तियां और भुगतान लेखों के संबंध में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए संस्थान की प्राप्तियां और भुगतान लेखा के लिए।

हम सूचित करते हैं कि:

1. हमने वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
2. हमारी राय में, जहां तक लेखा बही की जाँच से प्रतीत होता है, संस्थान द्वारा लेखा बही कानून द्वारा यथापेक्षित ढंग से रखी गई है;
3. इस रिपोर्ट से सबंधित बैलेंस शीट और आय व्यय का लेखा बही के अनुसार है।

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म रजि. सं. 00977एन)

हस्ता/-
अनुपमा गोयल
पार्टनर
एम.नं. 046053
यूडीआईएन: 20046053AAAAAB4866

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18-08-2020

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रुप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)

31 मार्च, 2020 तक का आय-व्यय लेखा

विवरण	अनुसूची	31.03.2020	31.03.2019
		राशि	राशि
		रुपए	रुपए
संचित निधि//पूंजी कोष और देयताएं			
आरक्षिती और अधिशेष	2	974,776,560.29	484,975,583.93
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	3	61,157,069.00	55,815,629.00
कुल		**1,035,933,629.29**	**540,791,212.93**
आस्तियां			
स्थिर आस्तियां	4	752,103,151.30	416,596,539.30
निवेश	5	281,768,962.00	113,611,701.00
वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम	6	2,061,515.99	10,582,972.63
कुल		**1,035,933,629.29**	**540,791,212.93**

महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियों और लेखा टिप्पणी

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 009771एन

हस्ता/-
अनुपमा गोयल
(पार्टनर)
एम. नं. 046053
यूआईडीएनः 20046053AAAAAB4866

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ता/-
मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल
(कार्यकारी निदेशक)

हस्ता/-
सुरेन्द्र सिंह बिष्ट
(लेखा अधिकारी)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक:18-08-2020

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रुप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान आय और व्यय लेखा

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2020	31.03.2019
		रुपए	रुपए
आय/(गृह मंत्रालय) से अनुदान			
गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	7	120,000,000.00	99,999,979.00
कुल क		**120,000,000.00**	**99,999,979.00**
व्यय (गृह मंत्रालय-अनुदान)			
स्थापना व्यय	8	47,212,866.00	38,959,712.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	9	31,117,452.64	30,315,955.59
प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं पर व्यय	10	40,944,465.00	31,238,769.00
अवमूल्यन	4	924,240.00	538,261.00
कुल ख		**120,199,023.64**	**101,052,697.59**
पूर्व अवधि और असाधारण मदों से पहले गृह मंत्रालय कोष से घाटा होने के कारण शेष राशि		**(199,023.64)**	**(1,052,718.59)**
घाटा: पूर्व अवधि व्यय		**-**	**2,667,468.00**
गृह मंत्रालय कोष से घाटा होने पर शेष		**(199,023.64)**	**(3,720,186.59)**
अन्य की ओर से प्राप्त किया गया ब्याज	11		
एफडीआर (अन्य) पर ब्याज		6,874,510.00	2,841,238.00
महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियों और लेखा टिप्पणी	1		

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 009771एन

हस्ता/-
अनुपमा गोयल
(पार्टनर)
एम. नं. 046053
यूडीआईएन: 20046053AAAAAB4866

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:18-08-2020

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ता/-
मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल
(कार्यकारी निदेशक)

हस्ता/-
सुरेन्द्र सिंह बिष्ट
(लेखा अधिकारी)

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रुप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान लेखा

(राशि रुपए में)

विवरण	31.03.2020		31.03.2020	
	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
प्राप्तियां				
अथशेष				
बैंक बकाया (चालू खाता)	1,532,802.24		1,746,590.87	
बैंक बकाया (पूंजी शीर्ष)	77,212,250.00		91,802,499.00	
बैंक बकाया (अन्य सावधि जमा)	36,399,451.00		51,451,973.00	
यूको बैंक बचत खाता	(1,412,966.26)	**113,731,536.98**	25,318.00	**145,026,380.87**
प्राप्त अनुदान				
एनडीएम कार्यक्रम स्कीम के लिए गृह मंत्रालय से (राजस्व)	120,000,000.00		99,999,979.00	
एनडीएम कार्यक्रम स्कीम के लिए गृह मंत्रालय से (पूंजी)	490,000,000.00		257,900,000.00	
एनडीएम से एसएसपी कार्यक्रम के लिए प्राप्ति	-	**610,000,000.00**	-	**357,899,979.00**
बैंक ब्याज अन्य	5,095.00		1,948.00	
पीएफ के साथ पूंजीकृत एफडी पर ब्याज	-		3,356,050.00	
एफडी पर ब्याज(अन्य)	-		793,589.00	
एफडी ऑटो स्वीप	5,934,998.00		-	
पूंजीशीर्ष एफडी ऑटो स्वीप	4,917,933.00		-	
अन्य प्राप्तियां	89,098.00		-	
आकस्मिक व्यय के लिए स्टॉफ अग्रिम	-		5,580.00	
फर्नीचर की बिक्री	-		1,082,983.00	
लेनदार	-		23,632.00	
सुरक्षा जमा	15,000.00	**10,962,124.00**	15,000.00	**5,278,782.00**
प्रशिक्षण भत्तावसूली के रूप में प्राप्त किया	-		120,791.00	
त्यौहार अग्रिम के लिए स्टॉफ से प्राप्त	-	-	-	**120,791.00**
कुल		**734,693,660.98**		**508,325,932.87**
भुगतान				
पूंजी व्यय/अन्य देयताएं				
फर्नीचर और फिक्सर	46,500.00		14,990.00	
कार्यालय उपकरण	1,244,598.00		594,226.00	
निर्माणाधीन भवन (दक्षिणी परिसर)	150,287,758.00		65,954,175.30	
निर्माणाधीन भवन (रोहिणी परिसर)	172,956,329.00		183,842,538.00	
कार्यालय वाहन	688,822.00		-	
पुस्तकें	925,227.00		248,840.00	
एनआईडीएम दक्षिणी परिसर (मोबिलाइजेशन एडवांस)	-		28,615,036.00	
लेनदार	-		666,688.00	
सुरक्षा जमा	-		45,000.00	
सावधि जमा (दक्षिणी परिसर)	-	**326,149,234.00**	1,438,183.00	**281,419,676.30**
राजस्व व्यय				
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अग्रिम	550,191.00		-	
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं	39,863,740.00		32,085,038.00	
सरकार को भुगतान	-		5,590,595.00	
पीएलए	-	**40,413,931.00**	-	**37,675,633.00**
स्थापना व्यय				
वेतन और भत्ते	47,788,371.00		35,025,755.00	
यात्रा रियायत भत्ता/एलटीए	82,926.00		322,508.00	
मेडिकल	186,616.00		140,869.00	
ट्यूशन फीस	391,500.00		418,500.00	
एलटीसी व्यय	-	**48,449,413.00**	738,828.00	**36,646,460.00**
अन्य प्रशासनिक व्यय				
मरम्मत और रखरखाव	2,150,317.00		3,991,165.00	
डाक	420,834.00		142,477.00	
मुद्रण और स्टेशनरी	942,449.00		483,826.00	
किराया, दर और कर	14,864,400.00		29,641,913.00	
विविध व्यय	1,821,257.83		888,315.00	
समाचार-पत्र और पत्रिकाएं	227,112.00		54,390.00	
टेलीफोन व्यय	258,233.00		183,328.00	
विज्ञापन व्यय	115,291.00		23,757.00	

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

घरेलू यात्रा	1,478,479.00		1,455,736.00	
विदेश यात्रा	149,952.00		141,260.00	
व्यवसायिक व्यय	6,451,012.00		860,890.00	
प्रकाशन	1,724,235.00		504,138.00	
बैंक प्रभार	17,404.81		7,811.59	
अनुसंधान और विकास	-		422,038.00	
दक्षिण परिसर व्यय	-		69,404.00	
कार्यशाला के लिए अग्रिम भुगतान	300,000.00	**30,920,976.64**	-	**38,870,448.59**
सरकार को भुगतान				
एनपीएस ट्रस्ट को भुगतान (सीपीएफ)			4,339,946.00	
आकस्मिक व्यय के लिए स्टॉफ अग्रिम	-		16,176.00	
सरकार को अतिरिक्त आय की अदायगी	7,095,258.00	**7,095,258.00**	-	**4,356,122.00**
अंतिम शेष				
चैक जारी किया गया परंतु सावधि जमा के लिए नहीं	-		-	
बैंक बकाया (एफडी ऑटो स्वीप)	33,277,574.00		34,353,750.00	
बैंक बकाया (पूंजी शीर्ष एफडी ऑटो स्वीप)	248,491,388.00		74,884,007.00	
बैंक बकाया (चालू खाता)	1,308,248.34		1,532,802.24	
यूको बैंक बचत खाता	(1,412,362.00)	**281,664,848.34**	(1,412,966.26)	**109,357,592.98**
कुल		**734,693,660.98**		**508,325,932.87**

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 00977।एन

हस्ता/-
अनुपमा गोयल
(पार्टनर)
एम. नं. 046053
यूडीआईएन: 20046053AAAAAB4866

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18-08-2020

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ता/-
मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल
(कार्यकारी निदेशक)

हस्ता/-
सुरेन्द्र सिंह बिष्ट
(लेखा अधिकारी)

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय)
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखा टिप्पण

अनुसूची 1

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क) वित्तीय विवरण प्राप्ति आधार पर पुरान लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए जाते हैं (स्थापना व्यय, किराया, दर तथा कर, सहायक अनुदान के अतिरिक्त, जिनका लेखा जोखा नकदी के आधार पर रखा जाता है) और सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन व्यवहारों के अनुसरण में है।

ख) स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर भौतिक सत्यापन के लिए रखा जा रहा है और परियोजना के अतंर्गत अर्जित सभी स्थिर परिसंपत्तियों को उस वित्तीय वर्ष जिसमें वह आस्ति प्राप्त की गई थी, में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की लेखा बही में रखा जाता है। स्थिर आस्तियों को प्राप्ति की लागत और स्थापना की लागत, यदि हो, के साथ एक वर्ष में प्रभारित अवमूल्यन से घटाकर लिखा जाता है। स्थिर आस्तियों पर अवमूल्यन का प्रावधान आयकर अधिनियम की तहत निर्दिष्ट दरों के अनुसार किया जाता है।

ग) एनआईडीएम के स्टाफ के लिए पेंशन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में गृह मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2017 के पत्र संख्या 45-16/2012-एनडीएम-II के अनुसार एनडीआईएम ने 3 कर्मचारियों, जिन्होंने एनपीएस में राशि जमा करने का विकल्प नहीं दिया है, को छोड़कर 27 में से 24 कर्मचारियों की एनपीएस खाते में जमा की है। तथापि, जिन कर्मचारियों ने सेवा छोड़ दी है, अदालत और निधन के मामले में उनकी राशि (कर्मचारी और नियोक्ता अंशदान) एनआईडीएम के बैंक खाते में है।

घ) पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, जहां कही आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहीकृत किया गया है।

ङ) संस्थान के गृह मंत्रालय के साथ किराया करार को अभी अंतिम रुप दिया जाना है और संस्थान ने जनवरी 2018 तथा फरवरी 2018 के दो महीने की किराये की राशि 1,37,14,570 रुपए अदा कर दी है । वित्त वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के किराए की राशि भुगतान के लिए लम्बित है।

च) संस्थान में पीएफएमएस उपलब्ध नहीं है अतः सहायक संपदा निदेशक को बकाया भुगतान नहीं किया जा सका।

छ) विशेष रुपए से उल्लेखन की गई लेखांकन नीतियां अन्यथा सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन व्यवहारों के अनुरुप हैं।

2. **आकस्मिक देयताएं**

संस्थान के विरूद्ध दावों को ऋण के रूप में मान्यता नहीं दी गई - शून्य।

3. प्रबंधन की राय में व्यापार के सामान्य क्रम में वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम वसूली का मूल्य राशि से कम नहीं होगा जो बैलेंस शीट में दर्शायी गई है। सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान लेखा में किया गया है।

4. गृह मंत्रालय के दिनांक 23 मार्च, 2010 के पत्र संख्या 45-5/2008-एनडीएम-IV/II के माध्यम से एक अलग पब्लिक लेजर अकाउंट (पीएलए) रखा गया है और जमा से प्राप्त ब्याज सहित परियोजनाओं से सृजित निवल बचत भारत की संचित निधि में जमा कराई गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पीएलए के वित्तीय विवरण अलग से तैयार किए गए हैं।

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 009771एन

हस्ता/-
अनुपमा गोयल
(पार्टनर)
एम. नं. 046053
यूडीआईएनः 20046053AAAAAB4866

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः18-08-2020

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ता/-
मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल
(कार्यकारी निदेशक)

हस्ता/-
सुरेन्द्र सिंह बिष्ट
(लेखा अधिकारी)

अनुसूची 2: आरक्षितियां और अधिशेष		
विवरण	**31.03.2020 तक**	**31.03.2019 तक**
	रुपए	रुपए
आरक्षितियां और अधिशेष		
अथशेष	484,975,583.93	230,795,770.52
"**जोड़े:** वर्ष के दौरान आंतरिक आय पर व्यय के आधिक्य का अंतरण"	(199,023.64)	(3,720,186.59)
पूंजी शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त अनुदान		
- रोहिणी परिसर	260,000,000.00	157,900,000.00
- साउथ कैंपस	230,000,000.00	100,000,000.00
कुल	**974,776,560.29**	**484,975,583.93**

अनुसूची 3: वर्तमान देयताएं और प्रावधान		
विवरण	**31.03.2020 तक**	**31.03.2019 तक**
	रुपए	रुपए
स्टॉफ अंशदान भविष्य निधि		
अथशेष	8,598,301.00	8,598,301.00
जोड़े: - नियोक्ता अंशदान	-	-
- कर्मचारी अंशदान	-	-
भविष्य निधि पर ब्याज	-	-
	8,598,301.00	**8,598,301.00**
घटा: कर्मचारी को अदायगी	1,210,197.00	-
आवधि जमा पर प्राप्त ब्याज (बी जी) - सरकार को देय	**7,388,104.00**	**8,598,301.00**
Interest Accrued on FD(BG)-Payable to Govt.	164,147.00	-
सरकार को देय अन्य आय*	10,790,267.00	7,105,258.00
बयाना जमा राशि	211,298.00	211,298.00
देय व्यय	41,329,324.00	39,172,286.00
प्राप्त सुरक्षा राशि	71,809.00	71,809.00
सी जी एच एस	12,050.00	12,050.00
एनपीएस में नियोक्ता अंशदान	543,880.00	263,762.00
एनपीएस में नियोक्ता का देय अंशदान	646,190.00	380,865.00
कुल	**61,157,069.00**	**55,815,629.00**

*इस राशि में सावधि जमा में निवेश किए गए पूंजी अनुदानों पर अर्जित ब्याज शामिल हैं।

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय के अंतर्गत एवं स्वायत्त निकाय)

अनुसूची 4: वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर आस्तियों और अवमूल्यन का विवरण

क्र. सं.	विवरण	दर	01.04.2019 को डब्ल्यूडीवी	परिवर्धन		कटौती	कुल	वर्ष के लिए अवमूल्यन	31.03.2020 को डब्ल्यूडीवी
				180 दिन से अधिक	180 दिन से कम				
			रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
1	पुस्तकें	40%	189,068.00	164,171.00	937,305.00	-	1,290,544.00	328,757.00	961,787.00
2	कार्यालय उपकरण	15%	924,636.00	653,448.00	638,280.00	-	2,216,364.00	284,584.00	1,931,780.00
3	फर्नीचर और उपस्कर	10%	638,848.00	46,500.00	-	-	685,348.00	68,535.00	616,813.00
	संयत्र और मशीनरी								
4	संयत्र और	15%	346,138.00	-	-	-	346,138.00	51,921.00	294,217.00
5	वाहन (मारुति सियाज)	15%		688,822.00	-	-	688,822.00	103,323.00	585,499.00
	कंप्यूटर								
6	कंप्यूटर और मशीनरी	40%	42,655.00	-	350,214.00	-	392,869.00	87,105.00	305,764.00
7	सॉफ्टवेयर	40%	38.00	-	-	-	38.00	15.00	23.00
8	भूमि(रोहिणी परिसर)	0%	55,417,002.00	-	-	-	55,417,002.00	-	55,417,002.00
9	निर्माणाधीन भवन (दक्षिणी परिसर)	0%	110,312,694.30	78,909,134.00	60,394,272.00	-	249,616,100.30	-	249,616,100.30
10	निर्माणाधीन भवन (रोहिणी परिसर)	0%	248,725,460.00	85,187,009.00	108,461,697.00		442,374,166.00	-	442,374,166.00
कुल			**416,596,539.30**	**165,649,084.00**	**170,781,768.00**	**-**	**753,027,391.30**	**924,240.00**	**752,103,151.30**

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

nidm Resilient India - Disaster free India

अनुसूची 5: निवेश		
विवरण	**31.03.2020 तक**	**31.03.2019 तक**
	रुपए	रुपए
यूकों बैंक में सावधि जमा (अन्य)	33,277,574.00	36,399,451.00
सावधि जमा (बचत खाता)	246,889,058.00	75,774,067.00
प्राप्त ब्याज	-	-
सावधि जमा (दक्षिणी परिसर - बैंक)	1,602,330.00	1,438,183.00
कुल	**281,768,962.00**	**113,611,701.00**

अनुसूची 6: चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम		
विवरण	**31.03.2020 तक**	**31.03.2019 तक**
	रुपए	रुपए
क. <u>चालू आस्तियां</u>		
बैंक बकाया:		
यूकों बैंक खाता संख्या 1820020000924924	1,308,248.34	1,532,802.24
यूकों बैंक खाता संख्या 18200110067819	(1,412,362.00)	(1,412,966.26)
बैंक बकाया	**(104,113.66)**	**119,835.98**
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां		
सुरक्षा जमा	-	15,000.00
स्रोत पर वसूली योग्य काटा गया टैक्स	253,673.65	253,673.65
कार्यशाला के लिए अग्रिम	300,000.00	-
आकस्मिक व्यय के लिए अग्रिम	2,800.00	300.00
परिवहन अग्रिम	29,781.00	29,781.00
त्योहार अग्रिम	-	498.00
एलटीसी अग्रिम	-	-
पीएलए (विविध प्राप्तिखाते)	1,579,375.00	1,579,375.00
दक्षिणी परिसर (मोबिलाइजेशन एडवांस)	-	8,584,509.00
कुल	**2,061,515.99**	**10,582,972.63**

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

अनुसूची 7: गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान (डीएम-डिवीजन)		
विवरण	**2019-20**	**2018-19**
	रुपए	रुपए
गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	120,000,000.00	99,999,979.00
कुल	**120,000,000.00**	**99,999,979.00**

अनुसूची 8: संस्थापना व्यय (गृह मंत्रालय – अनुदान)		
विवरण	**2019-20**	**2018-19**
	रुपए	रुपए
वेतन और भत्ते	43,328,381.00	34,405,487.00
पेंशन अंशदान	3,574,443.00	2,226,702.00
यात्रा रियायत भत्ता/एलटीए	82,926.00	1,061,336.00
छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान	-	774,318.00
मेडिकल	186,616.00	140,869.00
ट्यूशन फीस	40,500.00	351,000.00
कुल	**47,212,866.00**	**38,959,712.00**

अनुसूची 9: अन्य प्रशासनिक व्यय (गृह मंत्रालय – अनुदान)		
विवरण	**2019-20**	**2018-19**
	रुपए	रुपए
ऑडिट फीस	23,600.00	23,600.00
मरम्मत और रखरखाव	2,523,554.00	4,052,765.00
डाक	300,263.00	131,407.00
मुद्रण और स्टेशनरी	942,449.00	483,826.00
विविध व्यय	1,645,845.83	976,489.00
समाचार-पत्र और पत्रिकाएं	143,699.00	56,972.00
टेलीफोन व्यय	262,828.00	165,913.00
विज्ञापन और प्रचार	115,291.00	23,757.00
घरेलू यात्रा	1,976,519.00	1,518,523.00
विदेश यात्रा	1,49,952.00	141,260.00
व्यवसायिक प्रभार	6,427,412.00	860,890.00
किराया, दर और कर	14,864,400.00	20,877,162.00
बैंक प्रभार	17,404.81	7,811.59
प्रकाशन	1,724,235.00	504,138.00
अनुसंधान और विकास	-	422,038.00
दक्षिणी परिसर व्यय	-	69,404.00
कुल	**31,117,452.64**	**30,315,955.59**

अनुसूची 10: प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय (गृह मंत्रालय-अनुदान)		
विवरण	**2019-20**	**2018-19**
	रुपए	रुपए
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला व्यय	40,944,465.00	20,681,769.00
जेएनयू को अनुदान	-	10,557,000.00
कुल	**40,944,465.00**	**31,238,769.00**

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

अनुसूची 11: प्राप्त ब्याज

विवरण	2019-20	2018-19
	रुपए	रुपए
सावधि जमा पर ब्याज	6,869,415.00	2,839,290.00
अन्य ब्याज	5,095.00	1,948.00
कुल	**6,874,510.00**	**2,841,238.00**

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 009771एन

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ता/-
अनुपमा गोयल
(पार्टनर)
एम. नं. 046053
यूडीआईएनः 20046053AAAAAB4866

हस्ता/-
मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल
(कार्यकारी निदेशक)

हस्ता/-
सुरेन्द्र सिंह बिष्ट
(लेखा अधिकारी)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः18-08-2020

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

पब्लिक लेजर अकांउट (पीएलए)
(राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान)
(गृह मंत्रालय)

31 मार्च, 2020 तक पीएलए बैलेंस शीट

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2020	31.03.2098
		रुपए	रुपए
संचित निधि और देयताएं			
पूंजी और आरक्षिती तथा अधिशेष	1	731,560	731,560
निर्धारित राशि	2	8,112,024	7,013,269
चालू देयताएं और प्रावधान	3	3,999,989	2,013,092
कुल		**12,843,573**	**9,757,921**
आस्तियां			
चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम	4	12,843,573	9,757,921
कुल		**12,843,573**	**9,757,921**

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 009771एन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ता/-
अनुपमा गोयल
(पार्टनर)
एम. नं. 046053
यूडीआईएनः 20046053AAAAAB4866

हस्ता/-
मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल
(कार्यकारी निदेशक)

हस्ता/-
सुरेन्द्र सिंह बिष्ट
(लेखा अधिकारी)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः18-08-2020

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रुप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

पब्लिक लेजर अकांउट (पीएलए)
(राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान)
(गृह मंत्रालय)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रुपए में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
	रुपए	रुपए
आय		
ब्याज आय	13,312.00	15,118.00
विविधि प्राप्ति	1,716,118.00	63,639.00
सावधि जमा पर ब्याज	691,644.00	325,001.00
कुल (क)	**2,421,074.00**	**403,758.00**
व्यय		
बैंक प्रभार	729.85	41.30
कुल (ख)	**729.85**	**41.30**
अधिशेष/कम होने के कारण बकाया (क-ख)	**2,420,344.15**	**403,716.70**
घटाएं: पीएओ, एमएचए को अंतरित बचत	2,420,344.15	403,716.70
अधिशेष/कम होने के कारण बैलेंश शीट में ले जाया गया बकाया	-	-

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 009771एन

हस्ता/-
अनुपमा गोयल
(पार्टनर)
एम. नं. 046053
यूडीआईएन: 20046053AAAAAB4866

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ता/-
मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल
(कार्यकारी निदेशक)

हस्ता/-
सुरेन्द्र सिंह बिष्ट
(लेखा अधिकारी)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:18-08-2020

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रुप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

पब्लिक लेजर अकांउट (पीएलए)
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय)
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि रुपए में)

विवरण	31.03.2020		31.03.2019	
प्राप्तियां				
अथशेष				
यूको बैंक (बचत खाता)	1,000,673.78		27,963.08	
सावधि जमा	8,757,247.00	9,757,920.78	5,004,001.00	5,031,964.08
वर्ष के दौरान प्राप्तियां				
1. ऑनलाइन पाठ्यक्रम से प्राप्ति	99,500.00		91,500.00	
2. सरकार के लिए एफडी पर प्राप्त ब्याज	691,644.00		322,846.00	
3. केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड	400,000.00		-	
4. बाल केंद्रित डीआरआर-यूनीसेफ परियोजना से प्राप्त राशि	7,334,015.00		774,950.00	
5. विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्ति	3,900,000.00		-	
6. एनडीएमपी परियजना से प्राप्ति	1,609,286.00		-	
7. विज्ञान और प्रौद्यौगिकी से प्राप्तियां	201,120.00		4,683,472.00	
8. जलवायु परिवर्तन परियोजना से प्राप्त राशि	-	14,235,565.00	615,000.00	6,487,768.00
अन्य प्राप्तियां				
1. विविध प्राप्तियां	231,056.00		63,639.00	
2. प्राप्त ब्याज	13,312.00	244,368.00	17,273.00	80,912.00
कुल		**24,237,853.78**		**11,600,644.08**
भुगतान				
परियोजना व्यय				
1. बाल केंद्रित डीआरआर-यूनीसेफ परियोजना से प्राप्त राशि	4,776,334.00		575,266.00	
2. जलवायु परिवर्तन (एमओईएफ/यूएनडीपी) से प्राप्त राशि	92,645.00		509,542.00	
3. विश्व स्वास्थ्य संगठन परियोजना पर व्यय	1,044,351.00		-	
4. एनडीएमपी परियोजना पर व्यय	1,535,272.00		-	
5. यूजीसी परियोजना	681,906.00		-	
6. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से प्राप्त	2,752,795.00		-	
7. व्यय के लिए अग्रिम अदायगी	124,808.00	11,008,111.00	-	1,084,808.00
अन्य व्यय/भुगतान				
1. सरकार को देयता	-		757,874.00	
2. बैंक प्रभार	729.85		41.30	
3. गृह मंत्रालय को दी गई परियोजना बचत	403,717.00	404,446.85	-	757,915.30
अंतिम शेष				
यूको बैंक (बचत खाता)	23,740.93		1,000,673.78	
सावधि जमा	12,801,555.00	12,825,295.93	8,757,247.00	9,757,920.78
कुल		**24,237,853.78**		**11,600,644.08**

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 009771एन

हस्ता/-
अनुपमा गोयल
(पार्टनर)
एम. नं. 046053
यूडीआईएन:20046053AAAAAB4866

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक:18-08-2020

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ता/-
मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल
(कार्यकारी निदेशक)

हस्ता/-
सुरेन्द्र सिंह बिष्ट
(लेखा अधिकारी)

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रुप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (पीएलए)

अनुसूची 1: संचित/ पूंजी निधि

(राशि रुपए में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
	रुपए	रुपए
अथशेष	731,560.00	731,560.00
	731,560.00	**731,560.00**

अनुसूची 2: निर्धारित निधि

	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
		रुपए	रुपए
1.	न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण से 'आपदा प्रबंधन प्लान' तैयार करने के लिए प्राप्त राशि		
	अथशेष	770,249.00	770,249.00
	जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
	घटा: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-
	घटा: सरकारी कोष में देय बचत	770,249.00	-
		-	770,249.00
2.	विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त राशि, परियोजना व्यय		
	अथशेष	-	-
	वर्ष के दौरान प्राप्त	3,900,000.00	-
	घटा: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	1,140,809.00	-
		2,759,191.00	-
3.	ऑनलाइन – पाठ्यक्रम से प्राप्त राशि		
	अथशेष	172,500.00	81,000.00
	वर्ष के दौरान प्राप्त	99,500.00	91,500.00
		272,000.00	172,500.00
	घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	-	-
	घटा: सरकारी कोष में देय बचत	272,000.00	-
		-	172,500.00
4.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्राप्त राशि (कैप-रस परियोजना)		
	अथशेष	4,683,472.00	-
	वर्ष के दौरान प्राप्त	201,120.00	4,683,472.00
		4,884,592.00	4,683,472.00
	घटा: सरकारी कोष में देय बचत	-	-
	घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	2,759,327.00	-
		2,125,265.00	4,683,472.00
5.	आईआरएस मॉड्यूल तैयार करने के लिए यूएसएआईडी से प्राप्त राशि		
	अथशेष	400,000.00	400,000.00
	वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
		400,000.00	400,000.00
	घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	400,000.00	-
	घटा: सरकारी कोष में देय बचत	-	-
			400,000.00
6.	यूजीसी से प्राप्त राशि		
	अथशेष	681,906.00	681,906.00
	वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
		681,906.00	681,906.00
	घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	681,906.00	-
		-	681,906.00
7.	जलवायु परिवर्तन (एमओईएफ/यूएनडीपी) से प्राप्त राशि		
	अथशेष	105,458.00	-
	वर्ष के दौरान प्राप्त	-	615,000.00
		105,458.00	615,000.00
	घटा: सरकारी कोष में देय बचत	12,813.00	509,542.00
	घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	92,645.00	-
		-	105,458.00

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

8.	बाल केंद्रित डीआरआर-यूनीसेफ परियोजना से प्राप्त राशि		
	अथशेष	199,684.00	-
	वर्ष के दौरान प्राप्त	7,344,015.00	774,950.00
		7,543,699.00	774,950.00
	घटा: सरकारी कोष में देय बचत	-	-
	घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	4,776,334.00	575,266.00
		2,767,365.00	199,684.00
9.	केन्द्रीय प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड से प्राप्त राशि		
	अथशेष	-	-
	वर्ष के दौरान प्राप्त	400,000.00	-
		400,000.00	-
	घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	-	-
		400,000.00	-
10.	एनएडीएमपी परियोजना से प्राप्त राशि		
	अथशेष	-	-
	वर्ष के दौरान प्राप्त	1,600,000.00	-
		1,600,000.00	
	घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	1,539,797.00	-
		60,203.00	-
	कुल	**8,112,024.00**	**7,013,269.00**

अनुसूची 3: चालू देयताएं और प्रावधान

विवरण		**31.03.2020**	**31.03.2019**
		रुपए	रुपए
	सरकारी खाते में देय परियोजना बचत	2,420,343.93	403,717.00
	रिचा श्रीवास्तव	270.00	-
	बयाना राशि सुरक्षा जमा	-	30,000.00
	एनआईडीएम (मुख्य खाता)	1,579,375.00	1,579,375.00
	कुल	**3,999,988.93**	**2,013,092.00**

अनुसूची 4: चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

विवरण		**31.03.2020**	**31.03.2019**
		रुपए	रुपए
	(क) चालू आस्तियां		
	नकद राशि	-	-
	बैंक बकाया:		
	यूको बैंक खाता संख्या 6139	23,740.93	1,000,673.78
	सावधि जमा (एफडीडी)	12,801,555.00	8,757,247.00
	(ख) ऋण तथा अग्रिम		
	सीएपी-आरईएस अग्रिम लेखा	15,000.00	-
	एनएडीएमपी परियोजना अग्रिम लेखा	277.00	-
	विश्व स्वास्थ्य संगठन परियोजना अग्रिम	3,000.00	-
	कुल	**12,843,572.93**	**9,757,920.78**

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रुप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

अध्याय 8

अनुबंध

अध्याय 8: अनुबंध

अनुबंधों की सूची

8.1	अनुबंध-I	:	संस्थान के साधारण निकाय के सदस्यों की सूची
8.2	अनुबंध-II	:	संस्थान के शासी निकाय के सदस्यों की सूची
8.3	अनुबंध-III	:	एनआईडीएम द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची

8.1 अनुबंध-I: संस्थान के साधारण निकाय के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	सदस्य	पद
1.	केन्द्रीय गृहमंत्री, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001	अध्यक्ष
2.	उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ट्रामा सेंटर, एम्स, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष
3.	सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ट्रॉमा सेंटर, एम्स, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	सदस्य
4.	केंद्रीय गृह सचिव, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001	सदस्य
5.	सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
6.	सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
7.	सचिव, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
8.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	सदस्य
9.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली	सदस्य
10.	सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
11.	सचिव, अंतरिक्ष विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली	सदस्य
12.	सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, महासागर भवन, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003	सदस्य
13.	सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य

क्र.सं.	सदस्य	पद
14.	अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
15.	सचिव / अपर सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ट्रॉमा सेंटर, एम्स, ए -1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	सदस्य
16.	महानिदेशक, सिविल डिफेंस एवं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ईस्ट ब्लॉक -7, लेवल -7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली - 66	सदस्य
17.	एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख, डॉक्ट्राइन ऑरगेनाईजेशन एण्ड ट्रेनिंग (डीओटी), आईडीएस, मुख्यालय इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टॉफ, 23 साउथ हटमेंट्स, कश्मीर हाउस, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली - 110001	सदस्य
18.	सचिव (आपदा प्रबंधन), गुजरात सरकार, राजस्व विभाग, ब्लॉक - 11, तीसरा तल, न्यू सचिवालय, गांधीनगर - 382010	सदस्य
19.	सचिव (आपदा प्रबंधन), आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना – 800015	सदस्य
20.	उप-कुलपति, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली - 110006	सदस्य
21.	निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी – 248179	सदस्य
22.	निदेशक, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, शिवरामपल्ली, हैदराबाद – 500 052	सदस्य
23.	महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, मौसम भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली	सदस्य
24.	निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता, जोका, डी.एच. रोड, कोलकाता - 700 104	सदस्य
25.	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की, उत्तराखंड	सदस्य
26.	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	सदस्य
27.	निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
28.	महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
29.	महानिदेशक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास अकादमी, राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500 030	सदस्य
30.	महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, वी. रामलिंगमस्वामी भवन, अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110 029	सदस्य
31.	अध्यक्ष, उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार आयोग, 159 श्रद्धा कुंज, वसंत विहार, चकराता रोड, देहरादून	सदस्य
32.	राष्ट्रीय भूकंप संबंधी सलाहकार, गृह मंत्रालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य

क्र.सं.	सदस्य	पद
33.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय साधारण बीमा निगम, सुरक्षा, जे टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020	सदस्य
34.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 2, एन.एस. रोड, कोलकाता - 700 001	सदस्य
35.	अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ(फिक्की), फेडरेशन हाउस, नई दिल्ली	सदस्य
36.	अध्यक्ष, कान्फैडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री(सीआईआई), कोर 4-ए, चौथा तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली - 110 003	सदस्य
37.	निदेशक, अखिल भारतीय आपदा शमन संस्थान,साकार पांच, नजदीक नटराज सिनेमा, आश्रम रोड़, अहमदाबाद- 9	सदस्य
38.	महासचिव, इंडियन रेडक्रास सोसायटी, 1 रेडक्रास रोड़, नई दिल्ली	सदस्य
39.	निदेशक, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीटयूट, उप्पल रोड़, अहमदाबाद - 500007	सदस्य
40.	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	सदस्य
41.	प्रोफेसर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ए-विंग, चौथा तल, एनडीसीसी-II बिल्डिंग, जयसिंह रोड़, नई दिल्ली - 110001	सदस्य
42.	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ए-विंग, चौथा तल, एनडीसीसी-II बिल्डिंग, जयसिंह रोड़, नई दिल्ली - 110001	सदस्य सचिव

8.2 अनुबंध-II: संस्थान के शासी निकाय के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	सदस्य	पद
1.	उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ट्रामा सेंटर, एम्स, ए -1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	केंद्रीय गृह सचिव, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -110001	उपाध्यक्ष
3.	अपर सचिव एवं प्रभारी, आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
4.	सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
5.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली	सदस्य
6.	सचिव, अंतरिक्ष विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली	सदस्य
7.	सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ट्रॉमा सेंटर, एम्स, ए -1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	सदस्य
8.	अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
9.	प्रधान सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, असम सरकार, असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम	सदस्य
10.	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, 315, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	सदस्य
11.	निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता, जोका, डी.एच. रोड, कोलकाता -700 104	सदस्य
12.	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की-267667, उत्तराखंड	सदस्य
13.	निदेशक, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उप्पल रोड़, अहमदाबाद-500007	सदस्य
14.	उप-कुलपति, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली -110006	सदस्य
15.	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ए-विंग, चौथा तल, एनडीसीसी-II बिल्डिंग, जयसिंह रोड़, नई दिल्ली 110001	सदस्य सचिव

8.3 अनुबंध-III: एनआईडीएम द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
1.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा समुत्थानशीलता	एनआईडीएम, नई दिल्ली	22-26 अप्रैल, 2019	प्रो० सूर्य प्रकाश	43
2.	डीआरआर और सीएए का ग्रामीण विकास नीतियों और कार्यक्रमों में एकीकरण	जीएसडीएमए, गुजरात	24-27 अप्रैल, 2019	डा० सुषमा गुलेरिया	23
3.	पीआरआई क्षेत्र में डीआरआर को मुख्य धारा में लाना	जीएसडीएमए, गुजरात	24-27 अप्रैल, 2019	श्री शेखर चतुर्वेदी	23
4.	शिक्षा क्षेत्र में डीआरआर को मुख्य धारा में लाना	जीएसडीएमए, गुजरात	30 अप्रैल - 2 मई, 2019	डा० अजिंदर वालिया	17
5.	अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना में डीआरआर को मुख्य धारा में लाना	जीएसडीएमए, गुजरात	30 अप्रैल - 2 मई, 2019	डा० आमिर अली खान	16
6.	आपदा पश्चात् आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) तथा दीर्घकालिक बहाली	एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर	01-03 मई, 2019	प्रो० संतोष कुमार, श्री शेखर चतुर्वेदी	81
7.	आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएम): मूल और मध्यस्थ	आईएलडीएम, केरल	6-10 मई, 2019	प्रो० संतोष कुमार, श्री शेखर चतुर्वेदी	44
8.	पूर्व चेतावनी एवं संचार	एनआईडीएम, नई दिल्ली	13-17 मई, 2019	प्रो० सूर्य प्रकाश	30
9.	जलवायु एवं आपदा समुत्थानशीलता (एन. ढाका निगम के अधिकारियों के लिए)	एआईआईएलएसजी (चेन्नई)	20-24 मई, 2019	प्रो० अनिल कुमार गुप्त	13
10.	आपदा प्रबंधन योजना का ग्राम पंचायत योजनाओं से एकीकरण	जीआईडीएम और एनआईआरडी, हैदराबाद	27-31 मई, 2019	डा० सुषमा गुलेरिया	46
11.	जेंडर तथा आपदा प्रबंधन	ए.टी.आई नैनीताल	27-31 मई, 2019	डा० अजिंदर वालिया	32
12.	भूकम्प जोखिम न्यूनीकरण, आपदा प्रबंधन के तकनीकी ढंग तथा इंजीनियरों, वास्तुकारों और नगर योजनाकारों के लिए भवन निर्माण उप-नियम	मणिपुर सरकार / डीएमआई	28-29 मई, 2019	डा० आमिर अली खान	40
13.	भूकम्प जोखिम न्यूनीकरण	एचआईपीए, शिमला	10-14 जून, 2019	डा० आमिर अली खान	29
14.	जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय क्षेत्र विकास तथा भू-स्खलन प्रबंधन	केरल, केएसडीएमए	10-14 जून, 2019	प्रो० सूर्य प्रकाश	36
15.	आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएम): मूल और मध्यस्थ	यशादा, पुणे	17-21 जून, 2019	प्रो० संतोष कुमार, श्री शेखर चतुर्वेदी	27
16.	सीपीडब्लयूडी इंजीनियरों के लिए आपदा प्रबंधन योजना	वाईएमसीए, नई दिल्ली	18-20 जून, 2019	प्रो० प्रो० चंदन घोष डा० आमिर अली खान	26

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
17.	आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यशाला	श्रम और रोजगार मंत्रालय/ वीवीजीएनएलआई,नोएडा	24-28 जून, 2019	प्रो० सूर्य प्रकाश	26
18.	स्कूल सुरक्षा योजना तथा सुरक्षा ऑडिट	जे. एण्ड के. इम्पाई, श्रीनगर	24-28 जून, 2019	डा० आमिर अली खान	34
19.	आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएम): मूल और मध्यस्थ	एमजीएसआईपीए	25-28 जून, 2019	श्री शेखर चतुर्वेदी	34
20.	जलवायु परिवर्तन तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में समुत्थानशीलता	डीएआईसी, दिल्ली	26-28 जून, 2019	प्रो० अनिल कुमार गुप्त	28
21.	सीपीडब्लयूडी के लिए आपदा प्रबंधन योजना	अगरतला	3-5 जुलाई, 2019	प्रो० चंदन घोष	26
22.	सूखा प्रबंधन	एपीएचआरडीआई, विशाखापट्टनम	16-18 जुलाई, 2019	प्रो० सूर्य प्रकाश	55
23.	स्कूल सुरक्षा आपदा प्रबंधन योजना पर प्रशिक्षण कार्यशाला	एमजीएसआईपीए, चंडीगढ़	22-24 जुलाई, 2019	डा० रितु राज	95
24.	जेंडर तथा आपदा प्रबंधन	नई दिल्ली	22-26 जुलाई, 2019	डा० अजिंदर वालिया	41
25.	नगर विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने (शहरी समुत्थानशीलता) पर टीओटी कार्यक्रम	जीएसडीएमए, गांधीनगर, गुजरात	24-26 जुलाई, 2019	प्रो० अनिल कुमार गुप्त	23
26.	वानिकी क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु समुत्थानशीलता	टीएफआरआई जबलपुर	5-9 अगस्त, 2019	डा० ए डी कौशिक, प्रो० अनिल कुमार गुप्त	45
27.	ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से सुरक्षा की संस्कृति स्थापित करना	एसआईपीएआरडी, अगरतला	6-8 अगस्त, 2019	डा० रितु राज	27
28.	जलवायु परिवर्तन तथा अति विषम मौसम की परिस्थितियां	एनआईडीएम, नई दिल्ली	6-8 अगस्त, 2019	प्रो० सूर्य प्रकाश	74
29.	सीसीडीआर पर प्रबोधन प्रशिक्षण कार्यक्रम	ओएसडीएमए, ओडिशा	7-8 अगस्त, 2019	डा० कुमार राका, डा० बालू आई	44
30.	शहरी विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य धारा में लाना	एनआईडीएम, नई दिल्ली	19-21 अगस्त, 2019	डा० चंद्रानी बंद्योपाध्याय, श्री शेखर चतुर्वेदी	23
31.	स्कूल सुरक्षा योजना और सुरक्षा ऑडिट	एसडीएमए त्रिपुरा	19-21 अगस्त, 2019	डा० आमिर अली खान	40
32.	सीसीडीआरआर पर प्रबोधन प्रशिक्षण कार्यक्रम	एपीएचआरडीआई, बापटला	20-21 अगस्त, 2019	श्रीमति अशारोसे, डा० कुमार राका तथा डा० बालू आई.	48
33.	सीसीडीआरआर पर प्रबोधन प्रशिक्षण कार्यक्रम	यशादा, पुणे	27-28 अगस्त, 2019	डा० कुमार राका, डा० बालू आई	59

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
34.	स्कूल सुरक्षा	एचसीएम-आरआईपीए, जयपुर	28-30 अगस्त, 2019	डा० रितु राज, डा० ए डी कौशिक	56
35.	तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा समुत्थानशीलता	एचपीएचआरडीआई, आंध्रप्रदेश विशाखापट्टनम	03-05 सितंबर, 2019	प्रो० सूर्य प्रकाश	120
36.	शहरी जोखिम न्यूनीकरण: शहरों को समुत्थानशील बनाना	टीएनआईयूएस, कोयंबटूर	12-14 सितंबर, 2019	डा० चंद्रानी बंद्योपाध्याय	69
37.	सीसीडीआरआर पर प्रबोधन प्रशिक्षण कार्यक्रम	डॉ० एमसीआर एचआरडीआई तेलंगाना	16-17 सितंबर, 2019	डा० कुमार राका, डा० बालू आई	50
38.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण को स्कूल शिक्षा की मुख्यधारा में लाना	एनआईडीएम, नई दिल्ली	16-18 सितंबर, 2019	डा० अजिंदर वालिया	43
39.	वानिकी, वन्यजीवन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण	एफआरआई, देहरादून	16-20 सितंबर, 2019	डा० ए डी कौशिक, प्रो० अनिल कुमार गुप्त	20
40.	स्कूल सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	पोर्ट ब्लेयर	19-21 सितंबर, 2019	डा० रितु राज	80
41.	सीसीडीआरआर पर संकाय विकास कार्यक्रम	यशादा, पुणे	24-25 सितंबर, 2019	डा० कुमार राका	71
42.	सांस्कृतिक विरासत के स्थलों और संग्रहालयों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला	यशादा, पुणे	23-26 सितंबर, 2019	डा० चंद्रानी बंद्योपाध्याय	44
43.	निर्मित पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भूकम्प जोखिम शमन तथा प्रबंधन	एसडीएमए शिलांग	25-27 सितंबर, 2019	डा० आमिर अली खान	51
44.	कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना (ओडीएमपी) तैयार करना	एनआईडीएम, नई दिल्ली	25-27 सितंबर, 2019	डा० सुषमा गुलेरिया	50
45.	सतत विकास के लिए आपदा समुत्थानशील तथा हरित वृद्धि	कान्सटीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	26-27 सितंबर, 2019	प्रो० अनिल कुमार गुप्त	222
46.	सीसीडीआरआर पर प्रबोधन प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईएलडीएम, केरल	3-4 अक्टूबर, 2019	डा० कुमार राका, डा० बालू आई.	49
47.	ग्राम आपदा प्रबंधन योजना	जीआईपीएआरडी, गोवा	3-5 अक्टूबर, 2019	डा० अजिंदर वालिया	43

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
48.	अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना	एचपीएसडीएमए/ डॉ. राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज	9-11 अक्टूबर, 2019	डा० आमिर अली खान डा० सुषमा गुलेरिया	23
49.	भारतीय रेल के अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	भारतीय रेलवे आपदा प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु	14-16 अक्टूबर, 2019	श्री शेखर चतुर्वेदी	110
50.	बाढ़ जोखिम प्रबंधन तथा जल क्षेत्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण	एनआईएच, रुड़की	14-18 अक्टूबर, 2019	डा० ए डी कौशिक, प्रो० अनिल कुमार गुप्त	40
51.	आपदा पश्चात् आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) तथा दीर्घकालिक बहाली	एचसीएम आरआईपीए	21-23 अक्टूबर 2019	प्रो० संतोष कुमार	45
52.	आपदा के दौरान प्रसारण प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यशाला	नैशनल अकैडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एण्ड मल्टीमीडिया, नई दिल्ली	04 - 11 नवम्बर, 2019	प्रो० सूर्य प्रकाश	22
53.	वनाग्नि जोखिम प्रबंधन तथा प्रतिक्रिया	एफआरआई, देहरादून	04-08 नवम्बर, 2019	डा० ए डी कौशिक, प्रो० अनिल कुमार गुप्त	35
54.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन	एपीएचआरडीआई, विशाखापट्टनम	06-08 नवम्बर, 2019	डा० चंद्रानी बंद्योपाध्याय	106
55.	ग्रामीण विकास नीतियों और कार्यक्रमों तथा पीआरआई क्षेत्र से आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एकीकरण	एचआईपीए, शिमला	06-08 नवम्बर, 2019	डा० सुषमा गुलेरिया	41
56.	बड़ी सभाओं में भीड़ का प्रबंधन	आईएलडीएम, केरल	11-13 नवम्बर, 2019	श्री शेखर चतुर्वेदी	54
57.	मूलभूत संरचना तथा आपदा समुत्थानशील निर्माण तकनीक में आपदा प्रबंधन को मुख्य रूप से समाहित करना	ए.टी.आई , छत्तीसगढ़	13-15 नवम्बर, 2019	डा० आमिर अली खान	25
58.	आईआरएस: ऑपरेटिंग सेक्शन चीफ	एनआईडीएम, नई दिल्ली	18-20 नवम्बर, 2019	प्रो० संतोष कुमार, श्री शेखर चतुर्वेदी	13
59.	सीसीडीआरआर पर प्रबोधन प्रशिक्षण कार्यक्रम	पोर्ट ब्लेयर	20-22 नवम्बर, 2019	डा० कुमार राका, डा० बालू आई.	75
60.	आपदा पश्चात् आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) तथा दीर्घकालिक बहाली	ए.टी.आई नैनीताल, उत्तराखंड	21-23 नवम्बर, 2019	प्रो० संतोष कुमार	108
61.	आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	26-28 नवम्बर, 2019	प्रो० संतोष कुमार, डा० चंद्रानी बंद्योपाध्याय	49
62.	पंचायती राज क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य धारा में लाना	डीडीयूएसआईआरडी, लखनऊ, यूपी	27-29 नवम्बर, 2019	श्री शेखर चतुर्वेदी	37
63.	डीआरआर और सीसीए का ग्रामीण विकास में एकीकरण	यूआईआरडी, रुद्रपुर, उत्तराखण्ड	04-06 दिसंबर, 2019	डा० सुषमा गुलेरिया	42

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
64.	स्कूल सुरक्षा योजना और सुरक्षा ऑडिट	ए.टी.आई , मैसूरु	04-06 दिसंबर, 2019	डा० आमिर अली खान	30
65.	सीसीडीआरआर पर प्रबोधन प्रशिक्षण कार्यक्रम	एमएटीआई, शिलांग	05-06 दिसंबर, 2019	डा० कुमार राका, डा० बालू आई	40
66.	जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय क्षेत्र विकास तथा भूस्खलन प्रबंधन	आईआईटी, रुड़की	05-07 दिसंबर, 2019	प्रो० सूर्य प्रकाश	49
67.	एसडीजी 11: शहरों और समुदायों में समुत्थानशीलता सृजन	यशादा, पुणे	11-13 दिसंबर, 2019	डा० चंद्रानी बंद्योपाध्याय	50
68.	आपदा का सर्वप्रथम सामने करने वालों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण	जीएए, ओडिशा	11-13 दिसंबर, 2019	श्री शेखर चतुर्वेदी	40
69.	सीसीडीआरआर पर संकाय विकास कार्यक्रम	एमसीआरएचआरडीआईटी, हैदराबाद	12-13 दिसंबर, 2019	डा० कुमार राका, डा० बालू आई	35
70.	आपदा प्रबंधन में मनोसामाजिक देखभाल	यशादा, पुणे	16-18 दिसंबर, 2019	डा० अजिंदर वालिया	38
71.	स्कूल आपदा प्रबंधन योजना	डॉ. एमसीएचआरडीआई तेलंगाना	17-19 दिसंबर, 2019	डा० आमिर अली खान	31
72.	आपदा का सर्वप्रथम सामने करने वालों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण	एचसीएम-आरआईपीए, राजस्थान	18-20 दिसंबर, 2019	श्री शेखर चतुर्वेदी	23
73.	सुशासन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण	सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, हैदराबाद	18-20 दिसंबर, 2019	प्रो० संतोष कुमार	30
74.	आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एमजीएसआईपीए, चंडीगढ़	26-28 दिसंबर, 2019	श्री शेखर चतुर्वेदी	50
75.	आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस): मूल और मध्यस्थ	एमसीएचआरडीआई, हैदराबाद	06-10 जनवरी, 2020	श्री शेखर चतुर्वेदी	39
76.	संग्रहालय प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण	एनआईडीएम, नई दिल्ली	06-08 जनवरी, 2020	डा० चंद्रानी बंद्योपाध्याय	32
77.	तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा समुत्थानशीलता	दमन और दीव	06-10 जनवरी, 2020	प्रो० सूर्य प्रकाश	108
78.	सीसीडीआरआर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एचसीएम-आरआईपीए	06-10 जनवरी, 2020	डा० कुमार राका	81
79.	परिवर्तनशील जलवायु में आपदा और स्वास्थ्य:निवारण, तैयारी और प्रतिक्रिया	वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल और एओईएच	20-24 जनवरी, 2020	प्रो० अनिल कुमार गुप्त, श्री आशीष के पांडा	78
80.	सीसीडीआरआर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एपीएचआरडीआई, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	21-23 जनवरी, 2020	डा० कुमार राका, डा० बालू आई.	134
81.	पूर्व चेतावनी एवं संचार	लक्षद्वीप	22-23 जनवरी, 2020	प्रो० सूर्य प्रकाश	72
82.	सीसीडीआरआर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	सिपार्ड , अगरतला	27-31 जनवरी, 2020	डा० बालू आई	76
83.	आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	विज्ञान प्रसार, नोएडा	27-31 जनवरी, 2020	डा० अजिंदर वालिया	36

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
84.	डीआरआर और सीएए का ग्रामीण विकास नीतियों और कार्यक्रमों में एकीकरण	एनआईआरडी, गुवाहाटी	27-31 जनवरी, 2020	डा० सुषमा गुलेरिया	43
85.	एथियोपिया सरकार के शिष्टमंडल का भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए की गई पहलों के संबंध में एक दूसरे से सीखने और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए आगमन	बेंगलुरु, एडीपीसी	27-29 जनवरी, 2020	प्रो० अनिल कुमार गुप्ता	41
86.	सीसीडीआरआर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईआरडी, गुवाहाटी	03-07 फरवरी, 2020	डा० बालू आई	45
87.	भू-मौसम विज्ञान जोखिमों संबंधी खतरों का प्रबंधन	डीटीयू, नई दिल्ली	10-14 फरवरी, 2020	डा० कुमार राका, डा० बालू आई.	146
88.	अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना	एनआईडीएम, नई दिल्ली	10-14 फरवरी, 2020	प्रो० सूर्य प्रकाश	36
89.	पंचायती राज क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य धारा में लाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	यशादा, पुणे	10-14 फरवरी, 2020	श्री शेखर चतुर्वेदी	148
90.	सीसीडीआरआर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एएनयू कैंपस, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	18-22 फरवरी, 2020	डा० बालू आई	120
91.	गेल अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	गेल नोएडा, यू.पी.	19-20 फरवरी, 2020	प्रो० सूर्य प्रकाश	23
92.	“आपदा प्रभावित क्षेत्रों की महिलाओं के लिए कौशल विकास” पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईईएसबीयूडी, गौतमबुद्धनगर	24-28 फरवरी, 2020	डा० अजिंदर वालिया	45
93.	क्षेत्रीय एच.ई.एल.पी. (बड़ी जनसंख्याओं में स्वास्थ्य सम्बंधी आपात परिस्थितियां) पाठ्यक्रम	आईआईएचएमआर, नई दिल्ली	24 फरवरी 06 मार्च, 2020	प्रो० अनिल कुमार गुप्त, श्री आशीष के पांडा	24
94.	सीसीडीआरआर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	ए.टी.आई , पंजाब	24-28 फरवरी, 2020	डा० कुमार राका	112
95.	आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनईआरआईएसटी	27-29 फरवरी, 2020	प्रो० सूर्य प्रकाश	206

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
96.	पर्यावरण, जैव विविधता तथा आपदा जोखिम प्रबंधन विषय पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी)	बीबीएयू, लखनऊ	2-6 मार्च, 2020	प्रो० अनिल कुमार गुप्त, श्री आशीष के पांडा	105
97.	शिशु केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	मनोमनियमसुंदरनार विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	2-6 मार्च, 2020	डा० बालू आई	70
98.	संकाय तथा विद्यार्थीयों के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रबोधन कार्यक्रम	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार	4-5 मार्च, 2020	प्रो० संतोष कुमार	325
99.	एनटीआईपीआरआईटी के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, नई दिल्ली	4-5 मार्च, 2020	डा० आमिर अली खान	16
100.	शहरी जोखिम न्यूनीकरण-शहरों को समुत्थानशील बनाना	राजमुंदरी, क्षेत्रीय केंद्र, ए.पी.	5-7 मार्च, 2020	डा० चंद्रानी बंद्योपाध्याय	28
				कुल	**5646**

वर्ष 2019-20 के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	तिथियां	प्रतिभागियों की संख्या
बेसिक पाठ्यक्रम			
1.	व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क-1	1 सितंबर से 11 अक्टुबर	52
3.	व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क-2	8 सितंबर से 19 अक्टुबर	36
विषयगत पाठ्यक्रम			
3.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन	16 दिसंबर से 12 जनवरी	24
4.	आपदा बहाली और पुनर्निर्माण का लैंगिक पक्ष	16 दिसंबर से 12 जनवरी	22
5.	जोखिम आकलन	4 से 31 मार्च	44
6.	सुरक्षित शहर	4 से 31 मार्च	30
		कुल	**208**











nidm
Resilient India - Disaster free India

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)
ए-विंग, चौथा तल, एनडीसीसी-II भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
वेबसाइट : www.nidm.gov.in

Design & Print : kam@kamstudio.net